

# The Gazette of India

#### भाषिकार से भ्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₩o 6]

नई विल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1987/माथ 18, 1908

No. 61

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1987/MAGHA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह अक्ष्य संकलन के कप में

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (li)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए संविधिक प्रावेश ग्रीर प्रधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 ग्रगस्त, 1986

श्रायकर

का. आ. 307 :- ज्यायकर श्रीधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदस्त मित्तयों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिनांक 7-1-1986 को अपनी ध्रिधमूनना सं. 6558 की अनुसूची में निम्नलिखित संगोधन करना है। क्रम सं. 13 के सामने कालम 1, 2 और 3 की प्रविध्दियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविध्दियों की नाएंगी :- -

#### म्नन् मुची

क्रम ग्रायकर	मुख्यालय	क्षेवाधिकार
सं. स्राय्क्त		
1 2	3	4
 13 कोचीन	ः कोचीन	<ol> <li>ग्रायकर परिमडल-I ग्रनिकुलम</li> </ol>

- 2. भायकर परिमंडल-II भर्नाकुलम
  - वेतन परिमंडल, भर्ना-कुलम
  - 4 श्रायकर परिमडल, मातनचेरी
  - श्रायकर परिमंडल, श्रालवाई
  - 6. धायकर परिमडल-I त्रिचूर
  - श्रायकर परिमङ्ल-II, त्रिच्
  - श्रायकर परिमंडल, पालघाट
  - श्रायकर परिमडल-I, कालीकट
  - भ्रायकर परिमङ्कल-**H**,
     भालीकट

1	2	3	4	1	2	3	4
	<del></del>	11. भायकर	परिमंडलः			10. Income-tax II, Calicut.	Circle,
		कन्नानोर 	प <b>रिमड</b> ल,			11. Income-tax Cannanore.	Cir <b>c</b> le,
		12. <b>प्रा</b> यकर कसारगोड़	प्रमञ्ज,	,		12. Income-tax Kasargod.	Circle.
		13. निरीक्षी श्रामुक्त,	सहायक निर्घारण,			13. LA.C. (Asstt.), 14. LA.C.(Asst)., T	richur.
		कोचीन				15. Non-resident Cochin.	Circle,
			सहायक (निर्धारण)	This Noti	fication take	effect from 14-8-1986.	~ <del></del>
		धायुक्त न्निचूर 15. गैर द्यावार	,	•	[No	o. 6867 (F. No. 187/10/85 K.K. TRIPATHI, Dy	
		15. गर भावार कोचीन	ता पारमञ्ज,				

# यह ग्रधिसूचना 14-8-1986 से प्रभावी होगी। [सं. 6867 (फा. सं. 187/10/85 -धा.क. नि. I)] के. के. त्रिपाठी, उप संचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 14th August, 1986

#### (INCOME-TAX)

S. O. 307:—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes makes the following amendment to the Schedule to its notification No. 6558 dated 7-1-1986. Entries in column 1, 2 & 3 against serial No. 13 are substituted as under:—

#### SCHEDULE

Sl. No.	Commission of Income Tax	-	uorter, Jurisdiction
l	2	3	.1
13. (	Cochin	Coghin.	1. Income-tay Circle-1. Ernakulam.
			<ol> <li>Income-tax Circle-H Ernakulam.</li> </ol>
			<ol> <li>Salary Circle, Erna- kulam.</li> </ol>
			4. Income-tax Circle Mattancherry.
			<ol> <li>Income-tax Circle Alwaye.</li> </ol>
			6. Income-tax Circle-L Trichur.
			<ol> <li>Income-tax Circle-II. Trichur.</li> </ol>
			<ol> <li>Income-tax Circle, Palghat.</li> </ol>
			<ol> <li>Income-tax Circle-I. Callout.</li> </ol>

# ताणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1987 द्यादेश

का. श्रा. 308—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए रंगलेप तथा संबंध उत्पादों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी निर्यंतण और निरीक्षण के अत्रीन लाने के लिए कित्रथ प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी निर्यंतण और निरीक्षण) नियम, 1964 के निर्यम 11 के उपनियम (2) की अने आनुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अविण मं. का. श्रा. 2656, तारीख 2 अगस्त, 1986 के अवीन भारत के राज्यत भाग-2, खंड-3, उपखंड-(ii), तारीख 26 जुलाई, 1986 में प्रकाशित किए गए थे;

और जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उन व्यक्तियों से उक्त प्रादेश के राजपन्न में प्रकाशित होने की तारीख़ से पैनालोप दिन के भीतर ध्राक्षेप और सुझाव मनि गए थे;

और उक्त राजपन्न की प्रतियां जनता को 11-8-1986 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उका प्राम्प प्रस्ताव पर जनता से जो अक्षेत या मुझाब प्राप्त हुए ये उन पर विचार कर लिया गया है;

श्रतः निर्यात (क्वालिटी नयंत्रण और निरीक्षण) श्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त मनितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद के परामर्श करने के पश्चात श्रानी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात ब्यापार के विकास के लिए ऐसा करना श्रावश्यक और समीचीन हैं:---

- (i) यह श्रक्षियुचित करती है कि रंगलेप तथा संबंध उत्पाद निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के श्रधीन होंगे;
  - (क) सुसंगत भारतीय मानक या अन्य राष्ट्रीय मानको, या निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रन्थ निकासों के मानकों का मान्यता देती है :

- (ii) उत्पादों के परिणिष्ट-I में दी गयी न्यूनतम अभेक्षाओं की पूर्ति करने के प्रधीन रहते हुए संविदात्मक विनिदेशों को रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के लिए मानक विनिदेंगों के रूप में मान्थता देती है।
- (iii) परिणिष्ट-2 में दिए गए रंगलेप तथा सबद्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987 के ध्रनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिदिष्ट करती हैं, जो ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों को उनके निर्यात से पूर्व लागू होगा।
- (iv) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात की प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वा-लिटी नियंत्रण और निरीक्षण) धिधनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अधिकरण द्वारा निर्यात के लिए जारी किया गया इस आंध्रय का प्रमाण-पत्न न हो कि ऐसे रंगलेप तथा सम्बद्ध उत्पादों का मानक विनिर्देशों और अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बक्त क्या से निरीक्षण कर लिया गया है।
- 2. इस आदेश की काई भी वा: भावी श्रेताओं को समुद्र, भूमि बायु, मार्ग द्वारा रंगलेप तथा सम्बद्ध उत्पादों के ऐसे सदभावी व्यापार के नमूनों को लागू नहीं होगी जिनका पीत पर्यन्त निःशुल्क मृत्य 500 रु. से श्रिधक नहीं है।
  - 3. इस अविश में :---
  - (i) "परिणिष्ट" में इसं क्षादेश का परिणिष्ट अभिप्रेत हैं।
  - (ii) "रंगनेप तथा संबद्ध उत्पाद" से इस आदेश की सारणी-1 और सारणी-2 में दी अपी महें अभिनेत हैं।
- यह अत्वेश राज्यल में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होगा।

#### भारणी- 1

- संक्षिण्ट इनेमल ।
- 2. उप्मारोधी वार्निम (वायु गुष्कन बिटुमन प्रकार के)
- मंश्लिष्ट वार्निशा, फिनिशिंग (सामान्य प्रयोजन के लिए) ।
- इमल्यान रंगलेप (प्लास्टिक ऐक्रिलिक इमल्यान) ।

#### सारणी-2

- सभी प्रकार के तैयार मिश्रित रंगलेप तथा इनेमल जिनके अंतर्गत संग्लिष्ट इनेमल के सिनाय प्राइमर, फिलर, अंडर काहिंग तथा फिनिशिंग हैं।
- संक्लिब्ट बार्निण फिनिशिंग (सामान्य प्रयोजन के लिए) तथा उष्मारोधी वार्निण (बायु शुष्कन, बिट्सन

- प्रकार के) के सिवाय सभी प्रकार के वार्निश प्राकृतिक लाख या संश्लिष्ट लाख या दोनों से बनाए गए।
- उ प्लास्टिक तथा ऐफिलिक के सिवाय सभी प्रकार के इमल्सन रंगलेप।
- 4 फिलर, प्राइमर या सरफेसर सिहत, नाइट्रोसेल्युलीस प्रलाक्ष, सादी या वर्णकित।
- 5 पेस्ट रंगलेप तथा पेस्ट हिस्टेम्पर।
- 6 सुखे डिस्टेम्पर, चूने के रंग तथा सीमेंट रंग।
- 7. सीमेंट रंगलेप।
- इ. रंगलेय की पतला करने वाले।
- 9 रंगलेप के लिए संपिलष्ट लाख।
- 10. रंगलेप के लिए संसाधित तेल और रंगलेप के लिए शुष्कन या अर्धशुष्कन तेल।
- 11. विट्रमिनियस कीटिंग।
- 12. एल्युमिनियम पेस्ट ।

#### परिणिष्ट-1

#### न्यूनतम अपेक्षाएं

- 1. सामान्य अपेक्षाएं :
- 1.1 प्रत्येक प्राह्मरी डिब्बे को निम्नलिखित से चिन्हित किया आएगा:--
  - (क) सामग्री का नाम और श्रेणी।
  - (ख) विनिर्माता का नाम और/या व्यापार चिन्ह ।
  - (ग) कारखाना कांड, यदि विनिर्माता की एक से अधिक विनिर्माण एकक हैं।
  - (घ) सामग्री की मान्ना।
  - (इ.) विनिर्माण का बैंच।
- 1.2 पैक में प्राइमरी डिब्बे इस तरह से पैक किए जाएंगें जिससे उनमें धापस में टकराव न हों।
- अडिब्बों की रिसाव परख और सीवन क्षमता की अपेक्षाएं ऐसी होंगी जो विनिर्माता द्वारा श्रिष्ठिकथित की जाएं।
- 1.4 प्रत्ंज डिम्बों (बैरल) या लकडी की पेटियों/ गर्तेदार डिब्बों का जिनमें प्राइमरी डिब्बे पैक किए जाएंगे फिनिया अच्छी होंगी और जोखिम सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे।
- 1.5 फैंकने की पढ़ित उत्पाद की ज्वलनशील प्रकृति डिब्बे की ऊर्ज़ावस्था और अन्य ऐसे सुसंगत पहलुओं के बारे में उठाई-धराई निर्वेश विशेषतः अंतराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत साकेतिक कोड में पैंक के बाहरी और प्रमुख रूप से प्रविधित किए जाएंगें।
  - 2. परीक्षण :
- 2.1 निर्यात के लिए लाट पर निम्न प्रकार परीक्षण लागू होगा:---
  - सारणी-1 की पर्दों के लिए-उपाबंध-(i) से (iv) के प्रनुसार।

सारणी-2 की मदों के लिए संविदास्मक प्रपेक्षाओं के अनुसार।

टिप्पण: सारणी-2 की मदों की दशा में, सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में की विशिष्टताओं के लिए विनिर्देश केता की अपेक्षाओं के अनुसार संविदा में विणित किए जाएंगे।

# उन्मृतालेनाः

3.1 नमूने के रूप में चयन किए जाने वाले डिब्बों की संदर्भ प्रति लाट वह होगी जो नीचे दी गयी हैं:---

नमूना लेने का माप व मान

लॉट श्राकार (डिब्बों की संख्या)	नमूना लेने के लिए चयन किए जाने वाले डिब्बों की संख्या
 50 तक	. 3
51 से 100	4
101 से 200	5 .
201 से 300	6
301 से 400	7
401 से 800	8
801 और उससे अधिक	10

टिप्पण: नमूना लेने के प्रयोधन के लिए "लॉट", डिब्बों के नापों पर ध्यान दिए बिना, विशिष्ट कारखाना कोड वाले किसी विशिष्ट वर्ग के उत्पाद के विनिर्माण का प्रत्येक बैच होगा।

3,2 परीक्षण नमूनों की तैयारी: लॉट से लिए गए प्रत्येक नमूने का भार के लिए, जहां कहीं लागू हो, प्रति दस लीटर श्रलग-अलग परीक्षण किया जाएगा और यदि विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पाया जाता है तो उसी लॉट में से लिए गए अलग-अलग नमूने की सामग्री को एक मिश्रित नमूना बनाने के लिए मिला लिया जाएगा। सभी श्रविशिष्ट विग्रेपताओं के लिए मिश्रित नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।

#### 3 3 परीक्षण की प्रणाली:---

परीक्षण की प्रणाली वह होगी जो निर्यात सविदा में विनिर्दिष्ट है। ऐसे विनिर्दिष्ट श्रनुबंध की श्रनुपस्थिति में परीक्षण की प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के श्रनुसार होगी।

#### उपाबंध---1

संग्लिप्ट इनेमल के लिए परीक्षण :--

#### 1. प्रारम्भिक परीक्षण :---

ताजे खुले डिब्बों में सामग्री लियरिंग, ग्रास्थिरता और ग्रादृढ़ स्थरण वाली नहीं होगी। विलोखित श्रवस्था पर बुण करने के लिए वह एक सार, चिकना और सामग्री उत्पाद बनाएगा। तथापि सामग्री को पतला करने के पश्चात् उसमें गाढ़ा छिड़काव होगा।

#### 2. फिनिश:---

जब पैनल पर विहित रूप में लगाया जाए तब फिनिश चिकनी और चमकदार हांगी, कंकरीलेपन, रंग के अलगाव या अन्य कोई सतही अपूर्णता से मुक्त होगी।

3. पिसाई की सफाई:---

ग्राइंडिंग गेज (हैगमेन) से जब परीक्षित किया जाएगा तब वह कम से कम 6 की रीडिंग देगा।

4. सामग्री नीचे दी गई अपेक्षाओं के भी अनुरूप करेगी ।

कम सं. विशेषताएं	श्रपेक्षाएं
1. (i) गुष्कन समय	
(क) सतह शुष्कन	ग्रधिकतम 8 घंटे
(ख) कठोर <b>गुष्</b> कन	भ्रधिकतम 18 घंटे
(ग) टैक मुक्त भुष्कर	अधिकतम 24 घटे
(ii) रंग	श्रेता द्वारा विनिदिष्ट रूप में (निकटतम मैच) हो
(iii) 30° सें.ग्रे. पर बी-4 फोर्ड कप में स्थानता	<u>⊦</u> 15 सैंकेंड विनिर्दिष्ट
(vi) भार प्रति 10 लीटर	🗓 3 प्रतिशत विनिदिप्ट
(v) प्रज्वलन ताप	30° सें. ग्रे. से कम नही
(vi) <b>ख</b> रोंच कठें।रता परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा
(vii) लचीलापन और श्रासंजन परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा
(vlii) अपखंडन परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा

5. पक्के रंग के लिए परीक्षण :---

तमूनों को परीक्षण पास करना होगा । - (खंड---3 , 3 )

नंदि: यह परीक्षण प्रत्येक परेषण पर करने की अवश्यकता नहीं है। प्रत्येक विनिर्माता सभी निरूपणों के लिए प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार यह परीक्षण करेगा।

#### उपाबंध----2

उष्मारोधी वानिश के लिए परीक्षण (वायु गुष्कन बिदुमन प्रकार के):

#### प्रारम्भिक परीक्षण:---

ताजे खुले डिब्बों में मामग्री गहरे भूरे से काले रग, तरल श्रवस्था में, पपड़ी बनाने से मुक्त, बाह्य पदार्थी और श्रवसाद से मुक्त होगी। विलोड़ित किए जाने पर यह साफ, एकसार और संभागी मिश्रण होगी।

- 2. कॉपर के माथ वानिश की प्रक्रिया:→--
- अब परीक्षण किया जाए तव कॉपरका रंग नहीं बक्षतंगा।
- 3. (क) 5000 व*ोल्ट|*मिलीलीटर (न्यूनतम) कक्ष तापमान पर नायु में विद्युत क्षमता बोल्ट|मि. मी. में होगी।

(ख) पानी	में निमञ्जन	के पण्चात्	विद्युत्	क्षमता	:
----------	-------------	------------	----------	--------	---

सामग्री का 3000 वंगल्ट)मि.मी. (न्यूनतम) पर परीक्षण पास करना होगा ।

 सामग्री नीचे दी गई अपेक्षाओं के भी अनुस्प होगी:---

कम सं.	विश्वपाए	ऋयकाए
•	भार प्रति 10 लीटर 30° में . ग्रे . पर बी-4 फोर्ड क्य में स्थानना	± 15 प्रतिषात विनिदिष्ट ± 15 सैकेंड विनिदिष्ट
(iii)	) णुष्कन समय (क) कठोर शुष्कन (ख) टंक मुक्त शुष्कन	ग्राधिकतम 6 घंटे ग्राधिकतम 24 घंटे
	) प्रज्ञ्ञलन ताप ) रंग	30° सें. ग्रे. से कम नहीं नमूने के प्रनुसार

- (vi) तनुता क्षमता की संगतता 100%
- (vii) अवःष्यणील पदार्थ  $\frac{1}{2}$   $\pm 3\%$  जिनिर्दिष्ट
- (viii) खनिज तेल प्रतिरोध 🔠 परीक्षण पास करना होगा ।

(निकतम मैच हो)

- (ix) उप्ना मह्यता परीक्षण परीक्षण पास करना होगा।
- (x) लचीलापन तथा ग्रासंजन परीक्षण पास करना होगा। परीक्षण

#### उन(बंध---3

संक्ष्यिक वर्गनिया, किनिर्मिया के लिए परीक्षण (मामान्य प्रयोजन के लिए)

- 1. पार्टिशक परीक्षण :—ताजे खुते डिब्बों में सामग्री लिवरिंग या श्रित्थरता के कोई भो चित्ह नहीं दिखाएगी। सामग्री साफ पारदर्शी तथा श्रवसाद और पपड़ी से मुक्त होती। इसके संबदकों को विडोलित किए जाने पर एक सार और समंग्री बतने के लिए तेजी में विखेरा जाएगा।
- थः फिनिशः --जब मामग्री विहित पंतल पर लगाई जाए तब फिनिश चिकती और चमकदार होंगी।
- 3. स(मग्री नीचे दी गयी अपेक्षाओं के भी अनुरुप होगी:----

क्रम सं.	. —   – विशेषत(एं		শ্ব	 स्थाएं	
(1) Ac	 कन का समय				
( क	) सतह गुष्कन		छ: घंटे	( अधिकत	r <b>म</b> )
( 43	r) कठोर शु <sup>ह</sup> कन		18 घंटे	( श्रिधिः	क्तम )
(ग	) मुष्कन	·	2 4 घंटे	(अधिक	तम )

कम सं.	<b>विशेषत</b> ाएं	भवेकाएं
(2)	रंग	नमूने के भ्रनुसार
	0	(निकटतम मैच हं/)
(3)	प्रज्वलन ताप	30 % सें. ग्रे. में कम नहीं
(4)	वाष्पशील पदार्थ %	6 <b>0%प्रधिकत</b> म
(5)	30° सें. ग्रे. पर स्थानता	1=3 स्टोक
(6)	<b>श्रम्लम</b> ान	25.0 ( श्र्राधकतम )
(7)	भारप्रति 10 लीटर	$\pm3$ विनिर्दिष्ट
(8)	क्षार प्रतिरोध	परीक्षण पास करना होगा
(9)	श्रम्ल प्रतिरोध	, परीक्षण पास करना होगा ।
(10)	जल प्रतिरोध	परीक्षण पास करना होगा
(11)	खरोंच कठें।रता परी <b>क्षण</b>	परीक्षण पास करना होगा
(12)	लचीलापन और म्रासंजन परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा
(13)	भ्रपखंडन परीक्षण 	परीक्षण पास करना होगा

#### उपाबंध---4

इमल्यान रंगलेप के लिए परीक्षण ( प्लास्टिकं/ऐक्रिलिक इमल्यान )

- 1. प्रारम्भिक परीक्षण:—नाजे खुले डिब्बों में सामग्री डलों और पपड़ी से मुक्त होगी, अधिक स्थरण केकन, कणिकायन, लिवरिंग या रंग पृथककरण प्रदिश्चित नहीं करेगी और जिक्ती और एकसार अवस्था में निर्लेपन के साथ आसानी से बिबेरी जाएगी। यह घृणोत्पादक रंग से मुक्त होगी। पतला करने के पश्चान् अश या छिड़कान या रोलर द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए गाढ़ापन. चिकना और एकसार होगा।
- 2. शुष्कन ममय :--रंगलेप के स्तह गुष्कन का समय । घंटा (प्रधिकतम ) होगा तथा पुनः विलेपन का समय 4 घंटे (प्रधिकतम) होगा।
- 3. फिनिण :—-जब विहित पैतल पर सामग्री को लगाया जाए तब फिल्म की फिनिण चिकतो हागी और अण्डे की सकेदी जसी चमकदार होगी।
- ्र रंग :— विदेशी केता द्वारा विनिदिष्ट मानक के लिए तिकटनम मैच हो।
- 5. गोला श्रपथर्षण प्रतिरोध :—-रंगलेक किन्म को 4000 दोलन के लिए परीक्षण पास करना होगा।
- 6. भार प्रति 10 लिटर :——िविनिदिष्ट भार प्रति 10 लिटर पर सम्बायता  $\pm$  15 प्रतिणत होगी।
- 7. हल्के से पक्ता :--नमूने को परीक्षण पास करना होगा।
- 8. क्षार प्रतिरोध :----नमूने को परीक्षण पास करना होगा।

[फाइल सं. 6 (5)/85--ई माई एड हे पी]

# MINISTRY OF COMMERCE

#### New Delhi, the 2nd February, 1987

#### ORDER

S.O. 308.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting paints and allied products to quality control and inspection prior to export, were published as required by Sub-rule (2) of Rule 11 of the Export (Quality Coutrol and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 2nd August, 1986, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2656 dated the 2nd August, 1986;

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publication of the said Order in Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 11-8-1986;

And whereas objections or suggestions have been received from the public on the said draft proposals, have been considered.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consultation with the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby:—

- (i) notifies that paints and allied products shall be subject to quality control and inspection prior to export;
  - · (ii) recognises-
    - (a) relevant Indian Standard or any other national standard; or standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;
    - (b) Contractual specifications subject to the product satisfying the minimum requirements as set out in Appendix-I as the standard specifications for paints and allied products.
  - (iii) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of paints and allied products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987 as set out in Appendix-II as the type of inspection which shall be applied to such paints and allied products prior to their export;
  - (iv) prohibits the export of such paints and allied products in the Course of international trade unless the same are accompanied by an inspection certificate for export issued by an Agency established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such paints and allied products have been duly inspected in accordance with the standard specification and requirements of the Act.
- 2. Nothing in this Order shall apply to the export by sea, land or air of bonafide trade samples of paints and allied products not exceeding Rs. 500/- only in free on board value to the prospective.
  - 3. In this Order:-
    - (i) 'Appendix' means an appendix to this order.
    - (ii) 'paints and allied products' means items given in Table-I and II to this order.
- 4. This order shalf come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

#### TABLE-I

- 1. Synthetic enamels.
- 2. Insulating varnishes (Air drying, Bitumen type).
- 3. Syenthetic varnishes, finishing (General purposes)
- 4. Emulsion paints, (Plastic/Acrylic emulsion).

#### TABLE-II

- Ready-mixed paints and enamels of all types including primers, fillers under-coating and finishing except synthetic enamels.
- Varnishes of all types (prepared from natural resin or or synthetic resins or both) except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumen type).
- 3. Emulsion paints of all types except plastic and acrylic.
- Nitrocellulose lacquers, clear or pigmented including filler, primers or surfacers.
- 5. Paste paints and paste distempers.
- 6. Dry distempers, limecolours and cement colours.
- 7. Cement paints.
- 8. Thinners for paints.
- 9. Synthetic resin for paints.
- Processed oils for paints and drying or semidrying oils for paints.
- 11. Bituminous coatings.
- 12. Aluminium paste.

#### APPENDIX-I

#### MINIMUM REQUIREMENTS

#### J. GENERAL REQUIREMENTS

- 1.1 Each primary container shall be marked with the following—
  - (a) Name and description of the material;
  - (b) Name of the manufacturer and/or trade mark;
- (c) Factory code when a manufacturer has more than one manufacturing unit;
- (d) Quantity of the material;
- (c) Batch of manufacture;
- 1.2 The primary containers in a pack shall be so packed as to avoid collisions amongst them.
- 1.3 The requirement of the leakpoorness and scam strength of containers shall be as laid down by the manufacturer.
- 1.4 The bulk consiners (barrels) or the wooden cases or corrugated boxes in which primary containers are packed shall be well finished and strong enough to withstand hazards.
- 1.5 Handling instructions preferably in internationally accepted symbolic codes in respect of method of slinging, inflammable nature of product, vertical position of container and such other relevant aspects shall be predominantly displayed on the outer packs.

#### 2. TESTS

2.1 The tests which shall be applied against a lot for export shall be as below:—

For Table I items-As per Annexure (i) to (iv)

For Table II items-As per contractual requirements.

NOTE:—In the case of Table II items, specifications against the characteristics in the relevant National Standards are to be mentioned in the contract as per buyer's requirements. 

#### 3 SAMPLING

3.1 The number of containers to be selected as samples per lot shall be as given below:

#### SCALE OF SAMPLING

Lot size (Number of co	ntair	ners)	 		Number of con- tainers to be selec- ted for sampling
			 <del></del>	·—·-	
Upto 50				-	3
51 to 100	-				· ન
101 to 200					5
201 to 300					6
301 to 400					7
401 to 800					8
801 and abov	e,				10
		-4	 		

NOTE: A 'lot' for the purpose of sampling shall be each batch of manufacture of the particular class of product bearing the particular factory code irrespective of the container sizes.

- 3.2 Preparation of test samples.—Each sample drawn from a lot shall be individually tested for weight per 10 litres where applicable and if found conforming to the specified standard. The material of individual samples drawn from the same lot shall be blended to make a composite sample. Tests for all remaining characteristics shall be conducted on the composite sample.
- 3.3 Methods of test.—Methods of tests shall be as stipulated in the export contract. In the absence of such specific stipulation methods of tests shall be as per the relevant Indian Standard Specifications.

#### ANNEURE I

#### Tests for Synthetic Enamels

- 1. Preliminary Examination.—The material in a freshly opened containe, shall not show livering, instability and hard settling. On stirring it shall form a uniformm, smooth and homogeneous product suitable for application by brushing. However, after thinning the material shall be of spraying consistency.
- 2. Finish.—When applied on a panel as prescribed, the finish shall be smooth and glossy free from grittings separation of colour or any other surface imperfection.
- 3. Fineness of Grind,—When tested with Grinding gauge (Hegman) it shalf give a minimum reading of 6.
- 4. The material shall also comply with the requirements given below:

Requirements
8 hours maximum
18 hours maximum
24 hours maximum
As specified by buyer (small be a close match)
Specified ±15 seconds
Specified ±3%
Not below 30°C
To pass the test
To pass the test
To pass the test

5. Colour Fastness Test.—The sample shall pass the test (Clause 3.3)

Note: This test need not be done on every consignment.

Each manufacturer shall carry out this test at least once in every six months for each formulation.

#### ANNEXURE II

Tests for Insulating Varnishes (Air Drying, Bitumen Type)

- 1. Preliminary Examination.—The material in a freshly opened container shall be dark brown to blackism in colour, liquid in state, free from skin formation, foreign matter and sediments. On stirring it shall become a smooth, uniform and homogeneous mixture.
- 2. Reaction of varnish with Copper.—The copper shall not change colour when tested.
- 3. (a) Electric strength in volts/mm, in air at room temrerature 5000 volts/mm. (Minimum).
- (b) Electric strength after immersion in water.--The material shall pas the test at 3000 volts/mm. (minimum)
- 4. The material shall also comply with the requirements given below:

SI. Characteristic,	Requirements
(i) Weight pre 10 litre.	Specified ± 5%
(ii) Viscosity in Ford Cup B-1 at 30°C	Specified ± 15 records
(iii) Drying time	
(a) Hard dry	6 hours maximum
(b) Tack free dry	24 hours maximum
(iv) Flash point	Not below 30°C
(v) Colour	As per sample (shall be a close match)
<ul><li>(vi) Compatibility of dilution ability</li></ul>	100 %
(vii) Non-volatile matter %	Specified +3%
(viii) Resistance to mineral orl	To pass the test (Clause 3)
(ix) Thermal endurance test	To pass the test (clause 3)
(x) Flexibility and adhesion test	To pass the test (clause 3)

#### ANNEXURE III

Tests for Synthetic Varnishes Finishing (General purposes)

- 1. Preliminary Examination.—The material in a freshly opened container shall show no sign of livering or instability. The material shall be clear, transparent and free from sediment and skin. On stirring its components shall be rapidly dispersed to be smooth and homogenous.
- 2. Finish.—When the material is applied on a prescribed panel, the finish shall be smooth and glossy.

S. No.	Characteristic	Requirement
(ï) Di	ryingtime	
(a	) Surface dry	6 hours (Maximum)
(t	) Hard dry	18 hours (Maximum)
(c	) Tack free dry	24 hours (Maximum)
(ii) Co	olour	As per sample (shall be a close match)
(iii) Fla	ash point	Not below 30°C
(IV) Vo	latilo matter %	60% maximum
(v) Vi	scosity at 30°C	1-3 stockes
(vi) Ac	id value	25-0 (Maximum)
(vii) W	eight per 10 litres	Specified ±3%
(viii) R	esistance to alkali	To pass the test
(ix) Re	sistance to acid	To pass the test
(x) Re	sistance to water	To pass the test
(xi) Sci	atch: hardness test	To pass the test
(xii) Fl	exibility and adhesion test	To pass the text
(xiii) S	tripping test	To pass the test

#### ANNEXURE IV

Test for Emulsion Paints (Plastic/Acrylic Emulsion)

- 1. Preliminary Examination.—In a freshly opened container, the material shall be free from lumps and skin shall not exhibit excessive settling caking, granulation, hyering or colour separation and shall be easily dispersed with a stirrer to a smooth homogeneous state. It shall be free from offensive colour. The consistency shall be smooth and uniforms suitable for applying by brushing or spraying or by roller after thinning.
- 2. Drying Time.—The paint shall have a surface drying time of 1 hour (Maximum) and recoating time of 4 hours (Maximum).
- 3. Finish.—When the material is applied on a prescribed panel the finish of the film shall be smooth and matter or of egg shell gloss.
- 4. Coldur.—It shalf be a close match to standard specified by the foreign buyer.
- 5. Resistance to wet abrasion.—The paint film shall pass the test for 4000 oscillations.
- 6. Weight per 10 litres.—The tolerance on the specified weight per 10 litres shall be  $\pm\,5\,\%$ 
  - 7. Wastness to light.—The sample shall pass the test.
  - 8. Resistance to alkali.—The sample shall pass the test.

[F. No. 6(5)/85-EL&EP]

- का. थ्रा. 309:---केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण क्वोर निरीक्षण) प्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखिन नियम बनाती है, धर्यात:--
- संक्षिप्त नाम :---- इन नियमों का संक्षिप्त नाम रंग लेप तथा संबद्ध उत्पाद नियति ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम, 1987 है।

- 2. परिभाषाएं :--इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यया अवेक्षित न हो।
  - (क) 'श्रिधिनियम'' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) श्रिधिनियम , 1963 (1963 का केन्द्रीय श्रिधिनियम से 22) अभिष्ठेत हैं;
  - (ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मधाम में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिनेत है।
  - (ग) "रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद" से भ्रभिन्नाय है:---सारणी ---1
  - (1) संभिलष्ट इनेमल
  - (2) ऊष्मारोधी वार्निम (वायु णुष्कित, बिटुमत प्रकार)
  - (3) संक्लिप्ट वार्निश, फिनिशिंग (साधारण प्रयोजन)
  - (4) इम्लागन रंगनेष (प्लास्टिक/एकिलिक इमल्यात ) सारणी---2
  - (1) संश्लिष्ट इनेमलों को छोड़कर सभी प्रकार के तयार मिश्रित रंगलेप तथा इनेमल जिनके अंत-गंत प्राइमर, फिलर, अंडरकोटिंग और फिनिशिंग भी है।
  - (2) संक्ष्लिब्ट वार्तिण फिनिशिंग (साधारण प्रयोजन)
    और ऊष्मारोधी वार्तिणन (वायु गुष्कित, बिटुभन
    प्रकार) को छोड़कर सभी प्रकार की वार्तिण
    प्राकृतिक राल या संक्ष्लिब्ट राल या दोनों से
    तैयार की गई।
  - (3) प्लास्टिक तथा एकिलिक को छोड़कर सभी प्रकार के इम्लगन रंगलेप।
  - (4) नाईट्रोसेल्यूलोज प्रलाक्ष स्वच्छ या रंग मिश्रित हुई जिसमें फिलर, प्राइमर या सरफैसर भी सम्मिलित हैं।
  - (5) पेस्ट रंगलेप तथा पेस्ट डिस्टेम्पर।
  - (6) सूखे डिस्टम्पर, चूर्ण रंग तथा सीमेंट रंग।
  - (7) सीमेंट रंगलेप।
  - (8) (रंगलेप में मिलाने के लिए विरलक।
  - (9) रंगलेप के लिए संक्लिप्ट राज।
  - (10) रंगलेप के लिए संसाधित तेल या रंगलेप के लिए शुष्कत अर्धमा शुष्कत तेल ।
  - (11) बिट्मन लेपिता।
  - (12) एल्यूमिनियम पेस्ट।
  - (घ) "परिषद" में ग्राधिनियम की धारा 3 के ग्राधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिन्नेत हैं:
  - (इ) "अनुसूची" से इन नियमों से संसग्न अनुसूची अभिप्रेन है।

- 3 निरीक्षण का प्राधार:—निर्मात के लिए प्राणित रंगलेंग तथा सम्बद्ध उत्पादों का निरीक्षण इस वृष्टि से किया जाएगा कि रंगलेप तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्मात (क्वालिटी निर्मातण और निरीक्षण) प्रधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय प्रधिनियम से 22) की बारा 6 के प्रधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुक्रम है:—
  - (क) यह सुनिश्चित करके कि उत्पाद अनुत्वी-1 में विनिधिष्य उत्पादन के दौरान शनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिधित किया गया है; ना
  - (ख) श्रनुजुनी-III में जिनिर्दिष्ट रीति से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर।
- 4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के परेषण का निर्यात करने का आध्य रखने याला निर्यातकर्ता, निर्यात-संविद्धा था आदेश की एक प्रति के साथ सीविद्धारमक विनिवेशों का ब्योरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा जितते अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सकें।
- (2) इस प्रयोगन के लिए अभिकरण द्वारा गठित विशेषकों के पैनल द्वारा पर्याप्त संभाधन क्वालिटी नियंद्वण दाले अनुमोदित थिनिर्माण एकक के रंगलेप क्या संबद्ध उत्पादों का निर्यात करने के लिए, निर्यातका उपनिषम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ ग्रह घोषणा भी प्रस्तुत करेगा कि निर्यात के लिए अध्योगत रंगनेप तथा जंगद्ध उत्पादों का परेषण, अनुसूची—में नथा अधिकथिन नव लिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किए गए हैं तों परेषण, इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।
- (3) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना, विनिर्माता के परिपर्य से परेपण के भेजे जाने से कान से कम सात दिन पूर्व ही पाएगी, जबकि उपनियम (2) के प्रधीन घोगणा पहिं सूचना विनिर्माता के परिसर्यों भ परेपण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।
- (4) निर्यातकर्ता अभितृत्रण की, निर्यात किए जाने याले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देशा ।
- (5) उर्तानरण (1) के अधीन सूचना और उपनियम (2) के अधीन घोषणा, यदि कोई हो, के प्राप्त होने पर अधिकरण--
  - (क) तिलिमाण की प्रिक्रिया के दौरान अपना यह लागा-धान हो। जाने पर कि विनिर्माता ने इस प्रयोजना के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देणों के अनु-रूप उपाद का विनिर्माण करने के लिए अनुसूची I में यथा प्रधिक्षिता प्रयोप्त नवालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया है तथा इस संबंध में परिषद/ प्रकिक्शणद्वारा जारी किए भए निवेशों, यदि कोई हों, का पालन किया है, रंगलेप तथा संबंध

- उत्पादों के परेषण के निर्यात के लिए सीन दिन के भीतर निरीक्षण-प्रमाण पत्न जारी कर देगा। जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है, वहां परेषण का यथा आवश्यक सत्यापन तथा निरीक्षण जो श्रापिकरण द्वारी किया जाएगा जिससे यह सुनि-घिचन हो जाए कि उपरोक्त शती का पालन किया गर्ना है । भ्रीत हरण नियमित अंतराली पर युनिट में आएगा और परेपणों में से कुछ परेषणों की, यह सतापित करने के लिए स्थल, पर आंच करेगा कि युनिट द्वारा श्रननाई गयी संताधन क्वालिटी नियंत्रण पर्याप्त है । यदि विनिर्माण युनिट में यह पाना जाता है कि उनमें विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर भ्रपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण को नहीं भ्रमनाता गता या भ्रमिकरण के भ्रधि-कारियों की िफारिणों का पालन नहीं किया मया है तो यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट में संपाधन क्वालिटी नियंत्रण नहीं हैं । ऐसे भामलों में, यूनिट अपनी कमी की दूर करेगा और संज्ञायन वयालिटी नियंत्रण का अनुमोदन प्राप्त करतें के लिए नता श्रावेदन दगा ।
- (ख) ऐसी दशाओं में जितमें निर्यात इसी ने उपनियम 3 (ख) के अधीन निर्यात करने की मांग की है अपना वह मनाधान हो जाने पर कि रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का परेषण, किए गए निरीक्षण। परीक्षण के आधार पर मानक विनिदेशों के अनु- रूप है, निरोक्षण के सात दिन के भीतर रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के परेषण के निर्यात के लिए निरीक्षण प्रमाण-तद्ध जारी करेगा।

परन्तु जहां क्षधिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह विर्यात के लिए ऐसा प्रमाण-गन्न जारी करने से इंशार कर देगा और ऐमे इंशार की सूचना उसके कारणों सहित निर्याक्षित की देगा।

- (6) ऐसी दमा में जहां विनिर्मात्त उपनियम 5(क) के अवीन निर्मात के लिए निर्मातकर्ता नहीं है या परेषण का उपनियम 5(ख) के अवीन निरीक्षण किया जाता है, वहां अभिकरण निरीक्षण की जनाप्ति के तुरन्त पश्चात् पैकेजों को परेषण इस उंग से सील करेगा कि सीलबंद पैकेजों में रहोजदल न की जा सके। परेषण की अध्वीकृति की दशा में यदि निर्मातकर्ता ऐसा चाहता है तो परेषण अभिकरण द्वारा सील वंद नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसे मामलों में, निर्मातकर्ता इस निश्मों में नियम 3 के अधीन कोई भी अपील करने का हकदार नहीं होगा।
- 5. निरीक्षण का स्थान :--इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण:--
  - (क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसरों पर;

- (ख) ऐसे परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ने माल प्रस्तुत किया है, परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।
- 6. निरीक्षण कीस :—इन नियमों के अधीन निरीक्षण फील के रूप में निर्यातकर्ता अभिकरण की प्रत्येक परेषण के पोत-पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ हपए पर एक हपया की दर से फील देशा।
- 7. प्रपील:——(1) नियम (4) के उपनियम (5) के प्रधीन प्रमाण-पत्न देने से अधिकरण द्वारा इंकार किए जाने से अधिकरण द्वारा इंकार किए जाने से अपिकत कोई व्यक्ति, ऐसे इंकार की उसके डारा भूषना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विणेष पेनल को अपिल कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन तथा में अधिक अधिक सात व्यक्ति होंगे।
  - (2) विशेषक्षों के पेनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-परकारी होंगे।
  - (3) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।
  - (4) श्रपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी आएगी।

#### श्रनुसूची-I

# [नियम 3 (क) धेखें]

रंगलेप तथा मंत्रंद्ध उत्पादों का प्रत्येक विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उसने प्रतृसूची—II में दिए गए नियंत्रण स्तरों के साथ नीचे प्रधिकथित उत्पाद के विनिर्माण, परि-रक्षण तथा पैकिंग के विजिन्त प्रक्रमों पर निम्नलिखित निगंद्रणों का प्रयोग किया है।

- 1. कच्ची सामग्री नियंत्रण:
- (क) प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के गुणधर्मों को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा कय-विनिर्देश प्रधिकथित किए जाएंगे।
- (ख) कच्ची सामग्री के स्वीकृत परेषणों के साथ या तो प्रदायकर्मा का परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण-पत्न होगा या कप-विनिर्देशों की श्रपेक्षाओं को समाविष्ट करते हुए निरीक्षण प्रमाण-पत्न होगा। जिस मामले में किसी विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिए केता द्वारा कम से कम 10 परेषणों में से एक की प्रति-आंच की जाएगी या कप की गई सामग्री का केता द्वारा श्रमनी प्रयोगणाला में या प्रयोगणाला/परुष सदन के बाहर श्रधिक्षित कय विनि-देशों से धनुष्पता मुनिचित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा।
- (ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूना लेना श्रमिलिखित अन्वेषणों के भाधार पर विनिर्माता द्वारा श्रधिकथित किया जाएगा।

- (घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पण्चात्, स्वीकृत तथा प्रस्वीकृत सामग्री के पृथक्करण के लिए व्यवस्थित पद्धतियाँ यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाएंगी कि प्रस्वीकृत सामग्री का रंगलप और संबद्ध उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग तो नहीं हो रहा है।
- (इ) पूर्वोक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा नियमित और व्यवस्थित रूप में रखे गए प्रश्नि-लेख वस्तुतः प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त होंगे।

#### 2. प्रक्रिया नियंत्रण :

- (क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं जिनके अंतर्गत कच्ची स.मग्री और मध्यवर्ती उत्पाद, यदि कोई हों, से संबंधित प्रक्रिया भी सम्मिलित हैं के लिए क्यीरेबार प्रक्रिया विनिर्देश विनिर्माता द्वारा कच्ची सामग्री और मध्यमवर्ती उत्पादों के गुणधर्मी सहित ग्रिधिकथित किए जाएंगे।
- (ख) प्रक्रिया विनिर्देश में यथा अधिकथित संस्राधन के नियंत्रण के लिए उपकरण तथा उपस्करों की पर्याप्त मुविधाएं होंगी ।
- (ग) यष्ट्र सत्यापित करने के लिए कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान बस्तुत: प्रयुक्त नियक्षण पर्याप्त था, विनिर्माता द्वारा श्रीचलेख रखे जाएंगे।

#### 3. उत्पाद निस्नयंणः

- (क) प्रधिनियम की धारा 6 के प्रधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के प्रनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण मुविधाएं विद्यमान हों।
- (ख) प्रत्येक बैंच से प्रतिनिधि नमूना लिया जाएमा या।
  प्रयुंज नमूने के दो बराबर परीक्षण नमूनों में
  बांट दिया जाएगा। ऐसा एक परीक्षण नमूना
  दिनिर्माता द्वारा उत्पादों की प्रपक्षाओं के लिए
  परीक्षित किया जाएगा तथा दूसरा नमूना उतकी
  विशिष्टताओं लिहत कम-से-कम छः मास के लिए
  निर्देश नमने के रूप में रखा जाएगा।
- (ग) नमूना लेने और परीक्षण के बारे में ऋभिलेख इस संबंध में बस्तुतः प्रयुक्त तियंवणों की पर्याप्ता का सल्यापन करने के लिए नियसित और व्यव-स्थित कृण में रखे जाएंगे।
- (घ) उत्पाद की आंच करने के लिए नियंत्रण के न्यून-तम स्तर प्रतुसूची-ऑ में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

#### 4. परिरक्षण नियंत्रण:

विनिर्माता द्वारा मध्यवर्ती तथा श्रन्तिम उत्पादों के परिक्षण के लिए श्रीक्षाएं श्रिधिकथित की जाएंगी।

### 5 पैंकिंग नियंत्रण :

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्वेशों के न्यूनतम का समाधान किए जाने की दृष्टि से पैकिंग विनिर्देश प्रधिकथित किए जाएंगे तथा उन्हें कठोरता से कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) नै किंग के संबंध में प्रयुक्त नियंक्षणों के लिए श्रिभिलेख विनिर्माता द्वारा व्यवस्थित तथा नियमित रूप से रखे जाएंगे।

#### ग्रनुसूची-2 ०-ं--- े---

नियंत्रण के स्तर

(क) सारगी-1 में उल्लिखित उत्पादों के लिए

ऋम	सं. श्रपेक्षाएं	संदर्भ	नमूनों की संख्या	श्रावृश्ति
1	2	3	4	5
1.	गावृत्ति	इस प्रयोजन के लिए मात्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
2.	गुष्कन समय	इन प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति वैच
3.	फिनिश	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैंस
4.	प्रते 10 लिटरभार	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
5.	रंग	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
6,	खरोंच कडोरता	इस प्रोजित के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
7.	लचीलापन तथा ग्रासंजन	इस प्रयोजन के लिए मात्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैंध
8.	अंग्रबंडन परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विभिर्देश	एक	प्रति बैच
9.	रंगों का पक्कापन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
10.	ग्रन्त मूर्ट्य	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
11.	प्र <i>ज्</i> वलान तीप	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
12.	क्षःरोयता परीक्षण	इप प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
1 3.	वाष्यगोत पदगर्थ	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
14.	पानो का प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
15.	ग्रम्त का प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्वेश	एकं	प्रति बैच
16.	क्षारीय प्रतिरोध	इय प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	<b>एक</b>	प्रति बैच
17.	पिसाई को सूक्ष्मना	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैंच
18.	स्थानना	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	ए <b>क</b>	प्रति बैच
19.	चनक धारणयो नक	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति धैच
20.	पानी की मान्ना ()	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्वेश	एक	प्रति बैच
21.	आर्द्र अगरवर्णिता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
22.	परावैद्युता क्षमता परीक्षण	इस प्र <sup>थो</sup> जन के लिए मान्यता प्राप्त मानक <b>वि</b> निर्देश	एक	प्रति बैच
23.	काँगा स्तेमन तिगृत रोधनका प्रशि <b>रो</b> ध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति वैच
24.	ताम्र परवानिस की प्रतिकिया	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	<b>ए</b> क	प्रति बैच

# (ख) सारणी-11 में उल्जिखित उत्पादों के लिए:

(i) सभी प्रकार के, तैयार मिश्रित रंगलेपे और इनेमज, तभी प्रकार की संक्लिष्ट वानियों को छोड़कर (फिनिशिंग के लिए संक्लिष्ट वार्शिनयों को छोड़कर) और सह उज्मासहैवानियों (वायु णुष्कित, बिटुमन प्रकार) प्लास्टिक और एकलिक नाइड़ोल्यलोज प्रजाक्षा स्वच्छ या रंग मिश्रित को छोड़कर सभी प्रकार के इमल्यन रंगलय, जिसमें फिलर या प्राइमर ना सरफसर, पेस्ट रंगलपे और पेस्ट डिस्टम्पर भी सम्मिलित है।

ऋमसं.	भ्र <b>ेक्षा</b> एं	संदर्भ	नमूनों की संख्या	भावृति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1. गाव	 ध्रापन	इस प्रयोजा के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2. मुदक	त समय	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विभिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागूहो
3. फिनि	श	इस प्रयोजन के जिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
<b>4.</b> प्रतिति	तंडर/गैतन मार	इत प्रयोजन के तिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागूहो
5. रंग		इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति धैच	णब भी लग् हो
6. खरों <sup>स</sup>	व कठोरता	इत प्रयाजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागृहो
7. लमो	त्तापन तथा श्रासंजन	इस प्रयोजन के जिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
8. सम्ब	मुप्त्र/प्रस्ती ग्रा	इत प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	<b>ए</b> क	प्रति बैच	जब भी लागू हो
9. क्षारत	ता ,	इस प्रयोजन के लिए मात्यता प्राप्त मानक विनिर्वेश	एक	प्रति वैच	जब भी लागू हे
।0. विधुः	त्र अवत्रता	इस प्रयोजन के जिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैंच	जब भी लागूहो
। 1. ब्र <b>ब</b> ग से सं	को दगा में संभारग रक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक । विनिर्देश	एक	प्रति वैच	जब भी लागूहो
12. वाष्ट्र	शीज पदार्थ . •	इस प्रश्रोजन के जिए भान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागूहो
।3. विशा	क्तता <b>परख</b>	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागूहो
14. কাল	प्रभावन	इस प्रयोजन के जिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागूंहों
≀5. तेल व	हा प्रमायं	इस प्र <sup>क</sup> ाजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैंच	जब भी लागू हो
l <b>6. স</b> ত্সক	नन ताप	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागृहें
। <b>७. भ</b> ाच्छ	गदन क्षमता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्वेश	एक	प्रति बैच	जब भी लागूहो
. <b>८. भ</b> न्य	परीञ्चण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त गानक विनिर्देश	एक	प्रति बच	जब भी लागू हो

(ii)	शुष्क	डिस्टैम्पर,	चूर्ण	रंग	तथा	सीमेंट	रंग	
\ /	, O		•					

		<u></u>				
1	· 2	3	4		5	6
1.	शुष्कन का समय (कठोरता तथा पुनः कोटिंग की विशेषताएं)		् मान्येता प्राप्त	एक	प्रति बैच	जब भी लागूहो
2.	फिनिश	इस प्रयोजन के लिए मानक विनिर्देश	ए मान्यता प्राप्त	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	रंग	इस प्रयोजन के जिए मानक विनिर्देश	मान्यत प्राप्त	एक	प्रति बैंच	जब भी लागृहो
4.	प्रकाश में रंग प <del>त</del> वता	इस प्रयोजन के क्षिए मानक विनिर्देश	मान्यता प्राप्त	एक	प्रति भैच	जब भी लागू हो
5.	छलती में श्रवशेष	इस प्रयोजन के लिए मानक विनिर्देश	मान्यता प्राप्त	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
6.	शुष्क रगड़ने पर प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए गानक विनिर्देश	मास्यता प्राप्त	एक	प्रति धैच	जब भी लागू हो
7.	जल विकर्षण क्षमता	इस प्रयोजन के लिए मानक विनिर्देश	मान्यता प्राप्त	एक	प्रति बैंच	जब भी लागू हो
8.	पिश्रित रंगलेप की घट जीवन	इस प्रयोजन के लिए : मानक विनिर्देश	मान्यता प्राप्त	एक	प्रति बीच	जब भी लागू हो
9.	<b>त्रनुर</b> क्षण गुणधर्म	इस प्रशीजन के लिए म विनिर्देश	ान्यता प्राप्त मानक	एक	प्रति वैच	जब भी लागू हो
1 0.	फॅलाव क्षमता	इस प्रयोजन के लिए मा विनिर्देश	न्यता प्राप्त मानक	एक	प्रति बैच	जब भी लागृहो
11.	फैलाब का समय	इस प्रयोजन के लिए मा विनिर्देश	यता प्राप्त भानक	एक	प्रति बैंच	जब भी लागू हो
1 2.	क्षमता .	इप्त प्रयोजन के लिए ग विनिर्देश	रान्यता प्राप्त मानक	र <b>ए</b> क	प्रति बैच	अब भी लागू हो
13.	श्रन्य परीक्षण	इ.ग. ग्रांजिन के लिए मा विनिर्देश	न्यता प्राप्त मानक	एक	प्रति बैंच	जब भी लागू हो

टिप्पणः—सीमेंट रंगलेप, कार्बनिक योजकों से मुक्त होना वाहिए।

# (iii) रंगलेप के लिए विरलक :---

12	3	4	5	6
1. रंग	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	—— <sub></sub> एक	प्रति बैच	 जब भी लागू हो
2. घापेकित घनस्य	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3. भ्रासवन रेंज	इस अयोजन के लिए मान्यता प्राप्त नानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
<ol> <li>वाच्यीकरण पर का प्रविशेष</li> </ol>	ा इस प्रयोजन के किए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
<ol> <li>काउरी बूटानोन भान</li> </ol>	इस प्रयोजन के लिए सान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति वैच	जब भी लागू हो

1	2	3	4	5	6
6.	हाईड्रोकार्बन विचायकों के लिए एनिलिन बिन्दु और मिश्रित एनिलिन बिन्दु	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्वेषा	एक	प्रति बैच	जत्र भी लागूहो
7.	संक्षारक गंधक के लिए परी- क्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
8.	क्लोरीनित हाईड्रोकार्बन विलायक पदार्थी तथा बेंजीन से मुक्ति के लिए परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्वेश	एक	प्रति बैच	जब भी लागूहो
9	ग्रम्ल धुलाई परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
10.	हाइड्रोजन सल्फाईड तथा मिरकैपटैन के लिए परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्या। प्राप्त मानक विनिर्वेश	<b>एक</b>	प्रति बैच	जब भी लागू हो
11.	सीसे मे मृक्ति	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानव विनिर्देश	र एक	प्रति मैच	जब भी लागू हो
12.	प्रज्वलन ताप -	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानः विनिर्वेश	क एक	प्रति वैच.	जब भी लागू हो
13.	विक्रेता तया क्रेताके बीच तय पाया गया विशिष्टि परीक्षण, यदि कोई हो	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्वेण	एक	ं प्रति वैच	ं जब भी लागू हो

# (4) रंगलेप के लिये संक्लिब्ट रेजिन:--

2	3	4	5	6
1. स्थानता	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2. ग्रम्य मान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3. एम. प्वाइंट(गश्वन बिंदु)	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	अब भी लागू हो
4. स्यन्छता	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैध	जब भी लागू हो
5. ग्रन्य परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त <b>मानक</b> विनिर्देश	एक	प्रति भैच	जब भी लागू हो

# (5) रंगलेप के लिए प्रसंस्कृत तेल या रेंगलेप के लिए शुष्कन या ग्रर्धशुष्कन तेलों:—

1 2	3	4	5	6
1. रंग	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विभिन्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2. विशिष्ट गृष्टव (सावनट्य)	इस प्रयोजन के जिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3. भ्रम्तं मान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति वैच	जब भी लागू हो
4. स्वतुरुय नालिका	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
<ol> <li>गलन (या पिडन) सें.ग्रे. बिंदु</li> </ol>	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागृ हो
6. भ्रायोडिन मान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
7. साबुनीकरण मान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
8. घन्य परीक्षण	इस प्रयोजन के लिय मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रित बैच	जब भी लग्गुहो

# (6) बिटुमैनस कोटिंग:---

1 2	3	4	5	6
1. विभिष्ट गृहत्व	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैंज	जंब भी लागू हो
2. कोमलता बिंदु	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्र'ति वैच	जब भी लागू हो
3. वेधन परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक ,	प्रति वैच	जय भी लागू हो
4. छीलन परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यज्ञा प्राप्त मानक विनिर्देश	गृक <u>ः</u>	प्रति वैध	जब भी लागू हो
5. श्रापात प्रबस्ती	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्वेश	ग् <b>क</b>	प्रति बैच	जब भी लागू हो
6. द्यानमन परीक्षण	इन प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैंच	जब भी लागू हो
7. भस्म अंग	इ.स. प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति वैच	जब भी लागू हो
8. ऋत्य परीक्षण	इप प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो

	(7) एल्युमिनियम पेस्ट	1			
1	2	3	4	5	6
1.	एल्युमियनम चूर्ण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	वर्भान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक .    विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	छानने पर श्रवगेष ( 150 माङ्कोन, 75 माङ्कोत, 53 माङ्कोन भा∘मा . छत्रनी)	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	<b>एक</b>	प्रसि बैच	जब भी लागू हो
4.	चिकनाई अंश	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागुहो
5.	फिनिश	इस प्रयोजन के लिये म <i>्य</i> ता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति धैच	जद भी लागू हो
6.	स्थिरण विणिष्डताल्	इप प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति वैच	जब भी लागू हो
7.	वाष्प्रशील पदार्थ	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रशि बैच	जब भी लागृहो
8.	कीर्षिण गुणबर्म	द्म प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक ्विनिर्देश	एक	प्रति <b>बैच</b>	जब भी तागू हो
9.	कुल श्राद्वज्य जितके अस्तर्गत सावा और सीसा है	इस प्रकोजन हे हिन्ने मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैंच	जब भी लागू हो
10.	भ्रन्य परीक्षण	इम प्रयोजन के लिये भाष्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति भैच	जब भी लागृहो

# अनुसूची-3

# [नित्रम 3 (ख) देखिए]

- 1.1 रंगनेय और तंबद्ध उत्पादों का परेषण, अधितियम की घारा 6 के अधित मान्यताप्राप्य मानक वितिर्देशों से उतकी अनुरूपता सुनिध्वित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण के अधीन होगा ।
- 1.2 अत्र तक कि संधिदात्मक चितिर्देशों, में धन्यथा उल्लिखिन न हो, नभूनः मापदंड और लिए जाने कले नमूनां की संख्या अधिनियन की धारा 6 के अधीन अधिसूचित न्युनतम अपेक्षाओं के अनुसार होगी ।
- 1.3 एक लोट ने लिए गए प्रत्योह नमूने का नार प्रति 10 लिटर के लिए, जहां भी लागू हो, प्रलग-प्रलग परीक्षण किया जाएगा। यदि वे विनिर्विष्ट मानकों है अनुरूप पाए जाते हैं तो उपी लाट से लिए गए प्रलग-प्रलग नमूनों को एक तम्भिला गमूना बनाने के लिए एक प्राथ संमिधिन किया जाएगा। नव उसे दो एक गमान परीक्षण नमूनों में विभाजित किया जाएगा। ऐसे एक परीक्षण नमूने का मंगन विधिष्टिताओं के लिए परीक्षण किया जाएगा और दूसरे को कम से कम छः मास के लिए उनकी विधिष्टिओं सहित निर्वेश नम्ने के रूप में एखा जाएगा।

1.4 यदि निर्यात संविद्या में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो परीक्षण की पद्धति मुक्तित पारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार होगी ।

> [फा. नं. 6(5)/85-ई. श्राई. एंड ई. मी.] एन. एस. हिन्हरन, निदेशक

- SO. 309.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government mereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title.—These rules may be called the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—
  - (a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963);
  - (b) "Agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras;
  - (c) "paints and allied products" means

#### TABLE-I

- (i) Synthetic enamels
- (ii) Insulating varaishes (Air drying, Bitumen type)

(iii) Synthetic varnishes, finishing (General purposes)

(iv) Emulsion paints (Plastic/Acrylic emulsion)

#### TABLE-II

- Ready-mixed paints and enamals of all types including primers, fillers, under-coating and finishing except synthetic enamels,
- (ii) Varnishes of all type (prepared from natural resin or synthetic resins or both) except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumen type).
- (iii) Emulsion paints of all types except elastic and acrylic
- (iv) Nitrocellulose lacquers, clear or pigmenred including fillers, primers or surfaces,
- (v) Paste paints and paste distempers
- (vi) Dry distempers, lime colours and cement colours.
- (vii) Cement paints
- (viii) Thinners for paints
- (ix) Synthetic resin for paints
- (x) Processed oils for paints and drying or semidrying oils for paints.
- (xi) Bituminous coatings
- (xii) Aluminium paste
- (d) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;
- (e) "Schedules" means Schedules appended to these rules.
- 3. Basis of Inspection.—Inspection of paints and allied products for export shall be carried out with a view to seeing that the paints and allied products conform to the standard specifications recognished by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963)-
  - (a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary in-process quality control as specified in Schedule-I;

#### OR

- (b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Schedule-III.
- 4. Procedure of Inspection,—(1) An exporter intending to export a consignment of paints and allied products shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications alongwith a copy of the export contract or order to enable the Agency to carry out inspection in accordance with rule 3.
- (2) For export of paints and allied products of a manufacturing unit approved as having adequate in process quality control by the panel of exports constituted by the Agency for this purposes. The exporter shall also submit alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of paints and allied products intended for export has been manufactured by exercising quality control as laid down in Schedule-I and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.
- (3) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises while the intimation alongwith the declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.
- (4) The exporter shall furnish to the Agency the identification marks applied on the consignment to be exported
- (5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the de luration, if any, under sub-rule (2), the agency
  - (a) On satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer has exercised adequate quality control as laid down in Schedule-I to manu-1502 GI/86—3.

- facture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose and the manufacturer had followed the instructions, if any, issued by the Council/Agency in this regard, shall within three days issue an inspection certificate for export of the consignment of paints and allied products. In case where the manufacturer is not the exporter, such verification and inspection of consignment as necessary shall be carried out by the agency as to ensure that the above conditions have been complied with. The agency shall visit units at regular intervals and conduct and check on some of the consignments. conduct spot check on some of the consignments to verify the adequacy of in-process quality control adopted by the unit. If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures or recommendations of the officers of the Agency at any stage of manufacture the unit shall he declared as not having adequate in-process quality control. In such cases, the unit shall rectify deficiencies and apply afresh for the approval of in-process quality control.
- (b) In case where the exporter has sought export under sub-rule 3(b), on satisfying itself that the consignment of paints and allied products conform to the standard specifications, on the basis of inspection/ testing carried out shall within seven days of inspection issue an inspection certificate for export of the consignment of paints and allied products;

Provided that where the agency is not so satisfied it shall refuse to issue a certificate of inspection for export and shall communicate such refusal to the exporter within the said seven days alongwith the reasons therefor.

- (6) In case where the manufacturer is not the exporter for export under sub-rule 5(a) or the consignment is inspected under sub-rule 5(b), the Agency shall immediately after completion of the inspection seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency, but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal under rule 8 of these rules.
- 5. Place of Inspection,—Every inspection under these rules shall be carried out either—
  - (a) at the premises of the manufacturer of such products;

OF

- (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for inspection and testing exist therein.
- 6. Inspection Fee.—A fee at the rate of one rupce for every one hundred rupees of FOB value of each consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee under these rules.
- 7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government;
- (2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials;
  - (3) The quorum for the panel of experts shall be three.
- (4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

#### SCHEDULE-I

#### [See under rule 3(a)]

Every manufacturer of paints and allied products shall be ensured by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the product as laid down below together with the levels of control as set out in the Schedule-II.

#### (i) Raw material Control:

- (a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.
- (b) The accepted consignments of raw materials shall either be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications in which case counter checks shall be conducted atleast once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier or the purchased materials shall be regularly tested and inspected by the purchaser in own laboratory or in an outside laboratory/test house to ensure conformity with the laid down purchase specifications
- (c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be laid down by the manufacturer based on the recorded investigations.
- (d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials to ensure that the rejected materials are not used in the manufacture of paints and allied products.
- (e) Records in respect of the aforesaid controls regularly and systematically maintained by the manufacturer shall be adequate to verify the control actually exercised.

#### (ii) Process Control:

- (a) Detailed process specification for different processes of manufacture including those for raw materials and intermediate products, if any, shall be laid down by the manufacturer alongwith the properties of raw materials and intermediate products.
- (b) Fourpment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Records shall be maintained by the manufacturer to verify that the controls actually exercised during the process of manufacturer are adequate.

#### (iii) Product Control:

- (a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to the standard specification recognised under Section 6 of the Act.
- (b) A representative sample shall be drawn from each batch. The bulk sample shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested by the manufacturer for the requirements of the products and the other preserved as referee samples alongwith its particulars for atleast six months.
- (c) Records in respect of sampling and tests shall be regularly and systematically maintained to verify the adequacy of the controls in this regard actually exercised.
- (d) The minimum levels of control to check the product shall be as specified in Schedule-II.
- (iv) Preservation Control.—The requirements for preservation of intermediary final products shall be laid down by the manufacturer.

#### (v) Packing Control:

- (a) A packing specification shall be laid down with a view to satisfying minimum of the standard specifications recognised under section 6 of the Act and shall be rigidly implemented.
- (b) Records in respect of the controls exercised in respect of packing shall be maintained by the manufacturer regularly and systematically.

#### SCHEDULE—II

#### LEVELS OF CONTROL

#### (a) For products mentioned in Table-I

S.	Requirement		-,· —	 	~				Reference	No. of samples	Frequency
(1)	(2)		-	 				-	(3)	(4)	(5)
1.	Consistency .				,	-	•		Standard specifications recognised for the pusrpose	One	Per batch
2.	Drying time .		-					-	71	"	**
3.	Finish					• '			**	**	**
4.	Weight per 10 litres								17	11	,,
5.	Colour , .							-	11	**	**
6.	Scarich hardness								19	**	",
7.	Flexibility & adhesio	'n							*1	,,	17
8.	Stripping test								D	11	1)
9.	Colour fostness		,						**	11	**
10.	Acid value								11	••	**
11,	Flash Point								**	,,	21
12.	Alkalinity test .								11	,,	•
13.	Volatile matter				,				**	•	,,
14.		,							,,	,,	,,
15.	Resistance to acid					,			11	*1	**
16.	Resistance to alkali		-	•				-	*1	7,	**

1	2							3	4	5
17.	Fineness of grind									
18.	Viscosity .						•	"	>,	,,
19.	Gloss retention			•				11	- ,,	,,
20.	Water content(%)					• '		12	***	,,
21.	Wet opacity .				-			,	,,	**
22.	Di-electric strength	test						,,	,,	<b>)</b> 1
23.	Resistance to coil er	ame	l insu	lation				**	,,	**
24.	Reaction of varnish	with	capp	cr				11	11	**

(b) For products mentioned in Table-II

(i) Ready mixed paints and enamels of all types except synthetic varnishes of all types (except synthetic varnishes for finishing) and insulating var-

nishes (air drying, bitumen type), emulsion paints of all types except plastic and acrylic nitrocellulose lacquers, clear or pigmented including fillers, primers or surfacers, paste paint and paste distempers.

S. No.	Requirement							Reference	No. of sample	Frequency	Remark
(1)	(2)		-					(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Consistency	•		•	•			Standard speci- fications recog- nised for the purpose	One	per batch	Wheney e ap plicabl
2.	Drying time							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1,	,,	,,
3.	Finish							11	,,	,,	"
4.	Weight per litre/gallon							17	,,	.,	21
5.	Colour							**	31	,,	21
6.	Scratch hardness .							,,	,,	,,	**
7.	Flexibility and adhesion							,,	,,	,,	**
8.	Acid value/acidity .					٠.		17	13	"	.,
9.	Alkalinity							**	.,		•
10.	Electric strength .							,,	"	***	"
11.	Protection against corres	ion u	ider co	nditi	ons of	cond	en-	,,	1)	**	"
	sation							,,	,,		
12.	Volatile matter							,,	"	,,	1,
13.	Toxicant availability test					,		"	,,	"	2,
14.	Ageing							,,	"		11
15.	Effect of oil							"		1)	"
16.	Flash point							,,	,,	,,	"
17.	Covering capacity .							,,		,,	**
	Other tests.					•		" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,, 	···	21 22

(ii) Dry distempers, lime colours and cement colours

(1)	(2)				_			(3)	(4)	(5)	——————————————————————————————————————
1.	Drying time (hardening an	nd reco	oatin;	g prop	erties		•	Standard specifi- cations recogni- sed for the purpose	One	Per batch	Whenever ap plicable
2.	Finish			•				17	**	72	**
3.	Colour		•	-			•	1)	,,	*,	**
4.	Fastness to light .	٠.		. •				**	,,	1)	"
5.	Residue on sieve .		-	-				,,	,,	"	
6.	Resistance to dry rubbing							,,,	,,	"	**
7.	Water repellancy .							,,	.,		**
8.	Pot life of mixed paint								"	**	,,
9.	Keeping properties .			_				,,		"	"
10.	Spreading capacity		_				·		11	<b>"</b> .	**
11.	Spreading time				•	•	·	,,	**	**	27
12.	Capacity	•	•	-	•	•	•	"	"	21	**
13.		•	•	•	•	•	•	,,	17	,,	**
1.3.	Other tests	•	•	•	•	•	•	37	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**	,,

Note: Cement paint shall be free from organic binders.

(1)					
(1) (2)		(3)	(4)	(5)	(6
1. Colour		Standard specifica tions receg- nised for the	One	Per batch	Whenev applica
2. Relative density		purpose			
3. Distillation Range		<b>&gt;&gt;</b>	,,	**	**
4. Residue on evaporation		"	**	**	,,,
5. K auri Butanol value	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	"	<b>**</b> ***	27
6. Aniline point and mixed aniline point for l	hydrocarbon-			***	<b>"</b>
7. Test for corrosive sulphur	•	**	**	37	,,
8. Test for freedom from chlorinated hydrocard solvents and benzene	oon	"	7,	,,	
9. Acid wash test	•	<b>&gt;&gt;</b>	,,	,,,	,,
10. Test for hydrogen sulphide and mercapatans	•	95	**	**	**
1. Freedom from lead .		39	,,	99	22
2. Flash point		<b>55</b>	,,,	, i	,,
3. Specific test, if any, as agreed between buyer	and seller	, <b>),</b>		***	. ,,
			**	**	**
iv) Synthetic resin for paints					
) (2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1. Viscosity	C	andard specifi- ations recog- ised for the	One	per batch	Whenever applicable
		purpose			
. Acid value		,,	,,		
M. Pt		,,,	,,	***	99
. Clarity		,,	,,	"	.,,
Other tests.	• • •	39	,,	••	"
Processed oils for paints and drying or semi-drying	ng oils for pain	<b>ts</b>			
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Colour	ca	ndard specifi- tions recog- ted for the	One	per bath	Whenever applicable
	pu	rpose			
Sp. Gr. (or density)		,,	**	"	99
Acid value		,,	,,	**	,,
Melting (or solidification) Point °C	•	<b>,,</b>	**	**	,,
[odine value		<b>&gt;</b> >	22	25	**
Saponsification value		,,,	,, ,,	"	,,
Other tests		22	"	"	)) ))
Bituminous caotings					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Specific gravity		ard specifica-	One	Per batch	Whenever
		s recog- d for the			applicable
Softening point		••	29	99	en e
Penetration test		,,	"	,,	,,,
Peel test		,,	**	,,	**
Impact strength		19	,,	,,	,, ,,
Sag test		,,	99.	,,	,,
Ash content		,,	,,	,,	
Other tests	of the second second				**

(vii) Aluminium paste	9	
-----------------------	---	--

,	- Addinanium paste		_									
(1)	(2)						_		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aluminium powder	•	•	•	-	٠	-		Standard specifi- cations recog- nised for the purpose	Onc	per batch	whenever applicable
2.	Leafing value .					-	-		**	,,	",	,,
3.	Residue on sieve (15	0 mic	ron, 7	/5 mic	on, 53	mici	ron					.,
	1.S. Sieves) .		•	-		٠	-	•	**	**	**	19
4.	Grease content	•		•					"	**	,,	12
5.	Finish								,,,	*11	17	
6.	Settling properties								,,	22	1)	**
7.	Volatile matter								**	,,	1)	**
8.	Keeping properties								**	**		**
9.	Total impurities incl	uding	coppe	er and	l lead				**	11	1,	**
10.	Other tests									•	"	**
10.	Onici tests				•	•			—	**	**	

#### SCHEDULE-III

#### [See under rule 3(b)]

- 1.1 The consignment of paints and allied products shall be subject to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.
- 1.2 Unless otherwise mentioned in the contractual specifications, the sampling criteria and the number of samples to be drawn shall be as per the minimum requirements notified under section 6 of the Act.
- 1.3 Each sample drawn from a lot shall be individually tested for weight per 10 litre where applicable. If they are found to be conforming to the specified standard individual samples drawn from the same lot shall be blended together to make composite sample and then shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested for the relevant characteristics and the other preserved as referee sample along with its particulars for atleast six months.
- 1.4 If not otherwise specified in the export contract, methods of testing shall be as per relevant Indian Standards Specifications.

[F. No. 6(5)/85-EI&EP] N. S. HARIHARAN, Director

# पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महालय

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1987

का. श्रा. 310: — यतः केन्द्रीय सर्रकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह श्रावण्यक है कि गुजरात राज्य में बी. एल.एच. जे. से बलोल जी. जी. एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैंस श्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूचि में विणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवण्यक है।

श्रतः श्रब पेट्रोलियम और खानिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का श्रजंन) श्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का श्रपना श्राशय एतदद्वारा घोषित किया है।

बगर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए ग्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैंस ग्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बढ़ौदा-9 को इस ग्रिधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा म्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिद्धिटतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनव ई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

# अनुसूची

बी. एल. एच. जे. से बलाल जी. जी. एस.तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला :	मेहसाना तः	लुक:मे	हसाना
गौंव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	म्रार.	— — सेन्टीयर
मीठा	430	0	07	32
	429/1	0	08	64
	429/2			
	429/3	0	07	26
	429/4			
	428	0	17	16
	426	0	03	48
	425/1	0	19	68
	400/2	0	03	36
	400/1	0	07	32
	400/3	0	11	16
	399	0	01	32

[सं. ओ-12016/4/87-ओ एन जी-डी-4]

#### MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 20th January, 1987

S.O. 310.—Whereas it appear to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from BLHJ to BALOL G.G.S. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :-

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroluem and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

**SCHEDULE** Pipeline from BLHI to BALOL G.G.S.

State: Gujarat	District: Mehsana	Taluks	: Me	haana
Village	Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are
1		3		
Mitha		0	07	32
	4 <b>29</b> /1	0	08	64
	429/2			
	429/3	0	07	26
	429/4			
	428	0	. 17	16
	426	0	03	48
	425/1	0	19	68
	400/2	0	03	36
	400/1	0	07	32
	400/3	0	11	16
	399	0	01	32
	INO. O 12	2016/4/87	$0.\overline{N}$	G.D-4]

का आ. 311:---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह स्रायण्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. बी. एफ. से (वाय। एस. एन. क.) एस. पेट्रोलियम के परिवहन के लिये एस. सी.टी. एक. तक पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस भ्रायोग द्वारा विछाई जानी च। हिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद प्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना भावश्यक है।

ग्रतः भ्रब पेटोलियम और खनिज पाइपलाइन (भृमि में उपयोग के श्रधिकार का भर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिनतयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का भिधिकार भजित करने का अपना भ्राशय एतदद्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए श्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा पाकृतिक गैस ग्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपूरा रोड, बड़ौदरा-9 को इस ग्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

#### ग्रन् सूची

एस. एन. बी. एफ. से (वाया एस. एन. के.) एस. एस. सी. टी. एफ. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

तालुका: मेहसाना राज्य : गुजरात जिला: मेहसाना

- गाँव	सर्वे नं.	 हेक्टेयर	घारे.	— सेन्टीयर
1	2	3	4	5
	940	0	03	60
_	कार्ट ट्रैक	0	01	20
	827	. 0	10	44
	826	0	08	88
	831	0	01	44
	832	0	03	00

[स. ऑ-12016/3/87-ऑ. एन. जो. डी-4]

S.O. 311.-Whereas it appear to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum SNBF to (Via SNK) S.S. CTF i.e. N.E.S.S.C.T.F. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed thereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government teacher in the conference of hereby declares its intention to acquire the light of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner,

SCHEDULE

Pipeline from SNBF to (Via SNK) S.S. CTF i.e. N.E. S.S.CTF.

State: Gujarat District: Mehsana Taluka: Mehsana

Village	Survey No. H	ectare	Arc	tiare
1	2	3	4	5
Kasalpura	940	0	03	60
	Cart Track	0	01	20
	827	0	10	44
	826	0	08	88
	831	0	01	41
i	832	0	03	00

[No. O-12016/3/87-O.N.G. D-4]

का. श्रा. 312:—यनः पैट्टोलियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के श्रधिकार का श्रर्जन) श्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के श्रधीन भारत सरकार के पैट्टोलियम और प्राकृतिय गैस मंत्रालय की श्रधिसूचना का. श्रा. सं. 2766 तारीख 23-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस श्रधिसूचना से संलग्न श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के श्रधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए श्रजित करने का अपना श्राणय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त ग्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के ग्रिधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है।

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस श्रधिसूचना में संलग्न श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिया में उपयोग का श्रधिकार श्रजित करने का विनिश्चय किया है।

श्रव, श्रतः उक्त श्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्न शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत-द्वारा घोषिन करती है कि इस श्रिधसूचना में संलग्न श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रिधकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा श्रीजन किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) हारा प्रदत्न गिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राष्ट्रितिक गैस धायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### श्चनुसूची

एस.बी. डी. जे. से शोशभसन सी. टी. एफ. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य---गुजरात, जिला--मेहसाना, ता.--मेहसाना

_
सें.
-
24
36

[सं. O-12016 / 110 / 86-ओ एन जी-डी- 4] पो० के० राजगोपालन, डैंग्व अधिकारी

S.O. 312.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2766 dated 23-7-866 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral, Pipeiines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declored its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government; And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the pulication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission from encumbrances.

# SCHEDULE Pipeline from SBDJ to SOB. CTF

State : Gejarat	Di triet &	Taluka	: M5	h-ara
Village	Block No.	Heetare	Arc	Cen- tiare
1	2	₹	•	1
H- buva	102	0	01	24
	104	0	06	36

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

# रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्र)

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1987

का०आ० 313:—भारतीय रेलवे प्रधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम 9) की धारा 82वी द्वारा प्रदत्त गिवनयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री भिखारी राम, ध्रपर जिला एवं सेशन्स न्यायाधीण, पालामउ को 6-8-1986 को गड़वा रोड और तोलडा म्टेशन के बीच 162-डाउन, अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस की हुए दुर्घटना में उत्पत्त सभी दावों को निपटाने के लिए तदर्थ दाया आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय डाल्टनगंज में होगा।

[सं. 86/ई (अो) 🌃 /1/3]

#### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 21st January, 1987

S.O. 313.—In exercise of the powers conferred by section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shi Bhikari Rana Addl, District and Sessions Judge, Palamad as Ad hoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of accident of 162 DN, Amritsar-Tata Express on 6-8-1986 between Garwa Road and Tolra Station. His Headquarters will be at Daltonganj.

का अविश्वास १) की धारा 82 बी द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री गोपीनाथ चन्द्रा श्रपर जिला न्यादाधीण, धनबाद की 21-7-86 को गोमों में हुई 28 अप मौर्य एक्सप्रेम की दुर्घटना से उत्पन सभी दावों को निपटाने के लिए तदर्थ श्राधार पर दावा श्रायुक्त के रूप में नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय धनबाद में होगा। [सं. 86 /ई (ओ) II / 1(3)] एस. एम. वैश, सचिव (रेलवे बोर्ड)

S.O. 314.—In exercise of the powers conferred by section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri Gopinath Chandra, Addi. District Judge. Dhanbad as Adhoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of accident of 28 UP Maurya Express at Gomah on 21-7-1986. His Headquarters will be at Dhanbad.

[No. 86/E(O)II/173] S. M. VAISH, Secy., Railway Board,

#### संचार मंत्रालय

(दूरमंचार विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1987

का. आ. 315:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसार विभाग ने अनपींत टैलीफोन केन्द्र, करणाटका सकिल, में दिनांक 7-2-1987 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-8/87-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications)
New Delhi, the 22nd January, 1987

S.O. 315.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 7-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Anaparthy Telephone Exchange, Andhra Pradesh Telecom. Circle.

[No. 5-8-/87-PHB]

#### नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1987

का. आ. 316:—स्थायी अदिश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 हारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुभार महानिदेशका, दूरमंचार विभाग ने नियम टैलीफान केन्द्र, काटिक पिकल, में दिनांक 7-2-1987 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-7/87-पी एच बी] के.पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.) New Delhi, the 27th January, 1987

<u>-\_.</u> ,-\_.

S.O. 316.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 7-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sindhanoor Telecom. Circle.

[No 5-7|87-PHB]

K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB)

#### श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1987

का. आ. 317:—मैं भर्म सी.जे. पटेल तम्बाकू प्रोड्क्टम प्रा. लि., एम.जी. रोड, सागर (मध्य प्रदेण) (एम.पी./2814) (जिथे इसमें इसके पश्चाल् उक्त स्थापन कहा भया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण धपबन्ध प्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) (की धारा 17 की उपधारा 2क) के ग्रधीन छूट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रामिया या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा के रूप में सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ग्रधिक ग्रनुकूल नहीं है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रधीन उन्हें ग्रनुजेय हैं।

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधितियम की धारा 17 की उनधारा-2क द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए और धमने उनाबड़ अनुमूची में विनिदिष्ट धार्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती हैं।

#### **ग्र**नुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक निवध्य निधि अध्यक्त, मध्य प्रदेश की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेना नथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जी केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निदिष्ट करे।
- 2. नियंजिक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की नमाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेंगा को केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनिषम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रजीन समय पर सिदिष्ट करे।
- 3. प्रामृहिक बीमा स्कीम के प्रणापन में, जिसके धन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का धन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादिभी है, हो बाले सभी व्ययों का बहुत नियंति हारा किया जायेगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमोदित कामूहिक बीमा स्कीम के नियमां की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का अनुवाद स्थापन के भूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी मिविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उत्तका नाम पुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम् भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोक्षक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की ध्यवस्था करेगा किससे कि कर्म-चारियों के लिए नामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध के फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रों हैं।
- 7. संभूहिक वीभा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेग रकम उस रकम से कम है जो कर्मवारी का उम दण में संदेग होती जब वह उदा स्कीम के प्रयोग होता तो, नियोगक कर्मवारी के विधिक वारिस/नामनिर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रन्तर के वरावर रकम का संदाय करेगा।
- 8. तत्म्हित बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रादेशिक विविध सिधि प्रायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया आयेगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त प्रभान प्रमुखन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपत्ना ट्रिटकोण स्पष्ट करों का युक्तियुक्त प्रवार देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिमे स्थापन पहले श्रयना चुका है श्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रहे की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमिथम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजिक द्वारा प्रीपियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दथा में उन मृत नदस्यों के नाम निर्देगिति हैं। विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी। 1502 GI/86—4.

गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के श्रधीन शाने वाले किसी अदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक भास के भीतर सुनिष्चित करेगा।

[एस-35014(280)/86-एस.एस-2] MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th January, 1987

S.O. 317.—Whereas Messrs C. J. Patel Tobacco Products Private Limited, M.G. Road, Sagar (Madhya Pradesh) (M.P.| 2814) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provided Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And there is the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estalishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a cory of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees,
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Privident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary remium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under his Scheme are reduced in any maner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assued to the nominee/legal heirs of the decease. I member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

  [No. S-35014/280/86-SS-II]

का • आ. 218:— मैंसर्स महेर सिमेन्ट, पोस्ट आफिस-सरलानगर—485772, महेर जिला—सतना (मध्य प्रदेश) (एम.पी./4767) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उनत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अविषय निधि और प्रकीणें उप-बन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उनत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अबीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय भरकार का नमाधान हो गया है कि उक्त रथापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की भागूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं।

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त मिनतयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भती के श्रधीन रहने हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है।

#### **भ्रन्**स्ची

 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, मध्य प्रदेण को ऐसी विवरणियां भेजेगा और

- ऐसे लेखा रचेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समयार निहिष्ट करे।
- 2. निर्वोज स, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उनत श्राधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-कं खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके ग्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रमारों संदाय ग्रादि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहन नियंगक हारा दिया जायगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा म्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिश्त करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मणारी जो कर्मणारी भविष्य निधि का या उपत प्रिधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की गविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त धर्ण करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फाउदे बढ़ायें जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय है।
- 7. सामूहिक वीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रक्षम उस रक्षम से कन है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के ग्रन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त प्रथना प्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है प्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख़ के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में भासकल रहता है और पालिसी को व्ययगत हा जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के संस्वन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्यार नाम निर्देशितयों/विधिक वारिसों की बीमाइत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस-35014(281)/86-एत.एस.-2]

S.O. 318.—Whereas Messrs Maihar Cement, P.O. Sarla Nagar-485772, Maihar, Distt. Satna (Madhya Pradesh) (MP) 4767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estalishment from the o eration of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Machya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges Tas the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Limployees' Provident Fund or the Privident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme;
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the anyount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under his Scheme are reduced in any maner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased mentiers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assued to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

[No. S-35014(281)|86-SS-JI]

का० धा० 319.—मैं सर्स एम० पी० स्टेट को-ओ० हाऊ सिंग फेंडरेशन लि०, सहआर अवन, नोरण टी० टी० नगर, भोपाल (एम० पी०/3321) (िस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमंत्रारी भविष्य निधि और प्रकीण अपबन्ध ध्रिधिनियम, 1952 का 17 (िजसे इसमें इसके पश्चात् अक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा एक अधीन छट दिये जाने के लिए ध्राविदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक ग्रिक्टिय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं।

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में विनिर्दिष्ट शतौं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### **प्रनुसूची**

- 1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक अविष्य निधि श्रायुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय धादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुसोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन की प्रति तथा कर्म- चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियी-जित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी ग्रावह ग्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदा में समुचित रूप से बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमां स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुकूष हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन पंदेन रकम उस रकन से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता ती, नियोजक कर्मचारी के बिधिक वारिग/नाम निर्वेषिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमां के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीय के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भिविष्य निधि श्रायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व श्रुनुमोदन के जिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भिविष्य निधि श्रायुक्त श्रमात प्रतुमादन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रयंभर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुना है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, ता यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संबाय करने में श्रसफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गर्य किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों संदाय का उत्तरसायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उकत स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के भंधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयां/विधिक वारिसां को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा बोमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

# [सं॰ एस-3501 ब/279/86-एस एस-**11**]

S.O. 319.—Whereas Messrs M.P. State Co-operative Housing Federation Limited, Sahjar Bhavan, North T.T. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh (MP/3321) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estalishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

\_\_\_\_\_

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payemnt of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwi-hstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under his Scheme are reduced in any matter, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for navment of assurance benefits to the nominee, or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assued to the nominee legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(279)]86-SS-JIJ

कारुप्रारु 320:— मैसमं दि चुक् सेन्ट्रंल को-ओर बैंक लिरु, चुक् (राजस्थान) (धारु जेरु/3568) (जिसे इसमें इसके पश्चात छक्त स्थापन कहा गरा है) ने कर्मचारी पविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उनधारा 2क के प्रधीन छूट दिये जाने के लिए धारोदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदा से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप भहबढ़ बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इनमें इनके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं।

भ्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त भ्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध भ्रतुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के भ्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की श्रवधि के लिए एक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### . श्रनुसूची

- 1. उन्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रापुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय जरकार, समय-सनय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, एक्त ब्रोधनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा आना, विवरणियों का प्रम्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय धादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित मामूहिक बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाये, तब उत संगोधन की प्रति तथा कर्म-.चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ग्रनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिशत करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रधिनियम के श्रधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उतके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

. 6. यदि उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक लाम्हिक बीमा स्कीम के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिलसे कि कर्मच।रियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हो जा उनत स्कीम के अधीन ग्रन्ज्ञेय हैं।

7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के ब्रधीन होता ती, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रावेशिक नविज्य निधि आगुक्त, राजस्थान के पूर्व भ्रत्मोदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशी-धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त अपना धनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों की धपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मच।री भारतीय जीवन बीमा निगम को उन्न साम्हिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवर्ग नियोजक तारीख के भीनर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे; प्रीमियम का संदाय करने में प्रसफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों की जी यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उनत स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन वीना निगम से बोमाकृत रक्षम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस-35014 (278)/86 - एस॰ एस-2]

S.O. 320.—Whereas Messra The Churu Central Co-operative Bank Limited, Churu, Rajasthan (RJ/3668) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinfater referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto. the Central Government hereby exempts the said estalishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shalf be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in establishment, the employer shall immediately enrol bim as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount nayable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under his Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nomines or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cusure prompt payment of the sum assued to the nominee legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|278|86-SS-II]

का० ग्रा० 3? 1:—मैं सर्स — सागर को० ओ० मिल्क प्रोडू-सरज यूनियन लि., सागर मध्य प्रदेश (एम.पी./3748) (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के श्रधीन छट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रामिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के ग्रायीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक श्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सह-बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें श्रनुतेय हैं।

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावक श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### ग्रनुमुची

1. उनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिवट्य निधि ध्रायुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 2. नियोज है, ऐसे निरीक्षण प्रमानों का प्रत्येक मास की त्रमाप्ति के 15 दिन के भीतर पंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड-क के प्रजीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, िसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा का प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या अकत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित क्यामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उनकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं ता, नियाजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से यृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकों से अधिक
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के श्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के श्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के श्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व भ्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त ग्रपना भ्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है श्रधीन महीं रह जाता,

है या इस स्कीम के श्रधीत कर्मणारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो आते हैं, तो यह छूट रह की आ सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवण नियोजन उस नियद कारीख के भीतर को भारतीय जीवन बीना निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में प्रक्षफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यितिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती ता, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के श्रधीन श्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देणितयां/विधिक नारिसों को वीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीयाकृत रक्तम प्राप्त होने के एक माल के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं॰ एस-35014(283)/86-एस.एस.-2]

S.O. 321.—Whereas Messrs Sagar Co-operative Milk Producers Union Limited, Sagar, Madhya Pradesh (MP|3748) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estalishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. Alt expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a conv of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and

- when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an engloyee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Privident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nomines of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to nav the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in nayment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
- 12. Under the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

[No. S-35014(283)]86-SS-II]

का. आ. 322:—मैं मर्न चोपड़ा मैंटल प्रा. लि. 8-वी, हैंबी इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर-342003 (आर.जे.) 3614) (जिसे इसमें इपके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क अधीत छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा र अट्टीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ग्रिधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवत वीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके परचात् उन्त स्कीय कहा गया है) के ग्रिधीन उन्हें अनुबेय हैं।

श्रवः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवतन से छुट देती है।

#### श्रन्मुची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणिया भेजेशा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय सनय पर निरिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिलको अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. तियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भिवष्य निधि की या उकत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियंजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उत्तका नाम तुरना वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीप्तियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायें जाते हैं तो, नियो क सामृहिक बीमा स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्क्रीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्क्रीम के अधीन अनुकूल हों जो उक्त स्क्रीम के अधीन अनुकूल हों जो उक्त स्क्रीम के अधीन अनुकूल हों जो उक्त स्क्रीम के
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मच रो की मृत्यु पर इस स्कीम के अवीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 1502 GI/86775.

- में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक दारिस/नाम निर्देशिती को अतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बरावर रकम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीभ के उपजन्थों में कोई भी संगीधन प्रादेशिक भविष्य निधि धायुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुभोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मवारियों के हित पर अतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक गविष्य निधि आयुक्त अपना अनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवकार देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी नारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अराना चुका है, अबीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अबीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फानदे किसी रीति से कम हैं जाते हैं, तो यह खूट रइ की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण नियोजक उस निवस तारीख़ के भीतर जो आरतीय जीवन बीवा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में यत्रफल रहता है और पालिशी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोधक द्वारा श्रीसियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दथा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो, उनत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदाबित्व नियोजक पर होता।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीत आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीम.कृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम, प्राप्त होने के एक नाम के भीतर मुनिष्यत करेगा।

[सं०एस-35014(234)/86-एस एस-2]

S.O. 322.—Whereas Messrs Chopra Metal Private Limited, 8-B Heavy Industrial Area, Jodhpur-342003(RJ]3614) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said estalishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Cen'ral Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
- 4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an envolvee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay nereserv premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in negment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal hoirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
- 12 Treen the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corneration of India shall ensure prompt navment of the sum assured to the nomine (legal heirs of the deceared member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

  [No. S-35014(284)]86-SS-II]

का.आ. 322:— मैंसर्स जबलपुर को. ओ. मिल्क प्रोह्सर्ज यूनियन लि., इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, अदारतल, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482004 (एम. पी./3746) जिसे इसमें इसके पण्चात् उनत अधिनियम कहा गया है) ने कर्मचारी मिविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, अधिनियम, 1952 (1953 का 17) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उनत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केम्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अनिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए गे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी लिक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्तेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कन्ते हुए और इससे उपाबढ़ अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश, को ऐसी विवर्ष यां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय समय पर निर्दिग्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो, कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, असके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रुप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगाऔर उसकी बाबात आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदल्त करेगा।

- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मणारियां को उनलब्ध फाउदे बकाए जाते हैं ता, नियाजक सामूहिक बीमा स्काम के अधीन कर्मणारियों का उपलब्ध फायदों में समुजित ध्य से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मणारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उनत स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी वार्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेथ रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेथ होती जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियाजक कर्मचारी के विधिक चारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दानां रक्षमां के अंतर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगाधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और अहां किसी संगाधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संसावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमादन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना वृष्टिकाण स्पष्ट करन का युक्तियुक्त अवसंद देगा।
- े. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मनारी भारतीय जीवन बीमा निगम का उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण नियोजक उस नियत तारीख के भातर जो भारतीय जीवन वीमा निगम नियत करे ; प्रीमियम का संदाय करन में असफल रहता है और पालिसी को अपनात हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी कानिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियां या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी मई होती तो, उनत स्कीम के अंतर्गत होते, वीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्तं स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी मदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता ने और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीना निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर मृनिष्मित करेगा।

# [सं॰ एस-35014( 285)/86-एस. एस-2]

S.O. 323.—Whereas Messes Jabalpur Co-operative Milk Producers Union Limited Industrial Estate, Andhartal, Jabalpur, M.P. (MP/3746) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group insurance Scheme of the Lite assurance Corporation of India in the nature of Lite Insurance which are more favourable to such employees that the benefits aumissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regionar Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer,
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportuinity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to any the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the em-
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all

[No. S-35014(285)/86-SS-II]

का. आ. 324.—मैतर्स मेहता बेजीटेबल प्राडवटस (प्रा०) लि., वितोइमढ राजस्थाम-312001 (आर.जे./1605) (जिसे इसने इसके पश्चात् उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियस, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पण्चात उनत अजिनियम कहा गरा है) की छारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अविदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी, किली पृथक अभिदाज या प्रीमियम का संदाय िए विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उनत स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उन्त अधिनियम की धारा 17 की उपधार: 2क द्वारा अदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए और इत्ते उपाबद अनुमुची में विनिदिष्ट शर्तों के अवीत रहते हए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीत के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

# अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आजवत, राजस्थान को ऐसी विदर्णायां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरहार, समय समय पर निर्दिण्ड करे।
- 2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिवियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3 सामहिक वीमा स्कील के प्रशासन में, जिसके अंवर्धत लेखाओं ता एका जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीशियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों पंजाय आदि भी हैं, होते वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय तरकार द्वारा अनुमोदित शामुहिक वीसा स्कीप के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन ित्या आए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों

- की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी शिवष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तूरन्त दर्ज करेगा और उतकी बाबत आवश्यक शीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाये जाते हैं तो, नियोजा सामृहिक बीमा स्कीम के अबीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्चित रूप से बुद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मच।रियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अन्जेय हैं।
- 7. साम्हिक बीभा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी बदि किसी कर्मचारी की सृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेव रक्ष उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय
- सामृहिक बीमा स्कीम के उपवंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युनितयुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के किसी कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम की नियत करे, प्रीसियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आन वाले किसी सदस्य की मृत्यु हाने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयां/विधिक वारिसा का बोमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सिनिम्बत करेगा।

[५न-35014(282)/86-एस. एत-2]

S.O. 324.—Whereas Messrs Mehta Vegetable Products (Private) Lamited, Chittorgarh (Rajasthan) 312001 (RJ/1605) (hereinatter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident, Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the henefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount pavable under this Scheme be less than the amount that would be pavable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall now the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, kajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance screene of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(282)/86-SS-II]

का. आ. 325 मैतर्स—भोपाल को-ओ. तेन्ट्रल वैंक वि., 24-25 न्यू मार्केट, टी. टी. नगर, भोपाल (एम. धी./ 2316) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उकत स्थापन कहा गय है) ने कमंचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, (1952 का 17) जिसे इसमें इसके पश्चात् उकत प्रधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा 2क) के प्रधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया हाक उसत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रामिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निर्भेष सहबद्ध बोमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एकत स्कीम कहा गया है) के ग्रायीन उन्हें श्रनुत्तेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसने उगवद अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्षकी अवधि के लिए उक्त स्कीन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### - अनुसूची

1. उनत स्थापन के सज्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भनिष्य निधि ग्रायुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधामें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जे। केन्द्रीय सरकार, उनत श्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।
- सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिनके अलागत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाता, बीमा प्रीधियम का सदाय, लेखाओं का प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय ऋदि भी है. हाने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा विधा जाएगा।
- नियंक्नि, केन्द्रीय अस्कार द्वारा चनुमोदित सामुहिक बीमा स्कीम के निथमों की एक प्रति और अब कभी उत्में मंभीवन किया आये, तब उस संगीवन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुलंडक की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुकाद स्थापन के सूचना पट्टपर प्रवर्णित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा क्षमंचारी जो क्षमंचारी निवध निधि का या उनत अधिनियम के अधील छुट प्राप्त किसी स्थापन की जीवच्य निध्य का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियंशीकत किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक वीमा स्कीम के सदार्य के रूप में उसका नाम त्रन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत भावश्यक प्रीमियम मारनीय जीवन बीमा निगम को सदल करेगा।
- 6. यदि जनत स्कीमा के खबीन कर्मसारियों को उपलब्ध फार्र्ड बढ़ाये आते हैं ती, नियोजिक सामृहिक बीमा स्क्रीम के ग्रधीन कर्मचारियां की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए नामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से पर्वज्ञ अनुकुल ही जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
- . 7. साम्हिक वीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश र्कम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेज होती अब वह उक्त स्कीम के ग्रधीनहोता ती, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोशों रक्षमों के अन्तर के बराबर एकम का संदाय करेगा।
- े. सामहिक बीमा एकीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रार्दोशक अविषय निधि ग्रासमेन, मध्य प्रदेश के पूर्व श्रनुमीवन के जिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रकार पड़ने की संमाधना हो, वहां रादेशिक मिक्टिंग निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अनुना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कमंचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थायन पहले प्रपना चुका है ऋधीन नहीं रहजाला है या इस रकीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदें यिसी रीति से कम हूं। जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

- 10. यदि किसो कारणवंश नियोजक उस लेख तारोख के भीतर जो भारतीय ओवन बीमा नियम नियत करे, प्रामियन का सदाय करन में असफल रहता है और पालिसा का व्यवस्तहा जान दिया जाता है ता, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत नदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिमां का जो यदि यह छूट न या गई हाता ता, उक्त स्कोम के अन्तर्गत हाता। बामा फायरों के संशाका उत्तरवाधितव नियाअक परहागा ।
- 12. उबत स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक इस स्कीन के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू हान पर उपकहादार नाम निर्देशितियां/विधिक वारिसों का वीमाकृत रकम का मदौष तत्परता से ओर प्रत्येक दशा में मारताय जाबन शीमा निगम से बानाकृत रकम प्राप्त हान के एक मास के भोतर सुनिधिचत करेगा।

[एस-35014( 277)/86-एस. एस.-2]

S.O. 325.—Whereas Messrs Bhopal Co-operative Central Bank Limited, 24/25 New Market, T.T. Nagar, Bhopal (MP)/2516) (hereinalter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said es ablishment shall submit such returns to the Regional Provident, Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection changes as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts. submission of returns, payment of insurance prema, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shalf be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sallent features thereof, in the language of the majority of the employnes.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

- o. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employee under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be graphle had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No arrendment of the provisions of the Group Insurance Scheme stall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, sive a reasonable approval, to the employees to explain their point of view.
- 9. When, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the sail establishment, or the benefits to the employee; under this Scheme are reduced in any manner, the examples shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the rolley is allowed to large, the exemption is liable to be cancelled.
- 11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for gunt of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Schene the Life insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomine/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(277)/86-SS-III

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1987 णृद्धि पत्र

का. था. 326.— -नारीख 9 ग्रगस्त, 1986 के भारत के राजपर, भाग [], खंड 3. उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के तारीख 24 जुलाई, 1986 के श्रादेण संख्या का. श्रा. 2797 के पृष्ट 3180 की तीसरी पंक्ति में "क्षेत्रीण कार्यालय" शब्दों के पृष्ट्यात् "और स्थानीय कार्यालय" शब्द पहें।

[संख्या ई-11012/1/86-एस. एस. 1]

New Delhi, the 14th January, 1987

#### CORRIGENDUM

\$.O. 325.—In the order of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2797, dated the 24th July, 1985, published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-action (ii) dated 9th August; 1986, at page 3181, in line 1, after the words "Regional Office" read "and Local Offices".

[E-11012/1/86-SS. T]

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1977

गा. आ. 327—मैसर्ग इण्डियन हाइल्डाफ इण्डिस्ट्रीज लि. शाहद रेलवे स्टेशन के निकट, पीस्ट वानस नं. 227. करवाण—421304 (एस. एस./1492) (जिसे इसमें इसके पण्मात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने अमंबारी भिज्य निधि और प्रकीर्ण इपवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) नी वारा 17की उपधारा (२क) के अधीन छट दिए जाने के लिए अन्वेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मकारी किसी पृथक सभिदार या प्रीमिसम का सन्ताथ किए बिना ही, भारतीय जीवन बीभा निगम की जीवन बीमा स्कीम की नामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जें फाउदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्म-चारियों की उन फायदों से अधिक अनुक्ष हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम. 1976 (जिसे इसमे इसके पण्चान् उवत स्कीन कहा गया है) के अधीन अनुक्षेय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रधिसूचना संत्या का. ग्रा. 1902 तारीख 2-4-1983 के श्रनुमरण में और इससे उपावद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के प्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 6-4-1986 से तीन वर्ष की श्रन्धि के लिए जिसमें 5-4-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

# भनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भित्रध्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा चौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुनिधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विदिष्ट करे।
- ्रि. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो ेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना वीमा प्रीमियम का सन्दाय, नेखाओं का प्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रया श्रमुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथां कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रमुबाद, स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रविक्ति करेगा।

- 5. यदि कोई ऐपा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनत अधिनियम के अधीन छुट प्रापा किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामहिक बीधा स्कीम के सदस्य के रूप में उन्नक्त नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उन्नकी बाबन प्रावश्यक प्रीमिनम भारतीय जीवन कीया निषम की सन्दस्त करेगा।
- 6 यदि माम्हिक जीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों मी उपलब्ध फायचे लड़ाये जाते हैं तो, नियोजक उनत स्कीम के भ्रवीत कर्मवास्थित की उपलब्ध फायदीं में समृचित रूप से गृद्धि की जाले की व्यवस्था करेगा जिपसे कि कर्मचारियों के लिए आम्हिक बीया स्कीम के अधीन उपलब्ध फाउदे उन फागदों से अधिक अनुकल हों, जो उनत स्कीम के अधीन भार्जीय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में कियी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रुक्तम अप रुक्तम से अस है जो वार्मचारी की उन वमा में अन्देय होती अब वह उक्त स्कीय के श्रधीन होता तो नियोजक वर्मपारी के विधिक वारिन/नामनिर्देणिती की प्रक्रित के रूप में वीलों रकमों के धन्तर के बराबर रक्तम का सन्दायं करेगा।
- 8. साम्हिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संजोधन, प्रािशिक भिष्य निधि श्रायम्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमीदन के बिना नहीं िया जाएगा और जहां किसी संपोधन से कर्मजारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भिध्य निधि आयक्त, प्रयना धनमंदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रयना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का पुलितयुक्त ज्ञवसर देगा।
- 9. यदि किपी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीरन बीमा निगम की उस मामृहिक बीमा स्कीम के. जि । स्थापन पहले धाना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मभारियों की प्राप्त होने वाले फा दे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सक्तते हैं।
- 10 यदि किसी कारणवश, नियोजक मारतीय जीवन बीमा निमम हारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्तय करने में प्रात्मल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो अने दिया जाता है लो छूट रह की का सकती है।
- 11. निजीज क बारा प्रोमियम के सन्वाय में किए गए कियो व्यक्तिम की वशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्धेश-तियाँ या निधिक वारिसों को जो यदि यह, छट न दी भई होती ती उपत स्कीय के प्रस्तर्गत हाते, बीगा फायकों के 'सम्बन्धः भाः' उत्तरकावित्व' नियोजक पर हकेता । '

12. इन स्कीम के अधीत छाने वाले कियी सदस्य की गरा होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमासन रागि के हरवार नामनिर्देशिकी/विधिक पारिसी को उस रागि का बदाव व तराध के और अखेन देशा में हर प्रहार सेपूर्ण दावें हो प्राप्ति के एक गाम के फोलर मुनिविचन करगा।

[संबन, एन-35014/78/83और, एक,-3/एन, एस -2]

New Delhi, the 16th January, 1987

S.O. 327.—Whereas Mesurs Indian Dyestuff Industries Limited, Near Shahad Railway Station, Post Box No. 227. Kalyan-421304 (MH/1492) (hereinafter referred to us the said establishment) invo applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Hinked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in evereige of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1902 dated the 2-4-1983 and entirect to the conditions specified in the Schedule annexed boreto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 6.4-1986 upto and inclusive of the 5-4-1989.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and manifain such accounts provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time,
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clouse (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Gornoration of India.
- The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the cald Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said
- 7. Notwishstending anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable, under this scheme be less than the amount that would

be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one moth from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/78 '83-PF-II-SS-II]

का. श्रा. 328 — मैंसर्स रणवक्सी लेकोटरीज लि.. ओखला, नई दिल्ली-110020 (डी. एल./1546) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छूट दिए जिने के लिए श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मभारी किसी पृथक ग्रिनियय या प्रीमियम का सन्दाय किए विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्म-चारियों को उन फायदों से ग्रिधिक ग्रनुकूल हैं जो उन्हें कर्मभारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उनत स्कीम कहा गया है) के ग्रिधीन ग्रनुज्ञेय हैं;

श्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त श्रिधिनियम की धारा करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंद्रालय की ग्रिधिसूचना संख्या का श्रा. 3658 तारीख 19-7-1983 के श्रनुसरण में और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-9-1986 से तीन वर्ष की श्रवधि के लिए जिसमें 24-9-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं। 1502 G1/86—6.

### धनुसूची

- गुरुवत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भिष्य निधि धायुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके ध्रन्तगंत लेखाओं का रखा जाना, विधरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का ध्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय ध्रादि भी है, होते वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बार्ती का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी अविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनयम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्त हों ।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के भ्रधीन सन्देय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के भ्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिद्धिती को प्रा. कर के रूप में दोनों रकमों के भ्रन्तर के बराबर रक्तम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और अहां किसी संशोधन से कर्म-चारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो

महा प्रावेशिक भविष्य निधि भायुक्त, घरना धनुमोदन वेने से पूर्व वर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रमसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, मा इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाल फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, नो यह छूट रह की आ सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय भीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में ग्रसफल रहना है, और पालिसी को व्यपगन हो जाने दिया जाता है तो छुट रद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे- मितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के ग्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा कि राशि के हकदार नामनिर्धेशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावें की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/90/83-पी. एफ . -2/एस . एस-2]

S.O. 328.—Whereas Messrs Ranbaxy Laboratories Limited, Okhla, New Delhi-110020 (DL/1546) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Punds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible unde the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

New therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3658 dated the 19-7-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the gaid Scheme for a further period of three years with effect from 24-9-1986 upto and inclusive of the 24-9-1989.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount nayable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are areduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt rayment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one moth from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/90/83-PF-II-SS-II]

का. श्रा. 329— मैससं प्रैशर कुकर एण्ड एपलियन्स लि., एफ-101, मेकर टावर, पो.ओ. वाक्स-16083, क्यूफी परेड, बस्यई और इसकी शाखाएं (एम.एच.-6333/इक्सन/27) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिये जाने के लिये ग्राबेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान के कर्नचारी किसी गृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, अंत्रतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के का में जो फायदा उठा रहे हैं से ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976(जिसे इप्तमें इसके पण्चात् उका स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

भतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त भ्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त भिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंत्रालय की भ्रधिसूचना संख्या का. भा. 3710 नारीख 19-7-1983 के भ्रतुमरण में और इससे उपावक भ्रनुसूची में विनिदिष्ट भर्तों के भ्रधीन इते हुए उक्त स्थापन को, 1-10-1986 से तीन वर्ष की भ्रवधि के लिये जिसमें 30-9-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

# भ्रनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक अविषय निधि श्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. तामूहित बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके झत्तमंत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन तियोजक द्वारा किया जायेगा ।
- 4. तियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के तियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म जिर्मे की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों पा अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्णित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उपत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्यापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजिंग किया जाता है तो नियोजिंक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की मन्दल करेगा।
- 6. यदि सामूहिक वीमा स्कीम के ब्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं ती, नियोजक उन्नत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुखित रूप

- से वृद्धि की जाने की ध्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजोय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के, धवीन सन्देय रकम उस रकम से कम है तो जो कर्मचारी को उस देशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के धवीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के धन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेंगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भाविष्य निधि भ्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व भ्रनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, भ्रगना भ्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भ्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मवारी, मारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्वीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अजीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्तीन के अजीत कर्मवारियों की प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोशक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीज के भीतर प्रोमियम का संदाय करने में श्रातकत रहता है, और पालिसी की व्यवसत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम- निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दो गई होती तो उनत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के प्रधीत ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होते पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीसाइन राशि के हक्तरर नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों की उस राशि का का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दमा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/126/83-पी. एफ. -2/एस. एस. -2]

S.O. 329.—Whereas Messrs Pressure Cookers and Appliances Limited, F-101 Makers Towers, P.O. Box-16083, Cuffe Parade, Bombay including its branches (MH/6333/Exn/27) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3710 dated the 19-7-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-10-1986 upto and inclusive of the 30-9-1989.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and manitain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/126/83-PF-II-SS-II]

का आ. 330: — मैसर्स रिक्ट एंड कोलमैन ऑफ इंडिया लि., 41, चौरंघी रोड, कलकत्ता-700071 (डब्ल्यू. बी./1190) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध मधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चारा उक्त प्रिवित्यम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट दिए जाने के लिए म्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापन के कमचारी किसी पृथक श्रभिदाय या श्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से श्रधिक श्रनुकृल हैं जो उन्हें कमचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन श्रनुक्षेय है;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधसूचना संख्या का. श्रा. 3662 तारीख 19-7-1983 के ध्रनुसरण में और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के श्रधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-9-1986 से तीन वर्ष की श्रवधि के लिए जिसमें 23-9-1989 भी सिम्मिलित है, उक्त स्कीम है सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

# **प्रनुसू**ची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रावेशिक भविष्य निधि धायुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो के भीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की घारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के श्रिधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना,

भीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा श्रनुमोदित साम्-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभा उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुशाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मधारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनियम के श्रिधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाय जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रुप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से श्रधिक श्रनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के श्रधीन श्रमुकेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।
- 8. सामृहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर वेगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृद्धिक बीमा स्कीम कि, जिसे स्थापन पहले प्रपना खुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में प्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों

या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर हागा।

12. इस स्कीम के अधीन श्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राणि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिध्चत करेगा।

[संख्या एस-35014/94/83-पो. एफ2 /एस. एस-2]

S.O. 330.—Whereas Messrs Rockit and Colman of India Limited, 41, Chowringhee Road, Calcutta-700071 (WB|1190) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Laboury S.O. 3662 dated the 19-7-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-9-1986 upto and inclusive of the 23-9-1989.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal here/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional rovident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the payment of premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nonlinees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one moth from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/94/83-PF-II-SS-II]

# नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1987

का. आ.331--राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 क 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में श्री बी. के. बरुआ के स्थान पर श्री बी. एम. हजारिका, सचिव, असम सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा नियम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्विष्ट किया;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ॰ 545 (अ), दिनांक 25 जूलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :--

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद्द 9 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

> "श्री बी. एम.हजारिका, सचिव, असम सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, दिसपुर(असम)".

[संख्या यू-16012/7/85-एस. एस-1]

### New Delhi, the 20th January, 1987

S.O. 331.—Whereas the State Government of Assam has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948) nominated Shri B. M. Hazarika, Secretary to the Government of Assam, Labour and Employment Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri B. K. Barooah,

Now, therefore in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. No. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against Serial Number 9, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri B. M. Hazarika,

Secretary to the Government of Assam, Labour and Employment Department, Dispur (Assam)."

[No. U-16012]7[85-5S. I]

### नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

का. प्रा. 332—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठिन धारा 88 द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंद्राख्य की धिध्मूचना संख्या का. प्रा. 2661, तारीख 30 जुलाई, 1984 के क्रम में, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के दाल मिल, लखनऊ के नियमित उर्मेषारियों को उक्त धिनियम के प्रवर्तन में पहली धक्तूबर, 1984 से 30 सितम्बर 1987 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलत है, की ध्रवधि के लिए छुट देतीं है।

उनत छूट निम्नलिखित शर्तो ने प्रधीन है, प्रयात:--

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दक्षित किए जाएणे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संवत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त भवधि के लिए यदि कोई भिभदाय पहले ही संदरत किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए आएंगे।
- (4) उन्त कारखाने का नियोजक उस प्रविध की बाबत जिसके दौरान उस कारखान पर उन्त प्रधिनित्त प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात उन्त अविधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य वीमा (साधारण) विनियम, 1950 के बंधीन उसे उन्त अविधि की बाबत देनीं थीं।

- (5) निगम द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के प्रधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमिक्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,——
  - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विभिष्टियों को सस्यापित करने के प्रयोजनी के लिए, या
  - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनिध्म 1950 द्वारा प्रया अपेक्षित रिक्स्टर और अभिनेख उका अपि के लिए रखं गए थे या नहीं, या (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियाजक द्वारा दी गई उन प्रसुतिधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं। जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तुरूप में पाने का हकदार वना हुआ है या नहीं; या
  - (iv) यह श्रभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस श्रविध के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में श्रिधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का श्रनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सणकत होगा:---

- (क) प्रधान नियोजक या श्रव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उमे ऐसे जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक था अव्यवहित नियोजक के अभिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारताधक व्यक्ति में यह अपेका करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के मंदाय से संबंधित ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुन करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आयं यक समझें, या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्धवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिलके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है या वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या
- (ध) ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या भ्रन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, ृलेखाबही या अन्य दस्तायेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं. एत.-38014 /39/86 एसएस-1]

### स्पष्टीयारण शापन

इस मामले में छूट का भूतकाती प्रभाव देना भावप्यक हो गया है, क्योंकि छूट के लिए द्वावेदन पन्न विकम्ब से प्राप्त हुआ था, किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतरक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हिस पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### New Delhi, the 21st January, 1987

S.O. 332.—In exercise of the power conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 2661 dated the 30th July, 1984, the Central Government hereby exempts the regular empoiyees of the Dal Mill, Lucknow belonging to the Food Corporation of India, New Delhi from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1984 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950:
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

#### be empowered to-

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and

- other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document, maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/39/86-SS, T]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

### नई विल्ली, 21 जनवरी, 1987

का. आ. 333.— मैंसर्स जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, डीडवानोली, लास्कर, ग्वालियर-474001 (एम. पी./1092) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का 17) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

असः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रवत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा विया जाएगा।
- 4. तियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम् भारतीय जीवन बीमा निगम को संवस करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के क्या में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीस के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म- चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मघारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदें किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है:
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को अयपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रह की जा सकती है।

- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्धेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के ग्रधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदिशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर निश्चित करेगा।

[एस-35014(1)/87-एस . एस .-2]

New Delhi, the 21st January, 1987

S.Q. 333.—Whereas Messrs Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadi, Deedwanaoli, Lashkar, Gwalior-474001 Madhya Pradesh) (MP|1092) (hereinalter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinalter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and sub-ject to the conditions specified in the Schedule annexed heteto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHFDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhva Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer,
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 1502 GI/86-7.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than thebenefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the Interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heits of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(1)|87-58-II]

का. आ. 334 — मेंसर्स मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, एच. ओ. मलटी स्टोरिड बिल्डिंग, टी. टी. नगर भोपाल, 462003 (एम. पी./1111) (जिसे इसमें इसके परवात उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके परवात उकत श्रिधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा 2क) के ग्रिधीन छूट दिय जाने के लिए ग्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मे बारी, किसी पृथक श्रिभदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मेचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976) जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रनुक्रेय हैं; भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदस्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्ध प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधीन रहो हुए, उन्न स्थानन की तीन वर्ष की ग्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवतन से छूट देशी है।

### धनुसूची

- 1. जक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिविष्य निधि प्रायुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भजगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का यप्रत्क मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरहार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसकें अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया आना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का घन्तरण, निरीक्षण प्रभारों प्रादि भो है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामुहिक बोगा स्होन के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाय, तब उन्न संगोधन की प्रति तथा कर्म-चारियां की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रवशित करेगा।
- 5. प्रदि काई ऐता कर्मवारी जो कर्मवारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भित्रिष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिन सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत भ्रायश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीन के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ से जाते हैं, तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारि ों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से ग्रधिक अनुकूल हों तो उक्त स्कीम के ग्रधीन मनुक्रेय हैं।
- 7. सःमूहित बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किती कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मवारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मवारी के विधिक धारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशक भिषय मिधि धायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भिवष्य निधि भायुक्त ध्रूपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ध्रपमा दृष्टिकाषण स्पष्ट करने का यवितयुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के भ्रधीन कमचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी ीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संवाय करने में भसफल रहता है और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम को दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशि-तियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के भ्रन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उरसरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृथ्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों/विधिक दारिसों को बीमाकृत रक्त का संकाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रक्तम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिध्वित करेगा।

[एस-35014(2)/87-एस . एस .-2]

S.O. 334.—Whereas Messrs Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, H.O. Multistoreyed Building, T. T. Nagar, Bhopal-462003 (MP/1111) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and sub-ject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years;

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Com-Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been coverd under the hald Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employes of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any teason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineed legal heirs of the deceased number entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

335 --- मैसर्स -- ग्रमर्ज्योति टेक्सटाईल प्रोसैसर्जे, 12 हैवी इन्डिस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (राजस्यान) (म्रार, जे./3008) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भ्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भ्रधीन छट दिये जाने के लिए भ्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिनाही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवनबीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदेउन फायदों से प्रधिक प्रनुकुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा लीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा शया है) के प्रधीन उन्हें प्रनुजेय हैं।

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा- 2क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, उन्त स्थापन को तीन वर्ष की भ्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है।

### धनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, राजस्थान की ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन्त श्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामृहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके श्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामू हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ग्रनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त मधिनियम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता हैं तो, नियोजन सामृहिक बीया स्कीम

INo. S. 35014(2)!87-SS-I)1

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

- 6. यदि उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की ट्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में श्रधिक श्रभुकूल हो जो उक्त स्कीम के श्रधीन श्रमुक्त हो जो उक्त स्कीम के श्रधीन श्रमुक्त हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी वात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मवारी को उस दणा में संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक वीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेणिक अविष्य निधि भ्रायुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक जविष्य निधि श्रायुक्त ध्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रयसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंग स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम का उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अवना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्नचारिया का प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हा जाते हैं, ता यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि फिसी कारणवंग नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रातकल रहता है और पालिसी को उपयगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमित्रम के संदाय में किये गये किसी व्यतिकम की दणा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो अदि यह छूड़ न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बोमा फाउदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पणता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस.-35014(3)/87-एस. एस.~2]

S.O. 335.—Whereas Messrs Amariyoti Textile Processors, 12 Heavy Industrial Area, Jodhpur (Rajastran) (RJ|3008) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (17 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the empployees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shalf be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthau and where any unundment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted, by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the prendum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of decreased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

No. S-35014(3) 87-SS-II

का. भा. 336: — मैससं कालेखान मुहम्मद हनीफ, गुजराती बाजार, सागर, मध्य प्रदेश । (एम.पी./2992) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रिधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रिधिनयम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क) के श्रिधीन धूट दिय जाने के लिए श्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाद दा प्रीमियम का संदाय किय बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और एमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक श्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इनमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गना है) के श्रवीन उन्हें श्रनुजन हैं।

श्रातः केन्द्रीय सरकार, उत्तन श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायद्व श्रानुसूचों में विनिदिष्ट शर्तों के श्राधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की श्रावधि के लिए उक्त स्कीन के लगी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

# **अनुसूची**

- 1. उनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिविद्य निधि भ्रायुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजिक, ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के ग्रिधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

- 3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके श्रन्तगंत लेखाओं का रखा जानां, विवरणियों का प्रस्तृत किया जानां, वीता प्रतिभिध्य का संदाय, लेखाओं का श्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रादि भी हैं, होते वाले गभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय गरकार द्वारा धनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों के एक प्रति और जब कभी उनमें नशीधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का छानुबाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिन सामूहिक बीमा स्कीम क सदया के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उकत स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फारदे बढाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फारदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अवीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब बहु उक्त स्कीम के अवीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोंनों रकमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई मी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के जिना नहीं किया उत्तएगा और जहां किसी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अन्ना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रदव् की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में ग्रथफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापम के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के भ्रधीन भ्राने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार गाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाश्चत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइन्त एकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(4)/87-एस.एस-2]

S.O. 336.—Whereas Messrs Kale Khan Mohd. Hanif, Gujarati Bazar, Sagar (Madhya Pradesh) (MP|2992) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient fetures thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been coverd under the said Scheme, the employer shall pay the diffe ence to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees or the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the beneats to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowe to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the numineel legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(4)[87-SS-II]

का. आ. 337:---मैसर्स न्यूटैक रिफेट्रीज प्रा. लि., पोस्ट बाक्स नं. 63, 5-के.एम. अजमेर रोड, भीलवाडा (राजस्थान) (ग्रार.जे./4164) (जिसे इसमें इसके पश्चात उन्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविषय निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपघारा (2क) के भ्रधीन छूट दिये जाने के लिए ग्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक मिश्रदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृष्टिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मणारियों के लिए ये फायदे

उन फायदों से भिधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निसीप सहबस बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें अनुजोय हैं।

चतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम, की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबक श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की श्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रयर्तन से छूट देती है।

# **श्रनु**सूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगी और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुनिधार्य प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भ्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिश्यत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी मिविष्य निधि का या उनत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की मिविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में असका नाम तुरन्त दर्ज अरेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि किये जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक धनुकूल हो जो उक्त स्कीम के ध्रधीन प्रमुक्त हो जो उक्त स्कीम के ध्रधीन प्रमुक्त हो जो उक्त स्कीम के ध्रधीन प्रमुक्त हो जो उक्त स्कीम के ध्रधीन
- 7. सामृहिक वीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के भ्रवीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा

में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के मधीन होता ती, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम-निर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अस्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धां में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि धापुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हों, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त ग्रंपना ग्रनुमोदन देने से पूर्व कर्म नारियों को ग्रंपना कृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश नियोजक उस नियंद तारीख़ के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियंत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रसफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिकम की व्या में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के भधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(5)/87-एस.-एस-2]

S.O. 337.—Whereas Messrs Nutech Refractories Private Limited, Post Box No. 63, 5 K.M. Ajmer Road, Bhilwara, Pin Code-311001 (Rajasthan) (RJ|4164) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Raiasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, Te employees of the said establishment do not remain covered under the Groun Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to Japse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt rayment of the sum assured to the nomine legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(7)87-SS-II]

का. आ. 338.—मैंसर्स सुखना पेपर मिल्ज लि., एल. सी. ओ.-116-117, सैक्टर 8-सी, मध्यामार्ग, चण्डीगढ़, (पी. एत./10325) (जिसे इसमें इतके पश्चात् उकत स्थापत कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध श्रिधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उकत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सर हार का समाधान हो गया है कि उनत स्थान के हर्मचारी, किसी पृथक अनिदाय या प्रीमियम का संदान किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निजम की नामूहिक बीमा स्तीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फानदा उठा रहें हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इपमें इजके पश्वीत् उनन स्कीम कहा गया है) के प्रधीन अनुजेष हैं।

अतः केन्द्रीय सरहार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपनार-2क द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए और इतने उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट गर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थान को तीन वर्षकी प्रवधिके लिए उक्त स्कीम के नभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है।

### अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य तिथि प्रायुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा एखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भरतार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजित, ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मामकीय समाधित के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीर समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक जी मा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीवा गीति (न हा चंदाः, लेबाओं का अन्तर्ग, निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है, होते वाले सभी व्ययों का बहन नियोजिङ द्वारा दिवा जाएगा।
- 4. निर्मोजन, केली। तरकार हारा अनुमोदिन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया गाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा मंचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य जातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविधत करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिक्षिण निधिका पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित सामृष्टिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसकी नाम तुरत्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रतियक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. पदि उक्त स्तीम के प्रधीन कर्मचारियों को उक्तव्य फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिल्मे कि कर्मचारियों के लिए नामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों में प्रधिक अनुकूल हो जो अक्त स्कीम के अधीन आज़ीय हैं।
- 7- सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हात हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रक्षम में कम है जो कर्मचारी को छस दणा में संदेय होती जब वह उक्त रकीम के अधीन होता तो, नियोगक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देणिकी को प्रतिकर के घप में सीनी रक्षमों के अत्तर के बरावर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. शामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में काई भी गंगोधन प्रावेणिक भिवाय निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अत्मोदन के बिना नहीं, किया जाएगा और जहां किसी मंगोधि, से वर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संविधना हा, वहां प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अपनर देना।
- 9. प्रदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मवारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले आना चुया है प्रधीन नहीं रह जाता है पर इस स्कीम के ग्रधीन कर्मवारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हा जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. पदि किसी कारणकण नियंकिक उप नियत तारीख के भीतर और महिनोप जीवन बोसहितगर नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रमफल रहता है और पहिनशी को व्यपगत हो अहे दिए उपना है तो, छूट रह की जा भवती है।
- 1) नियाशक द्वारा श्रीमिथम के संदाय में किये गये किया व्यक्तिकम की दक्षा में उन सृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विश्विक पारिसों की जो यदि यह छूट म दी गई हाता ता. उस्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदी के गंदाय का उत्तरशायित्व नियाशक पर होता ।
- 13. उनते स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक इन स्कीम के खातीन आन बाल किसी भदस्य की मृत्यु होने पर उसके छक्तार पाम निर्देशितियों/जितिया गरियों को बीभाइत रकम का संदार तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बाना नियम से बामाइत रकम गरण होते के एक भाष के भीतर मृतिण्यित करेगा।

[एस.-35014(6)/87-एस. एस.-2]

S.O. 338.—Whereus Messrs. Sukhna Paper Mills Limited, S. C. O. [16-117, Sector P.C. Madhya Marg, Chandigarh (PN]10325) (hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Misceilaneous Provisions Act, 1952 (19 of 19522) (hereinalter referred to as the said Act);

-- -

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurunce Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance, which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, m exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and sub-ject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said enablishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- I. The employer in relation to the said establishment shall subrult such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- ? The employer shall pay such inspection charges as the Contral Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, termsfer of accounts, payment of inspection charges etc. hall be borne by the employer.
- d The employer shall display on the Notice Board of dis establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Comporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirhominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Chindigarh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the comployees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view,

- 9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt nayment of the sum assured to the nomineel legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(6)]97-SS-III

का. आ. 339.—मैंसर्स कुमार फैब्रिक्स (प्रा.) लि., 71/74 इन्डस्ट्रियल एरिया, बोहद रोड, बनसवारा-327001 (श्वार.जी./4083) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी मिवष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध श्रधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त श्रधिनियम कहा गया है) (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए अवदेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन वीमा के रूप में फायदे उठा रहें हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अवीन उन्हें अनुझेग हैं।

अतः केन्द्रीय सरकाण, उक्त श्रिष्ठिनयम की धारा 17 की उभ्धारा -2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के श्रिष्ठीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की श्रविध के लिए उक्त स्थापन के अवर्ध के लिए उक्त स्थापन के अवर्ध के लिए उक्त स्थापन के अवर्ध के श्रविध के लिए उक्त स्थापन के अवर्ध के श्रविध के लिए उक्त स्थापन के अवर्ध के श्रविध के श्रव के श्रविध के श्रव के श्रव

### श्रनुसूची

- गः उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजिक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान क्रेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करें।
- 2. तियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा 2-क के खण्ड-क के श्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विश्वरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीना श्रीमियम का सक्षाय, लेखाओं का यहाना, विश्विम प्रभारों का संदाय ब्यादि मी है, होते वाले सभी ध्यमं का तहन नियोगक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमादित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंगीधन किया जाये, तब उन मंगीधन की प्रति तथा हर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उमकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिन सामूहिक बीमा स्कीम के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदरत करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि किये जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक श्रमुकूल हैं। जो उन्त स्कीम के श्रधीन अभुजों है।
- 7. पाम्हिक बीमा स्कीम में कियी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीत संदेव एकम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दथा में संदेव होती जब वह उक्त स्कीम के अधीत होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितो को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामृष्टिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंग्रोधन प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त. राजस्थान के पूर्व श्रनुमंदिन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिभूक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भिष्य निधि श्रायुक्त ग्रयना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रयना मृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रयन्य देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा, निगन को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिले स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियस तारीख़ के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्री-भियम का संदाय करने में प्रक्षफल रहता है और पालिसी कं व्यपनत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- ा। नियं। जक द्वारा प्रीभियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देगितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती ती. उकत स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के सवाय का उन्तरदायित्व नियं। अक पर होगा।
- 12. उकत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के ध्रधीन आने याले जिसी भित्रस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितयों/विधिक वारिसो का बीमाकृत रकम का संदाय रुत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर सुनिम्बत करेगा।

# [एस-35014 (7)/87-एस एस-2]

S.O. 339.—Whereas Messrs Kumar Fabrics Private Limited, 71/74 Industrial Area, Dohad Road, Banswara-327001 (RJ/4083) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund, & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 5 the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charge, as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately entol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shalf be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the prendum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Schone but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under—the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(7)|87-SS-II]

का आ . 340 — मैंसर्स सौराष्ट्रा केमिकल, पोरबन्दर360576 (गुजरात) (जी.जे. 1367) (जिसे इसमें
इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य
निधि और प्रकीण उपवन्ध श्रिधिनियम, (1952 का 17)
(जिमे इसमें इसके पण्चात् उक्त श्रिधिनियम कहा गया है
की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छुट दिये जाने
के लिए श्रावेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की भामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें अनुक्रोय है।

श्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायद्व श्रनुसूची में विनिधिष्ट गैतों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की श्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### श्रनुस्ची

- 1. उन्त स्थापन के सबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा एथा निरीक्षण के लिए ऐसी मृशिधायें प्रवान गरेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समग्र पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाध्य के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा--17 की उपधारा 3-क के राष्ट-क के ग्रधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।
- 3. राम्हिक बीमा क्लीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत नेखाओं का रखा दाना, धिवरणिया का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदीय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सदीय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा ध्रम्भोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पष्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उपत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा रकीम के प्रधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से प्रधिक अनुकूष हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन मनुग्नेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जा कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता लो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के एप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई भी संगोधन प्रादेणिक भविष्य निधि प्रायुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के जिला नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कमैचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो. वहां प्रादेणिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना प्रमुमोदन देने से पूर्व कर्म जारियों को अपना दृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवस्त देगा।
- 9. यदि किसी नारणवण स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस साम्हिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चला है श्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवर्ग नियोजकं उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रसफल रहता है और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो. छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजन द्वारा श्रीभियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रधीन भाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

$$[v_{H}-35014(8)/87-v_{H}, v_{H}, 2]$$

S.O. 340.—Whereas, Messrs Savrashtra Chemicals Porbandar-360576 (Gujarat) (GJ/1367) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Lunds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

- I. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Guijarat and maintain such accounts and provide such regardless for impaction, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the subent features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately curol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adveserly the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Whereas, for any reason, the employer fails to nay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(8)/87-SS-II]

का. ह्या. 341.—मैसर्स-महाराष्ट्रा एग्रो इन्डर्म्ड्राज डिवेल-पमेंट कारपोरेणन लि. राजन हाऊस, तीसरी मंजिल प्रभादेवी, बस्बर्ट (एम. एच./11072) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त न्थापन कहा गण है) ने कर्मचारी जिण्य निवि और प्रकीर्ण उपवन्ध ग्राधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त श्राधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा-2 क के प्रजीन छूट दिये जाने के लिए आनेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गना है कि उक्त स्थानन के कर्नचारा, किसो पृथक अनिदान या प्रीमियम का संदाय किये जिना ही, नारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अवीन जीवन बीमा के का में फायरे जटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फानदे उनका खों से अधिक अनुकूल है जो इनचारी विक्षेप सहबढ़ बीमा रकीन, 1976 (जिने इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा नता है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं।

अ.त. अन्द्रीय राज्यार. अवत अधिनियम की धारा 17 की उपवार:- 2क होता प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इपमे उपावज अनुम्बी में विनिधिष्ट शर्तों के अधीन एहमें हुए उकत स्थापन की तीन वर्ष की ग्रवधि के लिए उकत स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छुट देशी है।

### ग्रन् सूची

- । उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियंत्वक प्रादेणिक मांबर्य निर्धि आयुक्त, बम्बई को पैसी निवरणियां भेजेगा और ऐसे निवा रखेगा निया निरीक्षण के निष् ऐसी मुन्धियां प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माभ को मनाप्ति के 15 दिन के भीतर मदाध करेगा को केन्द्रीय भरकार, उक्त स्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के स्रिधीन समय-प्रभय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गन लेखाओं का एखा ज(त), विवर्णण्या का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीरिपन का संदार, लेखाओं का अन्तरण, निरिक्षक प्रमारों संदार आदि भी है, होते वाले सभी व्ययं का बहुत नियंकक द्वारा विया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय भरकार द्वारा अनुमोदित अस्मृहिक बीमा स्कीत के नियोगों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया असे, तच उन संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंद्या की भाषा में उसकी मुख्य बातां का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शिन करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनिधम के अधीन छूट प्रत्या किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजीत किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम

के सदस्य के रूप में उसका नाम नुरस्त दर्ज करेगा और उन्की गामत श्रावण्यक श्रीमिश्रम भारतीय जीवन वीमा निगम को संदर्भ करेगा।

- 6. यदि उनत स्कीम के श्रयीन कर्मचारियों को उनलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के श्रयीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि किये जाने की व्यस्था करेगा जिसमें कि टर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में श्रधिक अनुकृत हो जो उक्त स्कीम के श्रधीन अनुकेय हैं।
- 7. सामूहिक बीना स्कीम में किसी बात के होते हुए भी प्रदि किसी वर्मचारी की जून्य एए हम स्कीम के श्रवीत संदेय रकम उस रक्षम में कम है जो कर्मचारी को उस दगा में संदेय होती जग वह उकत स्कीम के श्रवीत होता तो, नियंशवा कर्मचारी के विधिक व्यक्ति | नाम निर्देशिती को प्रतिकर के ख्या में दोनों रक्षमी के अन्तर के वरावर का संदाय करें।
- 8. मामूहित बीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई भी संगानत प्रादेशिक भविष्य निधि धायुक्त, वस्वई के पूर्व प्रनुतोदन के बिना नहीं विधा आएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभावन हो, वहां प्रादेशिक अविष्य निधि प्रायुक्त अपना प्रनुपेदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्राना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गुक्तिनुका अवकार देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस लामूहिक बीमा रकीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है श्रधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो प्रश्तीय जीवन बीपा नियम नियत करें, प्रीमियम का संवाप करने में श्राप्तकल रहता है और पालिसी को व्ययपत हा जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा लक्ष्ती है।
- 11. नियाजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट नदी गई होती नो, उक्त स्कीम के प्रन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदान का उत्तराजित्य नियोजक पर होगा। पर
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के प्रक्षीन आने वाले जिसी रायस्य की मृत्यु हो। पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का मंदा। तत्यरता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बींगा नियन से बींगाकृत राज्य प्राप्त होने के एक मास के भीतर गुनिश्चित करेगा।

[एस. -35014( 9) /87--एभ .एस-2]

S.O. 341.—Whereas Messis The Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited, Rajan House, 3rd Froor, Prabhadevi, Bombay (MH/11072) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees\* Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### **SCHEDULE**

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- A The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme,
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to effect adveserly the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9 Where, for our reason, the employees of the soil establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the promium are, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefit; to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the mominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(9)/87-SS-II]

#### CORRIGENDUM

S.O. 342.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2727 dated 21st July, 1986, published in the Gozette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 2nd August, 1986, in line 1 after the word 'Mechanical' the word 'Works' shall be interted.

[No. S-35014(201)/86-SS-II]

का. ओ. 343.—गुजरात राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (प) के अस्भरण में श्री पी. वी. भट्ट के स्थान पर श्री एम. पी. पारेख, सिचत्र, गुजरात सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

• अतः अत केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, आरत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या हा. ा. 545 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निमालिश्वित संशोधन करती है, अर्थात् :—

जिस्त अधिगूचना में, "[राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मद् 11 के सामने की प्रतिष्टि के रथान पर निम्न-लिखित प्रतिष्ट रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"श्री ए.स. पी. पारेख, सचिव, गुजरात सरदार, स्वास्थ्य और परिवार, कल्याण विभाग, न्यू क्षति ॥लय, कम्पलेक्स, ब्लाक नं. ७, ७वीं संज्ञिल, गांधीलगर ।"

[संख्या यु-16012/11/85-एम: एस: -T]

S.O. 343. Whereas the State Government of Gujarat has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated M. P. Parekh, Secretary to the Government of Gujarat to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri P. V. Bhatt;

Now, therefore, in pursuante of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the

notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely: -

in the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry againg Serial Number 11 the following entry shall be substituted, namely:—

'Shri M. P. Parekh, Secretary to the Government of Gujarat, Health and Family Welfare Department, New Sachivalava Complex, Block No. 7, 7th Floor, Gujarat."

INc. U-16012/11/85-SS-II

### गुद्धि-पन्न

का. आ. 3.44.—भारत के राजपन, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 5 जनवरी, 1985 को प्रकाशित, भाग नरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वाक्ष मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 84, दिनांक 26 दिक्षकर, 1984 के पृष्ठ 85 की पंक्ति 11 -12 में -

"वीरापांडी" के लिए "बीरापांडी नंबर 4" पढ़ा आए।

[संख्या एम-38013/23/84-एस एन -I]

#### CORRIGENDUM

S.O. 344.— In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), No. S.O. 84, dated 26th December, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 5th January, 1985 at page-85 in line 12 for "Vec apandi" read "Vec apandi No. 4".

[No S. 38013(23)/84 SS.]

नई दिल्ली. 22 जनवरी, 1987

का. आ. 345. केन्द्रीय मंग्कार को यह प्रतीन होता है कि निम्नलिखन स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्म-भारियों की बहुसंख्या इस बान पर रहमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य िधि और प्रकीर्ण उपयंध अधिनियम, 1952 (1952 क. 19) के उपवंध संबंधित स्थापन की लाग किए जाने चाहिएं:--

- मैंसर्स वोनाफाइड एक्सपोर्टरा, पटवा चैम्बर्र, पांचवीं मंजिल, परिजद स्टेशन के सामने ताना बन्दर यम्बर्ड-9
- मैं अर्स माडल हाई स्क्ल, कस्तूरबा नगर, वासीनाका, बस्बई-74
- ः मैनर्स खादी साम को-अप्रेटिट कन्टीन लिनिटिड, 3 इरला रोड, विले वार्ले (पश्चिम), अम्बर्ण-56
- मैनमं दी पेपर रील्स कंपनी, बी-14 रायल इडस्ट्रीरल एस्टेट नया गांव कास रोड, वदाला, बम्बई-31
- 5. मैंसर्म में टरल इन्वेस्टीगेशन एंड लिक्यूरिटी सर्विभिज प्राउवेट लिमिटिड, 160डी. एन, पंड, प्रथम मंजिल, फोर्ट बम्बई-1
- मैशसं पी०जी० इलैक्ट्रोनिक्स '217 आणीर्वाद इन्डस्ट्रियल एस्टेंट जिल्डिंग 3, राम मन्दिर रोड,गोरेगांव (पण्चिम), बम्बर्ड-4

7. मैसर्स निष्पन कायजी कयोकाई, 105 मेकर चैम्बर्स-5 नारीमन प्याइट बम्बई-21

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त नियम की धारा । की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त मिक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35018(10)/86-एस. एस-2]

#### New Delhi, the 22nd January, 1987

- S.O. 345.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
  - M/s. Bonafide Exporters. Patwa Chambers, opposite Masjid Station, Dana Bunder, Bombay-9.
  - M's Model High School, Kasturba Nagar, Vasi-Naka, Bombay-74.
  - M/s. Khadigram Co-operative Canteen Limited, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Bombay-56.
  - M/s. The Paper Reels Company, B-14, Royal Industrial Estate, 1st Floor Naigaum Cross Road, Wadala, Bombay-31.
  - Mls. Central Investigation and Security Services Private Limited, 160, D. N. Road, 1st Floor, Fort, Bombay-1.
  - 6 M/s P. G. Electronics, 217, Ashirwad Industrial Estate, Building-3 Rum Mandir Road, Goregaon (West), Bombay-4.
  - M/s. Ninpon Kaiji Kyokai. 105, Maker Chambers National Highway, G. T. Road, Kundli. District

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Goretnment hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35018(10)/86-SS-III

का. आ. 3 16.— बेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निस्तलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध संबंधित स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं:—

- 1. मैंसर्स सुप्रीम एनेमल, 12/4 मथुरा रोड, फरीवाबाद
- 2. मैसमं सीफाम औरगनिक्स लिमिटिड, 17 माइल स्टोन, नेशनल हाईवे जी. टी. रोड, कुंडली, जिला मोनीपन और इसका एम-134 द्वितीय खंड कैनाट सर्कम, नई दिल्ली स्थित मन्थ कार्यालय
- 3. मैसर्स पोलीइंक प्राइवेट लिमिटिङ, 14/3 मथुरा रोङ, फरीदाबाद और इसका आर-7ए ग्रीन पार्क, नई दिल्ली स्थित रिजस्टर्ड कार्यालय
- अ. मैश्सर्म धारुहर्ष कैमिकत्म, प्लाट नं. 3-4 धारुहेरा इंदिस्ट्रियल एस्टेट धारुहेरा (महेन्द्रगढ़) और इसका मुख्य 53 नेहरू प्लेग शहयोग भवन, नई दिल्ली-19 स्थित कार्यालय

- 5. मैसर्स सामनता प्राध्यट लिमिर्गटड, 11/7 मथुरा रोड, फरीदाबाद और इसका एन-146 पंचशील पार्क, नई दिल्ली स्थित रिजस्टर्ड कार्यालय
- 6. मैसर्स ह्रिशाणा पैट्रो कैमिकत्स लिमिटिड, 55-59 हुड़ा इंडस्ट्रियल एरिशा, दिल्ली-रिवाड़ी रेड, रिवाड़ी-1 और इसका हैं101-102 सूर्य मेनशन,1, कंशिल्या पार्क,हौज खास, नई दिल्ली-16 स्थित मुख्य कार्यालय

अतः केन्द्रीय सरकार उनत नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए उन्त अधिनिशम के उपबंध उन्त स्थापनों को लागू करती है। [एस-35019(187)/86-एस पस-2]

- S.O. 346.—Whereas it apepars to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
  - . 1. M/s. Supreme Enamels. 12/4, Mathura Road, Faridabad.
  - M/s. Cepham Organics Limited, 17th Milestone National Highway, G. T. Road, Kundli District Sonepat, including its Head Office at M-124, 2nd Floor, Connaught Circus, New Delhi.
  - M/\* Polyink Private Limited, 14/3. Mathura Road, Faridabad, including its Registered Office at R-7A Green Park, New Dolhi.
  - 4. M/s. Dharuhera Chemicals Plot No. 3-4 Dharuhera In Testrial Estate Dharuhera (Mahendergarh), including its Head Office at 58, Nehru Place, Sahyog Building, New Delhi-19.
  - M's Simanta Private Limited, 11/7, Mathura Road, Faridabad, including its Registered Office at N-146, Panchsheel Park, New Delhi.
  - M/s. Haryana Petro-Chemiculs Limited. 55—59
     Huda Industrial Area, Delhi Rowari Road, Rewari-1, including its Head Office at 101-102 Surya Mansion,
     Kaushalaya Park, Hauz Khas, New Delhi-16.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act. the Contral Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

IS. 35019(187)/86-SS-III

का. आ. 347: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मजारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी मिविष्य गिधि और प्रकीर्ण उपबंध अिनियमः 1952 (1952 का 19) के उपबंध संबंधित स्थापन की लागू किए जाने साहिएं:—

- मैसर्म भारत सर्विम स्टेशन, जी.टी, करनाल रोड, देहली करनाल बोर्डर, दिल्ली--40
- 2. मैंसर्स एमेंटिय अथार्टी आफ इंडिया, जवाहरखाल नेहरू स्टेडियम, लोडी रोड, नई दिल्ली
- अ. मैंसर्ग दी इंडियन मोलाइटी आफ इन्टरनेणनल लॉ, 7-8 भिल्थिया हाउभ, कस्तूरवा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1

- मैंगर्ग पारय अंगनी, 33 डिप्टोगंज, विल्ली--6 और इसकी सी-144 मायापुरी फेज-2, नई दिल्ली-64 स्थित फैक्ट्री।
- 5. मसर्स इन्डो गाल्फ फर्टील।इजर्स एंड कैमिकल्स कारपारेणन लिमिटेड, तृतीय मंजिल होटल सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल, बसंत बिहार, नई दिल्ली—57 और इसकी लखनऊ (यू. पी.) स्थित शाखा।
- 6. मैसर्स बारबर शोप ओबेराय इन्टर कान्टीनेन्टल, डाक्टर जाकिर हुसैन रोड, नई दिल्ली-3 और इसकी श्राच होटल ओबेराय सरोतन, 15 ए, नारिमन प्याइंट, बम्बई स्थित शाखा:

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019(188)/86-एस.एस-2]

- S.O. 347.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
  - M/s. Bharat Service Station, G. T. Karnal Road. Delhi Karnal Border, Delhi-40.
  - M/s. Sports Authority of India, Jawahar Lal Nehru Stadium, Lodi Road, New Delhi.
  - M/s. The Indian Society of International Law, 7-8 Scindia houst, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-1
  - M|s. Paras Company, 33, Deputy Gani, Delhi-6 Including its Factory at C-144, Maya Puri, Phase-11. New Delhi-64.
  - M/s. Indo Gulf Fertilisers and Chemicals Corpotation Limited, 3rd Floor Hotel Siddharth Continental, Vasant Vihar, New Delhi-57, including its Registered Office at Lucknow (U.P.)
  - M/s. Barbar Shop Oberoi Inter Continental, Dr. Zakir Hussain Road. New Delhi-3, including its branch at Hotel Oberoi Sheraton-15-A Nariman Point, Bombay.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S, 35019(188)/86-SS-II]

का. श्रा. 348—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन की लागू किये जाने चाहिएं:——

- मैसर्म इलेक्ट्रो प्रोटेक्शन सर्विस नं. 59ए, कोटाए-युर रोड, कराएकुदी-2
- मैनर्स थिलागाम ब्राफसैंट प्रिन्टर्स 9/4नी, पी. के. एस. ए. ब्रस्टम्गा नादर रोड, शिवकाशी

3. मैंगर्ग भार०बी० फाउंडरी, सी-12 एण्ड 13 प्राईबेट इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, कोयम्बतूर-21

- 4. मैंसमं कन्ता कलर 97, एन ग्रार के ग्रार स्ट्रीट, शिवकाशी-123
- 5. मैं मर्न मेल्स सर्विस कम्पनी, 186 शाम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1
- 6. मैंसर्स वीटा अन्नफाल्ट्न एण्ड फैल्ट्स 62 ए (एन पी) सिडको इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, मद्राम-98 और इसकी मद्राम 101 स्थित शाखा
- 7. मैसर्स एम०बी०एन० मर्विसिज कारपोरेशन एस०बी० एन० हाडस नं. 90 सर सी. पी. रामास्वामी अथ्यर रोड, मद्रास-18
- मैंसर्स श्री कुमार प्रिन्टिंग वक्सें, 38 अन्याचल अंसारी स्ट्रीट, मेलम-1
- 9 मैंसर्स प्रायोनी फ्लूड बे(बल्र इन्डिया लिमिटिड, चतुर्थ मंजिल 109 नुगामनाकाम, हाई रोड, मद्रास-34
- 10. मैंसर्स दा मिन्तूर को-ओपरेटिय मिल्स प्रोड्यूसर्स मोसाईटी लिमिटिड, मिन्तूर वानीयामवादी नार्थ श्राकोट कस्बा-7
- 11. मैसर्स श्री वानागामुदई ब्रिक्स वर्क्स संगामंगलम, मनामादुरई-13
- 12. मैसर्स वैंकटेशापेश्वल फाइनांस्मिम कोरपोरेशन, 90 (नया नं. 207) डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद रोड, टाटाबाद कोथम्बतूर-12
- 13. मैसर्स इन्स्न्टूमेंट्स एण्ड मशीन श्राई०एन०सी० 3 श्रव्मुग्गा निकट स्ट्रीट श्रन्ता रोड, मद्रास-2
- 14 मैंसर्स पत्तचीराजा टेक्स पो. बा. नं. 131, -191 सेलम भेन रोड, कोमरापालायाम-183
- 15. मैसर्स एयर फिग सर्विसेज, 167 पिटर्न रोड, मद्रास-14
- 16. मैंसर्स फार्मम् एण्ड गियमं एल-3 इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, गिन्डी, मद्रास-32
- 17. मैं सर्स राजेण इन्डस्ट्रीज ऑल्ड नं. 4/5 इनाया मुदाली स्ट्रीट नया नं. 97 कोरुक्पेट, मद्रास-21
- 18. मैंसर्स पेन्को (इन्डिया लिमिटिड) 102 वेलाचेरी। राड, गिडी, मद्रास-32
- 19. मैंनर्स लक्ष्मी सिल्क हाउस (मद्रास) एण्ड कम्पनी 10 प्रथम मंजिल नागेश्वरा राव राँड, मद्रास-17
- 20. मैसर्स सथानूर डैम गवर्नमैंट इस्पलाईज को-ओपरेटिव स्टोर्स लिमिटिड, एच. एच. 372 सथानूर एन०ए० कस्वा
- 21. मैंसर्स सुभ् लक्ष्मी विविध फैक्ट्री, 13वी, साउथ कालोनी पोस्ट बेंक्स तं. 171 कोमारापालायाम सेलम-183

- 22. मैसर्स रामा सिल्क फ्रीक्ट्री नं, 228 मार्किट रोड. आरनी, नार्थ अकटि कस्वा
- 23. मैसर्म मद्राम डाक लेबर बंदि इम्पलाईज का-आपरेटिव कैन्टीन लिमिटिड, राजा जी सलाए, एम डी एल वी विलंडिंग, मद्रास-1
- 24. मैसर्म प्रेस्टिश रबर्म 136 प्रकृटि रोड, नालीग्रामम मदास-93
- 25. मैसर्स एमएल्ड इन्डस्ट्रीज ग्लाट नं. 42 (एन पी) गिडी डवैल्ड प्लाट, मद्राम 97 और इसका 32, 79 स्ट्रीट 18 एवेन्यू अगोक नगर, मद्रास 83 स्थित प्रणासनिक कार्यालय
- 26. मैसर्स कलाएमनी ग्राफिक्स मशीन (प्राईवेट) लिमिटिङ, सिडका इन्डस्ट्रीयल स्टेट कुरूची कोम्बेतूर 21 और इनका अपनाकारा स्ट्रीट, कोम्बेतूर 21 स्थित कार्यालय
- 27. मैनर्न मेलम करवा लारी श्रोतर्स एसोसिएणन 29 श्रय्वासामी चेती राड सेवापेट, सेलम-2 और इसेकी मेलम मेन राड, सेलम 2 स्थित णाखा
- 28. मैंसर्न श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाईनान्स कम्पनी लिमिटिड रिजस्टर्ड कार्यालय 123 अंगप्पा निकेन स्ट्रीट,मद्रास-1 और इसका मद्रास स्थित प्रणासनिक कार्यालय तथा बंगलौर और निकन्द्राबाद स्थित णाखाएं

स्रतः केन्द्रीय सरकार अवत धारा नियम की धारा 1, व की उन धारा 4 द्वारा प्रदस्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए उकत प्रधिनियम के उपबन्ध उन्त स्थापनों की लागू करती है।

[त्म 35019 (190)/86 एम. एम-2]

S.O. 348.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:

- M/s. Electro Protection Services, No. 59A, Kattaiyur Road, Karaikudi-2.
- M/s. Thilagam Offset Printers, 9/4-B. P.K.S.A. Arumuga Nadar Road, Sivakasi.
- M/s. R. V. Foundry, C-12 and 13 Private Industrial Fstate, Coimbatore-21.
- M/s, Kanna Colours, 97, N.R.K.R. Street, Sivakasi-123.
- 5. M/s. Sales Service Company, 186, Thambu Chetty Street, Madras-1.
- M/s. Beeta Asphalts and Falts, 62-A (N.P.) Sidco Industrial Estate Madras-98 including its branch at Madras-101.
- M/s. S. V. N. Services Corporation. SVN House, No. 90, Sir C. P. Ramaswamy Iyer Road, Madras-18.
- M/s. Sree Kumar Printing Works, 38, Arunachala Asari Street, Salem-1.
- M/s. Igniffuid Boilers India Limited, 4th Floor, 109, Nungambakkam High Road, Madras-34.
- M/s. The Minoor Co-operative Milk Producers Societies Limited, Minnoor Vaniyambadi TK. North Arcot District-7.

- M/s, Sree Vanagamudi Bricks Works, Sangamangaiam, Manamadurai-13.
- M/s, Sree Venkatesa Perumal Financing Corporation, 90 (New No. 207) Dr. Rajendra Prasad Road, Tatabad, Coimbatore-12.
- M/s. Instruments and Machines INC-3, Arumuga Naicken Street, Anna Road, Madras-2.
- M/s. Patchiraja Tex, P.B. No. 131, 191, Salem Main Road, Komarapalayam-183.
- M/s. Air Frig Services, 167, Peters Road, Madras-14.
- M/s. Forms and Gears, L-3, Industrial Estates, Guindy, Madras-32.
- M/s. Rajesh Industries Old No. 4/5, Ellaya Mudali St. New No. 97, Korukkupet, Madras-21.
- M/s. Pebco (India) Limited, 102, Velacherry Road, Guindy, Madras-32.
- M/s. Lakshmi Silk House (Madras) and Company 10, 1st Floor, Nageswara Rao Road, Madras-17.
- M/s, Sathanur Dam Government Employees' Cooperative Stores Limited, H.H. 372, Sathanur Dam, N.A. District.
- M/s. Subbulakshmi Weaving Factory-13-B, South Colony, Post Box No. 171, Komarapalayam, 183 Salem.
- M/s. Ramma Silk Factory, No. 228, Market, Road Arni, North Arcot District.
- M/s. Madras Dock Labour Board Employees Cooperative Canteen Limited, Rajaji Salai MDLB Building, Madras-1.
- M/s. Prestige Rubbers, 136, Arcot Road, Saligramam, Madras-93.
- M/s. Emerald Industries, Plot No. 42 (N.P.) Guindy Developed Plot, Madras-97, including its Administrative Office at 32, 79th Street, 18th Avenue, Ashoknagar, Madras-83.
- M/s. Kalaimani Graphic Machine (Private) Limited, SIDCO Industrial Estate, Kurichi, Coimbatore-21, including its Office at Oppanakara Street, Coimbatore-1
- M/s. Salem District, Lorry Owners Association, 29, Avyasamy Chetty Road, Shavapet, Salem-2, including its branch at Salem Main Road, Salem-2.
- M/s. Shriram Transport Finance Company Limited, Registered office 123 Angappa Naicken Street, Madras-1 including its administrative Office at Madras and branches at Bangalore and Secundrabad.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the abovementioned establishments.

[S. 35019(190)/86-SS-II]

- का. आ. 349—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म- चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए:—
  - मैसर्स श्रीनिवासा राव एण्ड संस काकीनाडा ई. जी. कस्वा, श्रान्ध्र प्रदेश
  - मैसर्स श्री रधुराम माडर्न राईम मिल्ल फोर्ट रोड, बारगल

- मैमर्स पी. वेंकट राव एण्ड सन्स, गजुलाजिकि, विधाखापट्टनम
- 4. मैसर्स आदर्श एजेल्मी 7-1-26 /1 /1 भ्रमीरपट्ट, हैदराबाद
- मैसर्स कोस्टल रचड इन्डस्ट्रीज, 6/1, पटामाटा, विजयवाडा—6
- 6. मैंसर्स संगम इन्जिनियरिंग टीम, 49-55-1ए, विद्युत नगर, विशाखापट्टनम-24
- 7. मैनर्स चिपिंग एण्ड पेंटिंग वर्कर्स सोसाईटी, डा॰ नं. 151, गांधीग्राम विशाखापट्टनम
- 8. मैसर्स विजया इन्जिनियरिंग कारपोरेशन, 47, डाक्टर कालोनी, विशाखापट्टनम-13
- मैसर्स प्रसाद स्टील फैब्रीकेणन एन. एच-5 लंकाला-पालम, विशाखापट्टनम-21
- 10. मैंसर्स श्री सरवाराया मुगर कोओपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, नं. डी-1290, चेलरू, ई. जी. कस्बा
- े 1 1. मैसर्स बाला रामा कृष्णा दृन्जिनियरिंग कन्स्ट्रकशन कारपोरेशन 47-11-22, द्वारिका नगर, विषाखापट्टनम--16

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करने हुए उक्त श्रिधनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019 (191)/86 एम. एस-2]

- S.O. 349.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), shiuld be made applicable to their respective establishments namely:—
  - M/s. B. Srinivasa Rao and Sons ,Kakinada, E.G. Dt., A.P.
  - M/s. Sri Raghuram Modern Rice Mill, Fort Road, Warangal.
  - M/s. P. Vankat Rao and Sons, Gajulaveedhi, Visakhapatnam.
  - Ms. Adarsh Agencies, 7-1-26/1/1, Amcerpat, Hyderabad.
  - M/s. Coastal Rubber Industries, 6/1, Patamata, Vijayawada,
  - M/s. Sangam Engineering Team. 49-55-1A, Vidyut Nagar, Visakapatnam-24.
  - M/s. Chipping and Painting Workers Society, D. No. 151, Gandhigram, Visakhapatnam.
  - 8. M/s. Vijaya Engineering Corporation, 48. Doctor's Colony, Visakhapatnam-13.
  - M/s. Prasad Steel Fabrications, N.H. 5 Lankelpalans, Visakhapatnam-21.
  - 10, M/s. Sri Servaraya Sugar Co-operative Stores, Limited, No. D-1290, Chelluru E.G. District.
  - M/s. Bala Rama Krishna Engineering Construction Corporation, 47-11-22, Dwarakanagar, Visakhapatnam-16.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35019(191)/86-SS-II]

का. आ. 350.— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली फरवरी, 1987 को उस नारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त प्रधिनियम के प्रध्याय 4 (धारा 44 ओर 45 के सिवाय जो पहले ही प्रधृत की जा चुकी है) और प्रध्याय 5 और 7 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रयृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रयृत्त होंगे, प्रथात्:—

''ग्राम सरमा हदबस्त नं. 2 और ग्रान फुनपुरा हदबस्त नं. 3 तहसील और जिला भिवानी ।''

[संख्या एस-38013/1/87-एस एस-1]

S.O. 350.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st February, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section, 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely:—

"Village Sarsa Had Bast No. 2 and Village Phool Pura Had Bast No. 3 Tehsil and District Bhiwani."

[No. S-38013]1[87-SS-I]

का. ग्रा. 351.—कर्मचारी राज्य बीमा ग्रिक्षिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त गिर्मियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 फरवरी, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त ग्रिक्षिनियम के ग्रध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और ग्रध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्तिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, ग्रथात :—

 क्षेत्र-ग्राम	 होबली	· · · · नालुक	जिला
_ :_ :	 यशवन्तपुरा	बंगलीर उत्तर	बंगलीर
2. नल्लकदरनहाल्ली	यणवन्तपुरा	बंगलौर उत्तर	बंगलीर
3. चौक्कसन्द्रा	यशवन्तपुरा	वंगलीर उत्तर	बंगर्लीर
4. दसराहल्ली (टी.	यणवन्तपुरा	बंगलीर उत्तर	वंगलीर
ृँदसराहल्ली ) 🛱			

[संख्या एस-३८०13/3/87-एस .एस-1]

S.O. 351.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State ' Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st February, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely:

Area village	Hobli	Taluk	District
I. Laggere	Yeshwanipura	Bangalore North	Bangalore
2. Nallakada rana ha	lli Yeshwantpura	Bangalore North	Bangalore
3. Chokkasandra	Yeshwantpura	Bangalore North	Bangalore
4. Dasarahally (T. Dasarahally)	Yoshwantpura	Bangalore North	Bangalore

[No. S-38013/3/87-SS-1]

का प्रा. 352.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्निलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म-चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लाग किए जाने चाहिए :---

- 1. मैंसर्स सीटीजन रबड़ एण्ड प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, न्यू टांगरा रोड, कलकत्ता-46
- 2. मैसर्स रिजनल डायरेक्टर फुड एम्पलाईज को-ओपरेटिय कैन्टीन लिमिटिङ, मौगोलेन कलकत्ता-1
- मैंसर्स 'ए' टाइप टीफिन रूम इलक्ट्रोनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोग माला (पूर्व), इलैक्ट्रोनिक विभाग पी-1 तारा तोला रोड (प्रथम तल) कलकत्ता-88
- 4. मैसर्स आई०ए०एस० ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, 10, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-9
- 5. मैसर्स नार्दन कार्गो सर्विस, 20,बी०टी० रोड, कलकत्ता-2 और इसका 81, नीलगंज रोड, धगरपारा, 24-परगना स्थित गोदाम
- मैसर्स घुष्पर सेल्ज ओरगनाइजेशन (इंडिया) प्राईबेट लिमिटिङ, 56/1, विपलावी रास बिहारी कोस रोड (कैंनिंग स्ट्रीट), कलकत्ता-1 और इसकी 1202, विकम टावर, 16, राजेन्द्र प्लेम, नई दिल्ली-8 स्थित शाखा
- 7. मैसर्स मिन्टस कारपोरेशन, 12 डा. बिरेश गुप्ता रोड, कलकत्ता-17 और इसका 5 क्लाइव रो कमरा नं. 20; ग्राउंड फ्लौर, कलकत्ता-1 स्थित कार्यालय
- 8. मैसर्स मल्टी केंग्रल्म प्राईबेट लिमिटिड, 63 नेताजी मुभाष चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-40 और इसका 69-ए, प्रिस बखत्यार माह रोड, कलकत्ता-33 स्थित प्रधान कार्यालय
- मैसर्स पोर्जैक्टिब कर्माणयल कम्पनी लिमिटिङ 6-ए, साकलात प्लेस, कलकत्ता-72 और इसकी कलकत्ता-13 तथा ग्रामनसोल वर्दवान स्थित दो णाखाएं
- 10. पैसर्स कामरूप मेटल कारपोरेशन, 58/3 कर्निंग स्ट्रीट (बिप्लावी रास बिहारी बोस रोड) कलकत्ता-1 और

इसका जे०एन० मुकजी रोड, धुसरी, हाबड़ा स्थित कार्यालय तथा जेल रोड, गोहादी स्थित शाखा

ग्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्त प्रधिनियम के उपबन्ध उन्त स्थापन को लागू करती है। [एस-35017(12)/86-एस.एस-2]

- S.O. 352.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—
  - 1. M/s. Citizen Rubber and Plastic Industries, 13, New Tangra Road, Calcutta-46.
  - M/s. Regional Director Food Employees' Cooperative Canteen Limited, 4, Mango Lane, Calcutta-1.
  - 3. M/s. 'A' Type Tiffin Room of Electronics Regional Test Laboratory (East), Department of Electronics Government of India, P-I, Taratoxla Road, (1st Floor) Calcutta-88.
  - 4. M/s. I.A.S. Transport Corporation 10, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.
  - 5. M/s. Northern Cargo Service, 20, B.T. Road, Calcutta-2 including its Godown at 81, Nilgunj Road, Agar-para, 24-Parganas.
  - M/s. Dhupar Sales Organisation (India), Private Ltd., 56/1, Biplabi Rash, Bihari Bose Road, (Canning Street), Calcutta-1 and its Branch at 1202, Vikram Tower, 16, Rajendra Place, New Delhi-8.
  - M/s. Mints Corporation, 12, Dr. Biresh Gupta Road, Calcutta-17 including its office at 5, Clive Row, Room No. 20, Ground Floor, Calcutta-I.
  - 8. M/s. Multicables Pvt. Ltd., 63, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta-40 including its head office at 69-A Prince Bakhtiar Shah Road, Calcutta-33.
  - 9. M/s. Positive Commercial Co. Ltd., 6-A Saklat Place, Calcutta-72 including its Branches at (i) Calcutta-13 (ii) Asansoli, Burdwan.
  - 10. M/s. Kamrup Metal Corporation 58/3, Canning Street, (Biplabi Rash Behari Bose Road), Calcutta-1 including its office at I. N. Mukherjee Road, Ghusuri Howrah and branch at Jail Road, Gauhati-1.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned extablishments.

[S. 35017(12)/86-SS-II]

# नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1987

का. अर्थ. 353 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से संबंद्ध नियं। जक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो। गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध सर्वधित स्थापन को लागु किये जाने चाहिए: —

- मैसर्स स्टर्लिंग प्लैटरस 14/1 सैक्टर-1, परवानो मोलन (पंजाब)
- मैसर्स यूनको स्टील इंडस्ट्रीज (रिजः) होणियारपुर रोड, जालंधर
- मैसर्स ब्राटोमाटिय एजूकेशनल ट्रस्ट हिमाचल प्राइमरी स्कूल, सक्टर-1 परवाना, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन (हिमाचल प्रदेश)
- मैस्सं जालंधर मोटर एजेंसी, नेहरू गार्डन रोड, जालंधर
- 5. मैससं मैक्स इंडिया लिमिटेड, ग्राम तोन्सा, तहसील बालाचूर कस्बा होणियारपुर और इसकी 603/33 बी चंडीगढ़ और 72 नेहरू प्लेस, लक्ष्मी बिल्डिंग, तृतीय मंजिल, नई बिल्ली स्थित गाखाए

श्रतः केन्द्रीय गरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदक्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रिधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019(189)/86-एस एम-2]

New Delhi, the 22nd January, 1987

S,O. 353.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely.

- 1. MJS, Sterling Platers, 14/1, Sector-1, Parwanoo, Solan (H.P.).
- M|S, Unco Steel Industries(Registered) Hoshiarpur Ruod, Jalandhar.
- 3. M[S. Automotive Educational Trust Himachal Primary School, Sector-1, Parwanoo, Tehsil and District Solan (H.P.).
- MS. Jalandhar Motor Agency, Nehru Garden Road, Jalandhar.
- M|S. Max India Limited, Village Toansa, Tehsil Ballachur Dist. Hoshiarpur, including its branches at 603|33-B Chandigarh and 72, Nehru Place. Laxmi Building, 3rd Floor, New Delhi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(189)/86-SS-II]

### नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1987

का. थ्रा. 354--केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा श्रिधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के+साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त एक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधिस्थना मं. का. आ. 4317, तारीख 29 ध्रगस्त, 1985 के कम मं मैसमं हिन्दुस्तान लेटेक्स पूजापुरा विवेदम को जं भारत सरकार का एक उपकम है, प्रधान कार्यालय के नियमित कर्मच(रियां को, उक्त ध्रधिनियम के प्रवर्तन से 1 श्रक्तूबर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है ध्रवधि के लिए छट देनी है।

उक्त छूट निम्नलिखित गर्तों के श्रधीन है, श्रर्थान् :--

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्ट्र रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिशान किए जाएंगे;
- (2) इस छूट के हांते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधि-नियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनका पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रकृत होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त भ्रविध के लिए यदि कोई भ्रभिदाय पहले ही संदत्त किए, जा चुके हैं तो वे बापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस प्रविध की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त प्रधिन्नियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त प्रविध कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रकृप में और ऐसी विशिष्टियों सिहत देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के प्रधीन उसे उक्त प्रविध की बाबत देनी थी;
- (5) निगम द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के श्रिधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई श्रन्य पदधारी.--
  - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के प्रधीन, उक्त श्रविध की बाबत दी गई किसी विवरणो की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
  - (ii) यह श्रिभिनिष्मित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा श्रिपेक्षित रजिस्टर और श्रिभिलेख उक्त श्रवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या
  - (iii) यह श्रभितिण्वित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस श्रधिसूचना के श्रधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह श्रिभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि गसं प्रवधि के दौरान, जब उक्त कार-खाने के संबंध में श्रिधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,--

- (क) प्रधान नियोजक या भ्रव्यवहित नियोजक से यह ग्रंपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह ग्रावश्यक समझे: या
- (ख) ऐसे प्रधान नियाजक या ग्रव्यवहित नियाजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या श्रन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश व रना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि यह व्यक्तियों के नियाजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियाँ और ग्रन्थ दस्त(वेजें, ऐसे निरीक्षक या भ्रन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तृत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह ग्रावश्यक समझे;
- (ग) प्रधान नियाजक या प्रव्यवहित नियोजक की, उसके ग्राभिकर्ता या सेवक की या ऐसे कसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या प्रन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या प्रन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या ग्रन्य परिसर में रखे गए किसी रिजस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/4/85-एस. एस-1]

#### स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छुट को भूतलक्षी प्रभाव देना ग्रावश्यक हो गया है क्योंकि छूट के भ्रावेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था। किंतू यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट की भूत-लक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकृल प्रभाव नही पड़ेगा।

New Delhi, the 23rd January, 1987

S.O. 354.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91 A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4317 dated the 29th August, 1985, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Head office of M/s. Hindustan Latex Ltd, Poojapura, Trivandrum, a Government of India Undertaking from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1985 up to and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :-

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- this exemption, the employees (2) Notwithstanding shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such parti-culars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
  - (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :-
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to:—
    - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
    - (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
  - (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to be-lieve to have been an employee; or
  - (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014|4|85-HI (\$\$I)]

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

का. मा. 335 - केन्द्रीय सरकार, कर्मवारी राज्य ब्रीमा भ्रिधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठिन धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारतीय खाद्य निगम के मक्का मिल प्लांट, फरीदा-बाद, एक्स-पूनिट के नियमित कर्मचारियों को उक्त भ्रिधिनियम के प्रवर्तन से पहर्ल, मार्च, 1974 से दिसंबर, 1979 के 31वें दिन तक, जिसमें यह तार्र ख भी सम्मिलित है, की भ्रवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित गर्तों के अधीन है, अर्थात्:---

- (1) पूर्वीक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रिजस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्म-चारियों के नाम और पदाभिधान दिशित किए जाएंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त श्रिध-नियम के श्रधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस श्रिधिमूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त श्रिभदायों के श्राधार पर हकदार हो जाते ;
- (3) छूट प्राप्त प्रविध के लिए यदि कोई प्रभिदाय पहले ही सदम किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगें;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस श्रवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त श्रधिनियम प्रवृत था (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त श्रवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के श्रधीन उसे उक्त श्रवधि की बाबन देनी थी;
- (5) निगम द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के श्रिधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—
  - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के श्रधीन, उक्त श्रवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या
  - (ii) यह प्रिभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा प्रपेक्षित रिजस्टर और प्रभिलेख उक्त अविध के लिए रखे गए थे या नहीं, या
  - (iii) यह म्रिनिश्चित करने के प्रयोजनो के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुविधाओं को, जो ऐसी प्रमुविधाएं है

जिनके प्रतिफलस्यरूप इस ग्राह्मसूत्रना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कार-खाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सणक्त होगा,--

- (क) प्रधान नियोजक या श्रव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी देजो वह श्रावश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या ग्रन्थवहित नियोजक के ग्रिधिभोग में के करखाने, स्थापन, कार्यालय या ग्रन्थ परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति से यह ग्रपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजधूरी के सदाय से सर्वधित ऐसी लेखाबहियों और ग्रन्थ वस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या ग्रन्थ पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसे जानकारी दे जो वह ग्रावश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या श्रव्यवहित नियोजक की, उसके श्रिभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या श्रन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उकत निरीक्षक या श्रन्य पद्धारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या ग्रन्य परिसर में रखे गए किसी रिजस्टर, लेखाबही या ग्रन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्घरण लेना।

[संख्या एस-38014/2/86-एस . एस-1] ए के भट्टाराई, श्रवर मचित्र

### स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन पक्ष देरी से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकृत्न प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 355.—In exercise of the power conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Maize Mill Plant, Faridabad, Ex-unit of the Food Corporation of India from the operation of the said Act for a period from 1st March, 1974 upto and inclusive of the 31st day of December, 1979.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :-

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of-
  - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
  - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
  - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
  - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during period when such provisions were in force relation to the said factory be empowered to
    - (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
    - (b) enter any factory, establishment, office other premises occupied by such principal immediate employer at any reasonable time and required any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
    - (c) examine the principal or immediate employer. his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

> (F. No. S-38019/2/86-\$S-I) A. K. BHATTARAI, Under Secy,

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1987

का ग्रा 356--औद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की घार। 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व झान्जरा प्रोजेक्ट मैसर्स ई.सी.लि. के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच ग्रनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार/औद्योगिक ग्रधिकरण, कलकला के पंचाट का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय मरकार को 13-1-87 को प्राप्त हम्रा था।

New Delhi, the 23rd January, 1987

S.O. 356.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, as shown in the Annexure, in the incustrial dispute between the employers in relation to the management of Jhanjra Project of M/s. Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th January, 1987.

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

#### Reference No. 57 of 1984

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Jhanira Project of Fastern Coallields Limited.

#### AND

#### Their Workmen

#### PRESENT:

Shri Justice Amitakh Dutta: Presiding Officer.

#### APPEARANCES:

On behalf of Employers: Shri N. Das, Advocate with Shri I. P. Singh, Personnel Manager.

On behalf of Workmen . Shri S. K. Acharya, Co-opted Executive Committee Member of the Union.

STATE: West Bengal.

### INDUSTRY: Coal.

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by Order No. L-19012(35)/84-D-IV(B), dated 19th December, 1984 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication, namely :-

"Whether the action of the management of Jhanjra Project of Eastern Coalfields Limited, in dismissing Shri Rampat Harijan, Security Guard from service w.e.f. 30-1-1984 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?".

2. It appears from the record that the workman concerned was a Security Guard and was charged for serious misconduct under para 17(i) clause (a) of standing orders applicable to him as theft of certain articles of the employers worth about Rs. 5850/- took place while he was on duty.

and design and the second and the se

- 3. Both parties have settled the dispute and settlement in writing signed on behalf of the parties has been filed today. The settlement is to the effect that the employer will reinstate the workman in his original job without payment of any back wages. The workman concerned will be given benefit of continuity of service for the period of his non-employment from the date of dismissal upto the date of his reinstatement and the workman will have no further claim against the emp-. loyer whatsoever in regard to the industrial dispute covered by this reference.
- 4. Considering the circumstance of the case and the necessity of maintaining industrial peace and harmony in the establishment I find that the terms of the settlement appear to be fair and reasonable and should be accepted. An Award is passed in terms of the settlement between the parties which will form part of the Award as Annexure 'A'.

Dated : Calcutta,

The 6th January, 1987.

AMITABHA DUTTA, Presiding Officer [No. I-19012/35/84-D. IV (B)] R. K. GUPTA. Desk Officer

#### ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CEN-TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT **CALCUTTA** 

Reference No. 57 of 1984.

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Jhanjia Project of F.C.L.

#### AND

Represented by Collery Mazdoor Umon (INTUC). Cinema Road, P.O. Ukhra, Distt. Burdwon (W.B.)

The employer and the workmen jointly beg to state that the Industrial Dispute which is the subject matter of the above reference pending for adjudication by the Hon'ble Tribunal has been amicably settled between the parties on the following terms without however, admitting the correctness of the allegations made against each other leading to the Present Reference.

#### **TERMS**

- 1. That it has been agreed that the concerned workman Shri Ram Pat Harijan who had been dismissed from his service w.e.f. 30-1-1984 by the employer will be reinstated in his original job without payment of any back wages.
- 2. That the workman will be given the benefit of continuity of his service for the period of this non-employment from the date of his dismissal upto the date of his reinstatement.
- 3. That the workman will have no further claim against the employer whatsoever in regard to the industrial dispute covered in this reference and the parties will bear their tespective cost of this reference. 1502 GI<sub>1</sub>86-10.

The parties, therefore, jointly pray that for maintaining Industrial prace and harmony at the establishment necessary order may kindly be pasted permitting them to settle the dispute on the aforesaid terms and to pass an award accordingly by treating this petition as a part thereof.

Dated:

Sd!-

For Workmen

G. S. CMU UNTUCA

Cinema Road, Ukhra.

RAM PAT HARIJAN, Concerned Workman.

For & on behalf of Employer General Manager, Ihanjia Project.

#### Witness :

- 1. Indradeo Prasad Suih
- 2. Durga Mohan Chatterjee
- 3. Kison Chattarjee.
- 4. Ramayan Singh.

### नई दिल्ती, 27 जनवरी, 1987

का. प्रा. 357---औद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के भ्रन्तरण मे, केन्द्रीय नरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियंक्तको और उनके कर्मकारों के बीच, फ्रन्बन्ध में निर्दिष्ट औद्यंगिरु त्रिवाद में औद्योगिक अधिकरण वंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 12 जनवरी, 1987 की प्राप्त हुए। था।

### New Delhi, the 27th January, 1987

S.O 357 -In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industral Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Coporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th January. 1987.

# BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Dated this the 2nd day of January, 1987 Central Reference No. 3 of 1982

#### PRFSENT:

Sri R. Ramakrishna, B.A., B.L., Presiding Officer. Vs.

II PARTY.

Workmen represented by The LIC Employees' Union. The Senior Divisional Bangalore Division, No. 253, 9th Main Road, Sampangiramanagar,

Manager, L.I.C. of India, Divisional Office Jeevanprakash Building, J.C. Road, Bangalore-2.

### APPEARANCES:

Bangalore-27.

For the 1 Party: Sri M. C. Narasimhan. Advocate, Bangalore,

For the 11 Party:--Sri H. Shanmukhappa, we cente, Bangalore.

#### REFERENCE

(Government Order No. L-17015(1)/81-D,IV(A) dated 27th February, 1982)

#### ORDERS on LA. No. 1

The Central Government has referred this matter for adjudication on the question that the workmen annexed to the points of dispute were eligible for appointment on regular basis and if so, whether the action of the management of L.I.C. of India in relation to Bangalore Division in not appointing the said workmen on regular basis is justified? If not to what relief the concerned workmen are entitled?

- 2. When this case has reached the stage of recording evidence the II Party have filed this application under Section 10(6) of the Industrial Dispute Act, 1947 to pass an order quashing the point of dispute in this refrenece on the ground that an identical order was referred to the National Industrial Tribunal at Bombay and the same was adjudicated on 17-4-86 by passing an award.
- 3. The grounds urged in the application, in brief, are that an industrial dispute in Reference No. NTB 1 of 1985 has been referred to the National Industrial Tribunal, Bombay on the following dispute:
  - "What should be the wages and other conditions of sevice of Badli. Temporary and part-time workmen of Life Insuance Corporation of India as well as the conditions of their absorption in the regular course."
- 4. It is further contended that in view of the pendency of the above reference before the National Industrial Tribunal this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the points of dispute in this reference, as the points of dispute are similar and as such no parallel proceeding should continue and therefore this dispute automatically gets quashed under Section 10(6) of the Act.
- 5. The I Party has filed their objections contending thereon that Section 10(6) of the Industrial Disputes Act is not a procedural provision and does not enable a party to file such an application. Hence the same is liable to be rejected. It is further contended that as admitted by the II Party in para 6 of the application, it is not the same dispute but a similar dispute. A reading of Section 10(6)(a) of the I. D. Act will make it clear that unless the very dispute referred to the National Tribunal the proceeding pending before the Industrial Tribunal cannot cease. The Industrial Tribunal has no option but to proceed to pass an award as required under Section 15 of the Act. That the dispute that has been referred to this Tribunal has not been referred to the National Tribunal and the consequences of the said adjudication, reliefs to be granted are entirely different. It is further contended that the reference in NTB 1/85 is illegal and without jurisdiction as prior notice has not been given to the parties likely to be affected and the I Party Union is not made a party before the National Tribunal.
- 6. It is further contended that the dispute referred to the National Tribunal has to be a dispute which involves any quesion of National importance of is of such a nature that industrial establishments situated in more than one state are likely to be more interested in or affected by such dispute
- 7. It is further contended that the points of dispute referred by the same Government to the two Tribunals are not one and the same. This dispute relates to the specific claim of certain workmen whose names are mentioned in the Schedule to the Order of Reference. Such names are not mentioned in the reference to the National Tribunal. Sec-ondly, the latter portion of the points of dispute in this reference refers to the non-appointment of the workmen on regular basis. In other words, the reference to this Tribonal includes the claims for reinstatement of the so-called badli workers at Bangalore office of the II Party and such a matter has no been referred to the National Tribunal. It is also impossible for the said dispute to fall within the category of dispute that alone to be referred to the National Tribunal under Section 10(1) of the Industrial Disputes Act. Such a purely local issue cannot be referred to the National

العليم المراجع ا Tribunal. This would mean that either the reference to the National Tribunar is invalid or alternatively this would mean that the order of reference concerned should be so construed as to avoid a conflict. It is further contended that the above complex issues cannot be decided without closely examined all the relevant documents, namely, the order of reference in the two cases, the pleadings of the parties and the issues framed in both the cases. Unless circumstances leading to the reference to the National Tribunal are known in detail it would not be possible to decide the application at all. Without the Central Government being made a party, this application cannot be disposed of. Hence I.A. 1 deserves to he rejected.

- 8. Now the points that arise for determination are:
  - (1) Whether the points of dispute referred for adjudi-cation to the National Industrial Tibunal are similar to the points of dispute pending before this Tribunal for adjudication?
  - (2) If the above point is held in the affirmative whether the present dipute is hit by Sec. 10(6) of the Industrial Disputes Act ?
- (3) What order?

#### 9. Findings:

Point No. 1:-Affirmative Point No. 2 :—Affirmative, Point No. 3:—As per order below:

#### 10. Findings:

Point No. 1:-When I.A. No. I was filed the reference made to the National Industrial Tribunal was pending adjudication Since the I Party has contended in their objection statement the necessity of the reference, the pleadings are required to give a finding on this application. The H Party have furnished the copies of these materials, and also the award made by the National Industrial Tribunal and published in the Gazette of India on 17-6-1986.

- 11. The points of dispute referred to this Tribunal are
  - "Whether the workman of Life Insurance Corporation of India, Bangalore Division, mentioned in the annexure were eligible for appointment on regular basis? If so, whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India in relation to Bangalore Division in not appointing the said workmen on regular basis is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"
- 12. On the basis of this point of dispute the I Party---Union have contended in their claim statement that the name of employees shown in the points of dispute that the Corporation is extracting work from these employees giving different nomenclature as coolies or part timers, watchmen in order to deprive them of the confirmation and other benefits of subordinate staff. They sought for regularising the services of all these employees as full time employees extending all the benefits that has been enjoyed by permanent employees.
- 13. The point of dispute referred to the National Industrial Tribunal is as follows:--
  - "What should be the wages and other conditions of service of Badli, temporary and part-time workmen of Life Insurance Corporation of India as well as the con-ditions of their absorption in the regular cadre?"
- 14. On a reading of the points of dispute referred to this Tribunal and to the National Industrial Tribunal the reference made to the latter is more exhaustive than the reference made to this Tribunal, as the latter reference includes the Badli and Temporary workmen.
- 15. In the counter statement filed before this Tribunal by the II Party it is contended under Section 23(1) of the Life Insurance Corporation Act, shortly called Act, the Corporation is empowered to employ such number of persons to discharge its functions. Under Section 48 of the said Act, the

Central Government may by notification make rules to carry out the purpose of the said Act. Under Section 49 of the Act, the Corporation may with the previous approval of the Central Government by notification in the Gazette of India make Regulations not inconsistent with the Act and the Rules, to provide for all matters for which provision is expedient for the purpose of giving effect to the provisions of the Act. It is further contended that since the power to make rules and regulations has been taken over by the Government of India, the Regulations and Rules in force prior to the amendment are deemed to be the rules made in the Amendment Act 1981. The Corporation has to strictly follow the rules and it cannot deviate or modify the said rules. The appointment of Class III and IV employees are made and governed by the Life insurance Corporation of India instructions of 1979. These instructions were issued by Chairman in exercise of the powers vested on him under Regulation 4 of the Staff Regulations. The recruitment and appointments are made in accordance with the instructions of the Central Government by calling for applications through Employment Exchange.

.. ..

\_\_ - \_

- 16. They have further contended that the persons whose names are mentioned in the annexure to the reference were being engaged only as easual labourers and temporary on day to day basis. The deration of engagement is also for a very short period and with break. They are not at all eligible for appointment on regular basis either under the LLC. Recruitment instructions 1979 or any other law, and they have already recruited some of the workmen shown in the points of dispute on permanent basis and part time basis.
- 17. Before the National Industrial Tribunal after the reference has been made the preamble of the order pointed out "that the dispute is in such a nature that establishment of L.I.C. situated in more than one state are likely to be interested in or affected by such dispute the reference has been made to the National Industrial Tribunal to adjudicate the dispute."
- 18. The National Industrial Tribunal after the reference has been made, has impleaded six other unions of the Cornoration, as in the reference order there were only two unions joined as parties viz., Western Zone Insurance Employees Association. Bombuy and Central Zone National Life Insurance Corporation Employees' Association, Kanpur. All these eight unions represening the workmen of the above categories have filed their claim statements in support of their demands. In the claim statement by one of the unions viz., All India Insurance Employees Association Calcutta. The case of badli, temporary and part time workmen was dealt with exhaustively from para 22 to para 44.
- 19. The Corporation in their written statement before the National Industrial Tribunal has taken up the same contentions similar to the contentions taken in this dispute and also absorption of temporary employees on a permanent basis as and when the vacancies are occurred or sanctioned posts were available for filling up.
- 20. On a reading of the points of dispute and the contenions urged by both parties are found to be similar in both the disputes. Hence I find no merit in the submission of the learned counsel for the union that the points of dispute referred this Tribunal and to the National Industria Tribunal are different, except to the extent that the reference made to the National Tribunal is subsequent to the reference made to this Tribunal. In view of this, the 1st joint is held in the affirmative.
- 21. Point No. 2:—The learned counsel for the Corporation has submitted that the issue now pending before his Tribunal was also a point referred to the National Tribunal and since an adjudication is made by an award which is binding on all the workmen of Corporation throughout India, the reference now pending before this Tribunal is hit by Section 10(6) of the Industrial Disputes and the reference is liable to be quashed. The learned counsel further submitted that in view of the award made by the National Tribunal the local L.I.C. taken the sign to absorb and regularise the eligible caudidates and any independent award by this Tribunal will likely affect and prejudice the interest of the workmen who are eligible

or regularisation at present. The learned counsel further submitted that if a finding is given different to that of a finding already given by the National Industrial Tribunal, the said finding is likely to distupt and dishormony the structure of the Corporation which is being done on all India level basis. Against this submission, the learned counsel for the I Party tation submitted that it it is the contention of Government of India to treat that the reference made to the National Industrial Tribunal cover the points of dispute pending before this Tribunal they should have sent a copy of the reference and a notice to this Tribunal and even in the written statement filed by the Corporation before the National Industrial Tribunal this fact is not disclosed, hence section 10 (6) has no application to the present reference.

. --\_. -. -

- 2 On a perusal of the award made by the National Industrial Tribunal, Bombay, the learned Presiding Officer has givent a broad out-line of the dispute that requires adjudication in para 3 of the award as follows:—
  - "It would be convient to divide this dispute into two parts, one relating to wages and other conditions of service and the other with regard to their absorption in regular cadre. It is also necessary, in order to define to describe what are the kinds of employees covered in the employment, which occurs in their case who are generally described in the reference as baddi, temporary and part-time workmen. Admittedly, these categories of employees belong to class-III and cass-IV. Even in between then it is common ground that there are no class-III employees in the part-ime group of category of employees, who are covered in this reference. There are also no baddi employees from Class-III. In other-words, therefore, of the three kinds of employees covered by this reference, class-III employees only belong to temporary category while the class-IV category employees belong to all the three groups, namely, haddi, temporary and part-time".
- 23. Section 10 (6) of the Industrial Disputes Act reads as follows:—
  - "Where any reference has been made under sub-section (IA) to national Tribunal, then notwithstanding anything contained in this Act, no Labour Court or Tribunal shalf have jurisdiction to adjudicate upon any matter which is under adjudication before the National Tribunal, and accordingly:
  - (a) If the matter under adjudication before the National Tribunal is pending in a proceeding before a Labour Court or the Tribunal, as the case the Labour Court or the Tribunal, as the case may be, in so ar as it relates to such matter, shall be deemed to have been quashed on such reference to the National Tribunal; and
  - (b) It shall not be lawful for the appropriate Government to refer the matter under adjudication before the National Tribuna; to any I abour Court or Tribunal for adjudication during the pendency of the proceeding in relation to such matter before the National Tribunal."
  - "Explanation.—In this sub-section, Labour Court. or Tribunal includes any Court or Tribunal or other authority constituted under any law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in any State".
- 24. On a plain reading of Section 10 (6) it has been devised for avoiding multiplicity of proceedings which may result from such a reference. The effect of non-obstatute clause is that irrespective of the other provisions in the Act, it is the National Tribunal alone which will be seized of the matter referred to it after a reference under sub-section (IA), to the complete exclusion of adjudication by other adjudicatory authorities either under this Act or under any State statute, the combined effect of the provisions (2) and (b) under Section 10 (6) is not merely to impose a prohibition against proceeding with the enquiry before the Tribunal, but there

or and the second control of the con

is a obligation cast on the Tribunal to treat, the proceedings which would include the reference itself, as void as having been quashed by the reference to the National Tribunal.

- 25. This Tribunal after perusing the award made by the National Tribunal is satisfied that the points of dispute made before this Imbunal is already adjudicated exhaustively by the National Tribunal, the reference stands quashed and further adjudication is found unnecessary. Hence I hold this point also in the affirmative.
- 26. Point No. 3:—In the result, the reference made to this Tribunal fails and the same is hereby rejected without expressing any opinion on the merit of this reference.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by mo),

> R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer [No L-17015]1[81-D IV (A)]

> K. I. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई पिल्ली, 29 जनक्री, 1987

ता.आ. ३५८ ---अंदोर्तगक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रारं 17 के अन्तरण में, कर्न्याय नारकार, डीविभनर रेन्छे मैसेजर बैस्टर्न रेलबे, बीटा के प्रबंबतंत्र से शम्बद्ध सियोजको और उनके धर्मकारो के बीच. अनवन्य में निर्दिएं ओक्षोगित विवाद में केन्द्रीय सरकार आंद्योगिक मधिकरण, नई दिल्ली के पंचार की प्रकाणित करतो है, जो केन्द्रीय भएकाए का 13 जनवनी, 1987 की प्राप्त हथा था।

New Delhi, the 29th January, 1987

S.O. 358 —In pursuance of section 17 of the Industrial Dispputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of D.R.M. Western Railway, Kota, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-1-87.

#### BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

LD. No. 75/78

In the matter of dispute between ;

Shri Inder Parkash and Others through Divisional Secre tary, Paschim Railwayl Karamehari Parishad, in front of Hasthal, Bhimganj Mandi, Kola-2 (Raj)

#### Versus

- 1. Divisional Railway Manager, Western Railway, Kota,
  - 2. The General Manager, Western Railway, Churchgate, Bombay.

#### APPEARANCES:

Shri A. D. Grover—for workmen

Shii V. P. Mishra- for the Management,

#### AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. 1.41011(9)/77-D.II(B) dated 17th Aurist, 1978 has referred the following indistrial dispute to this Tribupal for adjudication :

Whether the action of Divisional Superintendent. Wesfern Railway, Kota in treating the Bungalow

Peone in separate cadre and thereby retrenching the senior Hemals whose names are mentioned below vide notice dated the 21st April, 1977, is justified? If not, to what relief are these Hamals entitled?

#### Names of Hamals

- (1) Shri Inder Prakash.
- (2) Shri Baboo M.
- (3) Shri Chotey Lal.
- (4) Shri Ashok Kumar M.
- (5) Shri Ganpat H.
- (6) Shri Narain Singh,
- (7) Shri Prakash.
- II. Whether the action of the Divisional Personnel Officer Western Railway, Kota in terminating the services of the undermentioned casual workmen under the Inspector of Works (W&D), Western Railway, Kota with effect from the 23rd April, 1977 is justified? It not, to what relief are these workmen entitled?

Names of the Casual workmen

- (1) Shri Hardeo Singh, son of Shri Kanahiya I al.
- (2) Shii Roop Shigh, son of Shri Sarkara Phai.
- (3) Shri Ramdeo, son of Shri Mangilal.
- (4) Shri Amarlal, son of Shri Daulat Ram,
- (5) Shri Satyanarain, son of Shri Damodar.
- (6) Shri Ravilal, son of Shri Kanahiya Lal.
- (7) Shri Brij Kishor, son of Shri Surajnatain.
- (8) Shii Kamlesh Chandra, son of Shri Suraj Prasad.
- III Whether the action of the Divisional Superintendent, Western Railway, Kota in not paying wages at higher rates to the undermentioned employees after completion of 6 months service under the Permanent Way Inspector, Bharatpur is justifled? If not, to what relief are they entitled?

Names of the employees

- (1) Shri Shyamlal S.
- (2) Shri Soni.
- (3) Shri Sadar Khunni.
- (4) Shri Bhagwan Singh M.
- (5) Shri Amar Singh M.
- (6) Shri Paras Ram R.
- (7) Shri Gyasi S.
- (8) Shri Sukhchandi L.
- (9) Shri Kirori K.
- (10) Shri Ram Lal D.
- (11) Shri Nathi Permoli."
- 2. The case of the workmen as setforth in the statement of claim schedule-wise is as under :

#### Schedule No. 1

The applicants were working as substitute Hamals in the office of the Divisional Superintendent, Western Railway Kota and they were served with retrenchment notice dated 21-4-77 mentioning the reason that their services were no more required because of the less absentees of Class IV .staff. However, the reasons given for retrenchment were absorbately incorrect as juniors to the claimants viz. SiShri Ismaial s'o Abdul. Abdul Hamid sjo Ibrahim, Balco II and Dol Chand were continued in service. No seniority list was displayed nor the principle of last come first go was followed and thus there has been violation of Rules 76 and 77 of the I.D. Act Central Rules 1957 and Section 25-H of i. Li li linguations til li liliant transconsi li li li li linguation della linguation della completa della compa the LD. Act. Hence the termination of the services of the not paid the retrenchment compensation at the time of their retrenchment and thus there is violation of Section 25-F of the I.D. Act. Hence the termination of the services of the claimants is illegal and liable to be set aside.

#### Schedule No. II

The workmen listed in this schedule were working under I.O.W. (W&D) Western Railway, Kota. It is alleged that artificial breaks were made in their service to deprive them of their legitimate rights of becoming Railway Servants. These workmen were retrenched w.e.t. 23-4-77 and re-engaged on 29-4-77. No notice was served nor any notice-pay in lieu of notice and retrenchment compensation was paid. Hence retrenchment of these workmen is filegal and liable to be set aside.

#### Schedule III

It is stated that the workmen have worked as casual gangmen under PWI Bharatpur for the period shown against., each of them as under :

(1) Shri Shyam Lal S. Gang No. 112	1960 to 1969
(2) Shri Soni Gang No. 112	1963 to 1968
(3) Shri Sardar Kaluram Gang No. 112	1963 to 1968
(4) Shri Bhagwan Singh M.	
Gaug No. 112-B	1961 to 1968
(5) Shri Amar Singh M 112	1962 to 1968
(6) Puraram R 112	1963 to 1968
(7) Shri Gyasi I 112-B	1963 to 1969
(8) Shri Sukhehandi I 112	1963 to 1971
(9) Shri Kirori K. 112-A	1963 to 1969
(10) Shri Ram Lal D. 112	1963 to 1973
(11) Slui Nathi Parmoli 112	1963 to 1967

As per the Extant Rules they ought to have been paid authorised scale of pay after completion of six months service but they have not been so paid and hence it was prayed that the Management be directed to make payment as pper authorised scale together with the arrears.

3. The reply of the Management Schedule-wise is as under:

#### Schedule No. I

It is admitted that the claimants had been working as Hamais in the Office of the Divisional Superintendent, Western Railway. Kota and that they were served with retrenchment notice but it was denied that junior, were retained in service and the principle of last come first go was not followed. It was also denied that the termination of services of these claimants is illegal and the claimants were called upon to specify the names and designations of the employees who were alleged to have been retained in service although they were junior to the applicants.

#### Schedule No. II

The notice of termination of the workmen-claimants was revoked and the period from 23-4-77 to 29-4-77 was treated on duty and the claimants have been paid their wages and at present the applicants are working as casual labour in authorised scale.

#### Schedule No. III

The Railway Administration had never denied to pay the required sufficient time and the arrears will be paid us per rules.

- 4. The workmen in their rejoinders furnished the names of the junious who were retained in service as under -
  - 1. Shri Ismail S/o Shri Abdul working as peon in Control Office Divisional Suptd. Western Railway Office, Kota-2.

- 2 Shri Abdur Hanii Sjo Ibrahim working as a Khalasi in C&W Depot, Western Railway, Kota.
- 3. Sini Baloo H. working as bunglow Peon in APO's house.
- 4. Shri Dal Chand working as Pcon of Divisional Mechanical Engineer (C&W), Kota,
- 5. My findings schedule-wise are as under :

#### Schedule No. I.

The workmen in their statement of claims itself had mentioned the names of four junior employees who were retained in service and, therefore, the contention, of the management in the written statement, that the workmen should specify the names and designations of the employees who were retained in service though they were juniors is quite illogical. In any case the workmen have provided further detailed particulars of these workmen mentioning the place of their employment in the rejoinder filed by them and which have been reproduced above. However, all that the Management had to say through Shri K. P. Saxena Chief Clerk in the Office of the DRM Kota is that the names of person given in the rejoinder are not relevant to this case as one out of those 4 i.e. Baloo-H was utilised as Bungfow Peon and the rest three were not employed in the Unit where the claimants were employed. This averment of Shri K. P. Saxena appears to be incorrect on the face of it because it has been mentioned in the rejoinder that Shri Ismail s/o Abdul was working as Peon in the office under the Control of Divisional Superintendent, Western Railway. Kota and the contention of the workmenclaimants in their statement of claim is also that they were working in the office of the Divisional Superintendent West-ern Railway Kota. Hence it is quite inexplicable as to how the Management can say that the three persons other than Baloo H mentioned in the rejoinder were not employed in the same Unit as the claimants. Now Shri K. P. Saxena in his cross-examination when he appeared in court first stated that the seniority of casual employees for retrenchment is unitwise and not division-wise. Later be stated that the entire class IV staff of Divisional Office is one cadre. He further stated that Hamals, Bunglow Peons and other Peons are all in one cadre. If the entire class IV staff of the Divisional Office constitute one cadre and the Hanadas, Bunglow Peon and other peons are all in one cadie, the four workmen mentioned in the statement of claim as well as the rejoinder would therefore be in the same cadre as the claimants. As the Control Office of the Divisional Superintendent C&W Depot Divisional Mechanical Engineer C&W, all fall within the Kota Division of the Western Railway, this statement of Shri K. P. Saxena MWI virtually admits the claim of the worken and negates the stand of the Management taken before the appropriate government which necessitating the reference of this dispute. As all the class IV staff include Hansals, Bunglow Peons and other peons admittedly constitute one cadre, there was no justification for the Management to treat the Bungiow Peons separately from the Hamals and other peons and thereby to have retained in service junior employees and retrenched the claimants who were senior to them. There is a clear violation of the principle of last come first go in the case of these workmen and hence action of the Management cannot be justified. The J.d. representative for the Management has tried to draw some succour from the letter dated 5-12-68 addressed by the Head Quarters office of the Western Railway to the Divisional Superintendent in which some instructions regarding appointment of Bunglow Peons were issued. However, even this letter makes it clear that the appointment of bungalow peons is normally made from the peons working in the office but if the concerned officer does not like to appoint an office peon as his bunglow poon, he can select a candidate of his own choice, only if there are vacancies and the officer concerned would exercise this option only once so as to avoid this being a method of hiemilar recruitment to class IV posts. It is therefore, clear that this letter gives some relaxation in the procedure for recruitment but it does not say anything about the retrenchment of class IV employees. In other words an officer entitled to Bungalow Peon can select a person other

than peons working in the office only if there are vacancies, which would mean that the person so selected would be placed junior to the persons already working as office peons and in case of retrenchment he will have to go by principle of last come first go, if there is no vacancy. Hence the action of the Management is not at all justified. Therefore, the claimants are entitled to reinstatement with continuity of service and with back wages subject to the availability of vancancies available on the date of termination as per the common seniority of the class IV employees of the Kota Division of the Western Railway including Hamals and Bunglow Peons.

#### Schedule No. 11

All the workmen have since been reinstated and the period between the termination and reinstalement treated as on duty, and they have been paid their wages for this period. Hence these claimants have got no further grievance.

#### Schedule No. III

The Management has conceded that on completion of six months service the workmen are entitled to the authorised scale of pay. However, the reasons given for non-payment viz, the work being voluminous and required time, is not sufficient justification for the inordinate delay in making the payment. It is therefore, directed that the Management should make the payment of the arrears within one months of the date of enforcement of the award alongwith 12 percent interest w.e.f. 17-8-78 when the reference was made by the Appropriate Government.

6. This reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

18th December, 1986.

G. S. KALRA, Presiding Officer INo. L-41011/9/77-D.II(B)(Pt.) HARI SINGH, Desk Officer

# नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1987

का आ , 359 :-- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुभरण में, केन्द्रीय सरकार, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक श्रधिकरण, नई दिल्ली, के पंचाट की प्रशाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-1-87 की प्राप्त हुआ था।

# New Delhi, the 29th January, 1987

S.O. 359.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal. New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Baroda House, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th January, 1987.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. NEW DELHI

### T. D. No. 31|83.

In the matter of dispute between :

Shri Bhagwan Singh, slo Shri Shiv Lal, rjo 248, Khanpur. New Delbi.

#### Versus

General Manager, Northern Railway, New Della APPFARANCES :

Shri Bhawan Singh workman in person.

Shri S. L. Nim for the Management.

#### AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. 1,-41012(10)[80-D, II(B) dated 15-3-82 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

- "Whether the management of Northern Railway, Baroda House, New Delhi is justified in terminating employment of Shri Bhagwan Singh, Khalasi beyond 14th October, 1978. It not, to what relief the workman is entitled ?"
- 2. The workman is his statement of claim has stated that he joined the service of the respondent as casual khalasi w.e.t. 28-5-76 and he had completed more than 870 days of work without any break and in view of his long spell of service he got the status of permananet worker. A test was conducted by the Management for absorption of Khalasis on permanent basis and he qualified in that test but was nover made permanent whereas the other workmen who were junior to the orkman were made permanent. The Management terminated the service of the workman without assigning any reason which action was illegal and contrary to the provisions of law and principles of Natural Justice. His termination amounted to retrenehment but no retren chment compensation was paid hence there is violation of section 25 of the I. D. Act. Hence the workman has prayed that he may be reinstated in service with continuity of service and full back wages.
- 3. The Management in its written statement pleaded that the claimant was an unwilling worker and had been served with letter asking his explanation for misbehaviour and disobedience to carry out instructions to perform duty but instead of submitting any reply he left the employment and never returned thereafter to report for work. was denied that the applicant had acquired permanent status before he deserted his service. It was further stated that although the claimant had qualified the screening test for appointment as Khalasi his number in the list was at serial No. 190. It was denied that any junior person to him in the list was issued medical memo for absorption as Khalasi prior to the date he left the employment. The service of the claimant was as a casual worker and his services were never terminated as alleged but he himself left the work of his own accord. There has been no termination of service or retrenchment as the claimant left the work of his won accord and hence he is not enritled to the protection of section 25-F or any other relief.
- 4. The short question that arises for determination in this case is whether the services of the workman were terminated on 14-10-78 as alleged by the workman or whether it is a case of abandonment of services by the claimant as alleged by the Management, Although the record of service as casual labour Ex. WZ-1 shows the lust date of working of the claimant as 14-7-78 yet the Management has produced sufficient evidence which goes to prove that the claimant had actually performed duty upto 31-3-79. This is evidenced from the document. Ex. MZ-1 which contains the details of working days of the claimant right from 15-7-6 to 31-7-1979. It goes to show that the claimant had put in duty for 143 more days after 14-10-78. The similar position is forthcoming from the letter Ex. M-1. The similar position is forthcoming from the letter Fx. M-I dated 11-9-1981 addressed by the Divisional Personal Officer. New Delhi to the General Manager (P) Northern Railway, Baroda House, New Delhi in which it was clearly stated that the claimant-workman had left his service of his own accord and that the claimant's claim that his services were terminated w.e.f. 15-10-78 is not correct, since he was engaged subsequently as was clear from his service particulars. The reference to this Tribunal was made vide order duted 15-3-1982. Therefore, the letter Fx. M-1 which though written in connection with the industrial dispute vet was written prior to the order of reference and, therefore, is appears to be authentic. It has been reiterated by MW1 Shri Rajiv Bhatnagar also that the claimant worked into 31-3-79 and that after 31-3-79 he did not come and left of by own accord. He has further stated that on 19-3-79 an FIR was lodged against lifth for his mishebaviour with IOW. Nizamuddin and that is why he did not come after

11-3-79. The workman han not been able to produce and evidence which could go to prove that his service; were terminated on 14-10-78 or that he had not performed any duty upto 31-3-79 as alleged by the Management. It is pertinent, to mention here that the service card Ex. WZ-1 was in the custody of the workman and he was getting periods of his work authenticated from time to tame. It further appears that he did not get any entry made for the period after 14-10-78 and he has tried to take unduc advantage of the non-existence any entry of his service beyond 14-10-78 in the Service Card by alleging that his services were terminated on 14-10-78, The evidence produced by the Management goes to prove that the workman is guilty of making a false statement that his services were terminated on 14-10-78 because he is proved to have actually worked with the Management upto 31-3-79. Since the workman is proved to have been performing the duty with the respondent upto 31-3-75, the question of termination of service of the workman on 14-10-78 does not

arise. In the Circumstances, the contention of the Management that the workman himself abandoned, his service and that it was not a case of terreination appears to be correct and is accepted. Hence the workman is not entitled to any telief and this reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end,

31st December, 1986.

G. S. KALRA, Presiding Officer [No. 1-41012]10[80-D, II(B)] HARI SINGH, Desk Officer